₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

फरवरी 2019

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.-35

पहाड़ से डगमगा रहा सिंहासन

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग,

पटना-800020,

सम्पर्क संख्या :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

ई-मेल :-kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

शीघ्र अपने प्रदेश में

अपना घर

बेसहारों का बने सहारा। इसके लिए आपका अनुदान आवश्यक है।
आपका सहयोग कई जीवन को दिशा दे सकता है।
निश्चित सहयोग करें :-

केवल सच सामाजिक संस्थान

खाता संख्या (A/C No.)	-	0600010202404
बैंक (Bank Name)	-	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
आईएफएससी कोड (IFSC Code)	-	UTBIOKKB463
पैन नं. (Pan No.)	-	AAAAK9339D

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

जैकी श्रॉप
01 फरवरी 1960

मनोज तिवारी
01 फरवरी 1971

ब्रह्मनंदम
01 फरवरी 1956

खुशवंत सिंह
02 फरवरी 1915

शमीता शेट्टी
02 फरवरी 1979

रघुराम राजन
03 फरवरी 1963

उर्मिला मांदोडकर
04 फरवरी 1974

अभिषेक बच्चन
05 फरवरी 1976

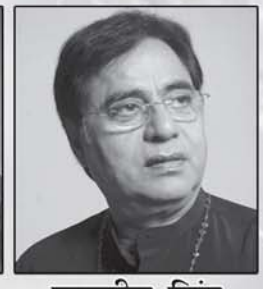

जगजीत सिंह
08 फरवरी 1941

मो० अजहरूद्दीन
08 फरवरी 1963

राहुल रॉय
09 फरवरी 1968

उदिता गोस्वामी
09 फरवरी 1984

कुमार विश्वास
10 फरवरी 1970

चौधरी अजीत सिंह
12 फरवरी 1939

सुषमा स्वराज
14 फरवरी 1952

टेकलाल महतो
15 फरवरी 1945

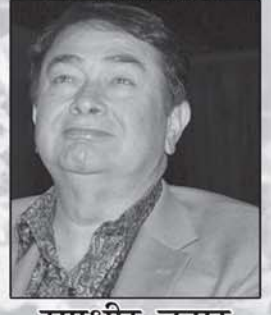

रणधीर कपूर
15 फरवरी 1947

प्रफुल्ल पटेल
17 फरवरी 1957

जयललिता जयराम
24 फरवरी 1948

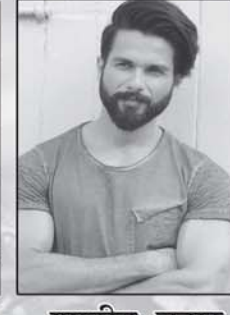

शाहीद कपूर
25 फरवरी 1981

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769, 09308727077
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Sector- 1, Block - 14, Flat No.- 501, Khelgown Houseing Colony, Ranchi - 834009 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, 97A, DDA Flat, Gulabi bagh, New Delhi- 110007
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

देश के हर दल में प्रधानमंत्री

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

बिगुल बच चुका है, रणभूमि सज-धज कर तैयार भी हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल की सेना भी अपने - अपने हथियार (घोषणा - पत्र) में धार देने में लगे हुए हैं जैसे महाभारत में पांडव की सेना को परास्त करने के लिए कौरव की सेना के साथ अन्य रियासत भी साथ में खड़ी थी। कुछ ऐसा ही आलम है 2019 के लोकसभा चुनावी युद्ध में, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ देश के अन्य राजनीतिक दल। लेकिन मोदी का मुकाबला करने में कांगेस के युवराज राहुल गाँधी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है जिसकी वजह से देश के अन्य राजनीतिक दल को यह खटक रहा है और इसके फलाफल है की देश के सबसे बड़े प्रदेश में एक-दूसरे के घोर विरोधी रही बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को शिकस्त देने के लिए बुआ-भतीजा का रिश्ता जुड़ गया है ताकि मोदी और राहुल दोनों को शिकस्त दिया जा सके। ममता बनर्जी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं जिसने नरेन्द्र मोदी पर राजनीतिक प्रहार किया है और मोदी भी पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं जिसकी वजह से कभी शाह तो कभी योगी और अन्य दिग्गज राजनेता पश्चिम बंगाल में हिन्दुवादी वातावरण तैयार करना चाहते हैं लेकिन ममता के माया के कारण परेशानी बढ़ती जा रही है। पीएम नरेन्द्र मोदी का नारा ''सबका साथ-सबका विकास'' का मुकाबला राफेल का मुद्दा उठाकर नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे को जनता स्वीकार नहीं करने वाली है तो बिहार के लालू के लाल पारिवारिक कलह एवं राजनीतिक ज्ञान के अभाव के कारण बड़ा कमाल करते नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जब नीतीश कुमार के विकासशील सोच के सामने सर्वमान्य शक्तिशाली मोदी आधा सीट पर चुनाव लड़ने का घोषणा करके झुक सकते हैं वैसे में तेजस्वी यादव की विसात ही क्या है। दलितों की राजनीति करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद की प्रतिष्ठा बचा लें यही गलीमत है क्योंकि धीरे-धीरे करके सभी दिग्गज राजनेता हम को गम दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरबिन्द केजरीवाल भी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं क्योंकि उनकी नजरों में उनसे बड़ा ईमानदार एवं मोदी जैसा चौकीदार चोर का नारा दूसरा कौन दे सकता है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पीएम उम्मीदवार तो कांग्रेस के युवराज ही हैं लेकिन वर्त्तमान विपक्ष भी मोदी के लिए संख्या में सीटों का जुगाड़ करने में कारगर साबित हो सकता है, वहीं महाराष्ट्र में भी शरद पवार खुद को पीएम न सही डिप्टी पीएम की लालसा में बैठे हैं तो भाजपा से छीन चुकी यशवंत एवं शत्रुघ्न सिन्हा की जमींदारी मोदी को नुकसान पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब दिख रही है। आजादी के बाद यह देखा गया है की यूपी, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में जिसकी भी संख्या सर्वाधिक हो उसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है और गत 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी की सरकार को प्रचंड बहुमत से बनाने वाला यही राज्य रहा है लेकिन 2019 आते - आते भाजपा अखिलेश यादव की यूपी सरकार छीनने में कामयाब हो गयी तो 2018 के अंत में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने भाजपा से सरकार छीनकर मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है लेकिन मोदी के मुकाबले विपक्ष में मजबूत एवं विश्वास से भरे गठबंधन का आभाव दिख रहा है। मोदी विकास के दम पर सरकार बनाने में कितना कारगर साबित होंगे यह तो वक्त बतायेगा लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण में गंदी राजनीति एवं देश के भीतर एससी/एसटी एक्ट का भारपाई 10 प्रतिशत सामान्य आरक्षण से हो पायेगा की नहीं इसपर सभी दलों में मैराथन राजनीतिक मंथन चल रहा है। फरवरी के अंत आते - आते चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो जायेगी और इसके बाद जुबानी जंग और तेज हो जायेगा तथा खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित करने वाले का चेहरा भी सार्वजनिक हो जायेगा लेकिन मोदी के सामने आज के तारिख में कोई ऐसा अन्य दल में नहीं दिखता जो सामना कर सके। पीएम मोदी को किसी अन्य दल से अधिक खतरा खुद के ही दल एवं संघ में है। भ्रष्टाचार में सिर्फ राफेल को लेकर कांग्रेस मोदी को घेर तो सकती है पर परास्त नहीं कर सकती और अन्य दल खुद ही इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नरेन्द्र मोदी को भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में नहीं फंसाया जा सकता है। जिस प्रकार मोदी पूर्वोत्तर भारत में अपनी साख जमाने का प्रयास कर रहे हैं उससे यह तो साफ होता दिख रहा है कि भाजपा का कद उन क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है जहां खाता भी नहीं खुलता था लेकिन बिहार, झारखण्ड, यूपी एमपी और छत्तीसगढ़, गुजरात एवं राजस्थान के साथ महाराष्ट्र में भी 2014 की तरह बादशाहत कायम करनी होगी अन्यथा मिशन 350 का आंकड़ा तो दूर बहुमत के 273 पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। संघ एवं भाजपा के कुछ नेता मोदी एवं शाह की तानाशाह जोड़ी से नाराज भी दिख रही है तथा नितिन गडकरी के बयान भी कुछ ऐसे ही संदेश देते दिख रहे हैं। महागठबंधन में कोई न कोई अपने ही दल से निकलकर मोदी की ताकत बढ़ा रहा है तो यह स्पष्ट दिख रहा है की मोदी का सीधा मुकाबला राहुल से ही होने वाला है और अन्य दलों के पीएम उम्मीदवार मोदी की बहुमत नहीं मिलने पर दावेदारी पेश करेंगे। राजनीति के दांव-पेंच सोशल मीडिया एवं पत्रिका-अखबारों के साथ चैनलों पर भी जोर पकड़ चुका है और राम मंदिर का मामला शांत होकर भी अपना राजनीतिक प्रभाव छोड़ने से बाज नहीं आयेगा...।

2019 के मध्य में भारत को 2019 से 2024 मध्य तक का प्रधानमंत्री नियुक्त हो जायेगा। एक तरफ वर्त्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज राहुल गाँधी तो तीसरे तरफ भारत के सभी राजनीति दल के सुप्रीम भी इस पद पर सुशोभित होने का सपना देख रहे हैं और इसको हकीकत में बदलने के लिए जानी दुश्मन से भी दोस्ती करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के महारैली में शामिल हुए विभिन्न राजनीतिक दल के नेता खुद को पीएम मोदी के विरोध में खड़ा करता दिख रहा है लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखती। एक प्रदेश से देश के अन्य प्रदेश में 2 - 4 सांसद नहीं बना पाने वाला भी गठबंधन की जुगाड़ के तहत देश में देवगौड़ा और झारखण्ड में मधु कोड़ा की तरह ताज ग्रहण करना चाहते हैं। एनडीए में शामिल जदयू के नीतीश कुमार भी पीएम की कुर्सी पर विराजमान होने के जुगत में दिखते है की चाह कभी - कभार बयानों से दिख जाती है और मुस्लिम के मुद्दे को लेकर कभी भी 2012 मध्य की तरह गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। एक तरफ मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं तो विकास के दम पर उससे अधिक न तो उतना ही सही प्राप्त करने की कोशिश में हैं तो विरोध करने वाले खुद कितनी सीट जीतकर अपनी लाज बचा पायेंगे उसकी फिराक में हैं पर पीएम मोदी को कुर्सी से बेदखल करने की हर हथकंड़ा को अपना रहे हैं। लालू यादव जेल में रहने की वजह से चाणक्य की भूमिका में नहीं दिखते, इसलिए ममता की चट्टानी एकता पर दांव लगा रहे हैं।

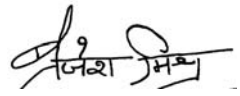

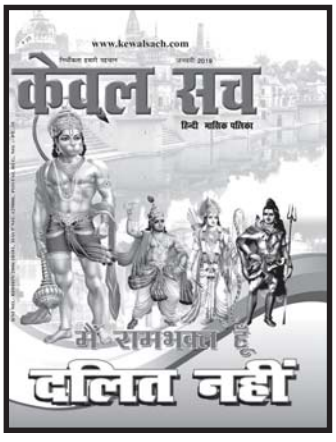

जनवरी 2019

हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769, 9955077308
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

साक्षात्कार

संपादक जी,

जनवरी 2019 अंक में पत्रकार अमित कुमार ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक का साक्षात्कार किया उसको पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई तथा पटना की सुरक्षा से संबंधित विषय पर पढ़कर अच्छा लगा। प्रश्न एवं उत्तर भी पठनीय है। झारखण्ड में भी सभी एसपी का साक्षात्कार होना चाहिए ताकि पाठकों को इस राज्य के पुलिस अधिकारियों के विषय में विस्तृत जानकारी एवं उसके उद्देश्य का भी पता चल सके। सही एवं उचित लगा साक्षात्कार एवं सामग्री।

✦ **जीवन पटेल, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली**

सेफ्टी मैनेजमेंट

ब्रजेश जी,

''इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट में है रोजगार की आपार संभावना'' आलेख में ललन कुमार प्रसाद ने जनवरी 2019 अंक में सेफ्टी प्रबंधन के लाभ एवं रोजगार की संभावनाएं पर सटीक व कारगर जानकारी दी गई है। इस अंक में अजय कुमार की जमुई का खबर भी काफी रोचक एवं चिंतनीय लगा। रंगीन पृष्ठ नहीं होने की वजह से भले ही इसका बड़ा बाजार नहीं हो पर इसकी खबरें दिल की गहराई तक छूती है। केवल सच का निरंतर प्रयास सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।

✦ **जितेन्द्र जयपुरियार, टावर चौक, मुंगेर**

रामभक्त हूं

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका की लेखनी एवं उसकी धार के साथ उसकी दूरगामी सोच को बेबाकी के साथ पाठकों के समक्ष रखती है। ''**मैं रामभक्त हूं, दलित नहीं!**'' आलेख में राम मंदिर विवाद सहित देश के सात विवादों को बहुत ही प्रमुखता के साथ रखने के अलावा इसपर हो रही राजनीति को भी गंभीरता के साथ आलेख में देने का काम किया है। राजनीतिक समीक्षा के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में होने वाली कूटनीति पर भी सार्थक आलेख इस अंक में पढ़ने को मिला है। इस प्रकार की खबर को बेबाकी से लिखना ही सच्ची पत्रकारिता को दर्शाता है।

✦ **महेन्द्र सोलंकी, नदिया के पार, अयोध्या**

मालिक कौन

संपादक जी,

आपके आलेख वर्त्तमान समय में किसी वरदान से कम नहीं है। जनवरी 2019 अंक का संपादकीय ''**प्रजातंत्र का मालिक कौन**'' में आपने वोटर के पावर को बहुत ही बारीक ढ़ंग से बताने का सार्थक प्रयास किया है। प्रजातंत्र का मालिक के अधिकार एवं उसके साथ हो रहे अन्याय पर सटीक जानकारी सहित नौकरतंत्र पर सही प्रहार इस संपादकीय में पढ़ने को मिला। आवाम की समस्या एवं उसके समाधान के लिए आपकी कलम हमेशा सच्चाई से रू-ब-रू कराती है। आपकी खबर समाज को दिशा देने के साथ - साथ जनता को जागरूक भी करती है।

✦ **रौशन अग्रवाल, सदर बाजार, हजारीबाग**

हार का जिम्मेदार कौन

ब्रजेश जी,

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका समाज का दर्पण का काम कर रही है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव परिणाम पर समीक्षात्मक खबर जनवरी 2019 अंक में अमित कुमार ने ''हार का जिम्मेवार कौन?'' में भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों का इन राज्यों के विधानसभा में की गई राजनीति के हर अनछुए पहलुओं को छूने का सही कोशिश किया गया है। राजनीति पर केवल सच बेबाकी से टिप्पणी करता है, जिसकी वजह से इसकी साख बढ़ती जा रही है। सराहनीय आलेख।

✦ **अभिषेक राय, रेलवे कॉलोनी, भोपाल**

जनसंख्या विस्फोट

मिश्रा जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और सभी खबरों को गंभीरतापूर्वक पढ़ता हूं। जनवरी 2019 अंक में वरीष्ठ पत्रकार तथा फायर सेफ्टी के जानकार ललन कुमार प्रसाद की खबर ''**सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या बिस्फोट**'' में सभी बिन्दुओं पर फोकस किया है उसपर सरकार को गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। जनसंख्या और राजनीति एवं प्रशासनिक महत्वकांक्षा को भी इस आलेख में ध्यान आकृष्ट किया है जिससे मामले को समझने एवं उसके समाधान के लिए प्रयास में सहायक सिद्ध होगा। मजबूत खबर।

✦ **योगेन्द्र साव, पिस्का मोड़, राँची**

अन्दर के पन्नों में

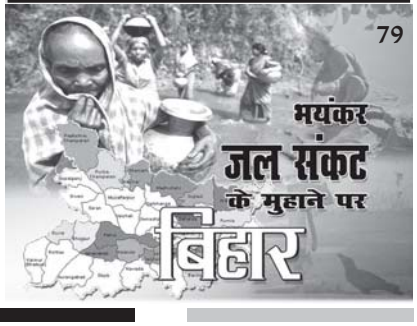

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 13 अंक:- 153 माह:- फरवरी 2019, मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

गोपाल मिश्र **0612/2362784**

संपादक

ब्रजेश मिश्र

09431073769

09955077308 08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

kewalsach_times@yahoo.com

प्रधान संपादक

दीपक मिश्रा 09334096060, 09717857012

सच्चिदानन्द मिश्र 09431878843

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 09430888060, 08873004350

अमोद कुमार 09431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 09308815605, 09122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

रीता सिंह 9471867210, 9308729879

उपसंपादक

डॉ० निर्मल आनन्द 08581837557

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 09576438501

शिवचन्द्र झा 08521329144

संयुक्त संपादक

अमित कुमार ''गुड्डू'' 09905244479

amit.kewalsach@gmail.com

सहायक संपादक

रामपाल प्रसाद वर्मा 09939086809, 07079501106

संजीव रंजन तिवारी 09430915909

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 09608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 09308454485

रणविजय सिंह यादव 09334612716, 09801111138

रवि कुमार पाण्डेय 09507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 09905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 08002647553, 09060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 09905203164

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 09835916650, 09430192929

ब्रजेश मिश्रा 07654122344, 07979769647

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो चीफ

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:-	अभिषेक मिश्र	09431732481
साहेबगंज	:-	अनंत मोहन यादव	09546624444
खूँटी	:-		
जमशेदपुर	:-		
हजारीबाग	:-	शैलेश मेहता	09973027485
जामताड़ा	:-		
दुमका	:-		
देवघर	:-		
धनबाद	:-		
बोकारो	:-		
रामगढ़	:-	दिव्य प्रकाश सिंह	08227979999
चाईबासा	:-		
कोडरमा	:-		
गिरीडीह	:-		
चतरा	:-	धीरज ठाकुर	09430353639
लातेहार	:-	रविकांत पासवान	09801637947
गोड्डा	:-		
गुमला	:-		
पलामू	:-		
गढ़वा	:-		
पाकुड़	:-		
सरायकेला	:-		
सिमडेगा	:-		
लोहरदगा	:-		

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	09470709185
(ग्रा०)	:-		
भोजपुर	:-		
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-	मयंक कुमार	9852569398
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-		
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-	सनोज कुमार	9955672241
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	अविनाश कुमार	9470659050
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-		
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-		
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-		
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-		
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-		
नवगछिया	:-		
बांका	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०-09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०-09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
सेक्टर- 1 ब्लॉक नं.- 22,
फ्लैट नं.- 303,
खेलगांव, होटवार, राँची- 834009
मो०- 9955077308, 9431073769

मध्य प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास,
बेलभाँटा, अभनपुर, रायपुर
(छत्तीसगढ़)
मो०-09835845781,
08602674503

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 7492868363

उत्तर प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उत्तराखण्ड कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

गुजरात कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

राजस्थान कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

हरियाणा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

कर्नाटक कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उड़ीसा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

आसाम कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- शम्भू नाथ मिश्र
रेलवे गेट नं.- 02 राजेन्द्र नगर
वार्ड नं.- 08, लंका, पोस्ट- लंका
जिला-नगावॅ, दिसपुर (आसाम)
मो०- 08135023285, 07631376135

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश कुमार मिश्रा 07992327070
09631400205

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 09433567880
09339740757

उत्तर प्रदेश हेड
गदाधर नाथ मिश्रा 09452127278

महाराष्ट्र हेड
कमोद कुमार कंचन 07783822144

एक नजर इधर भी

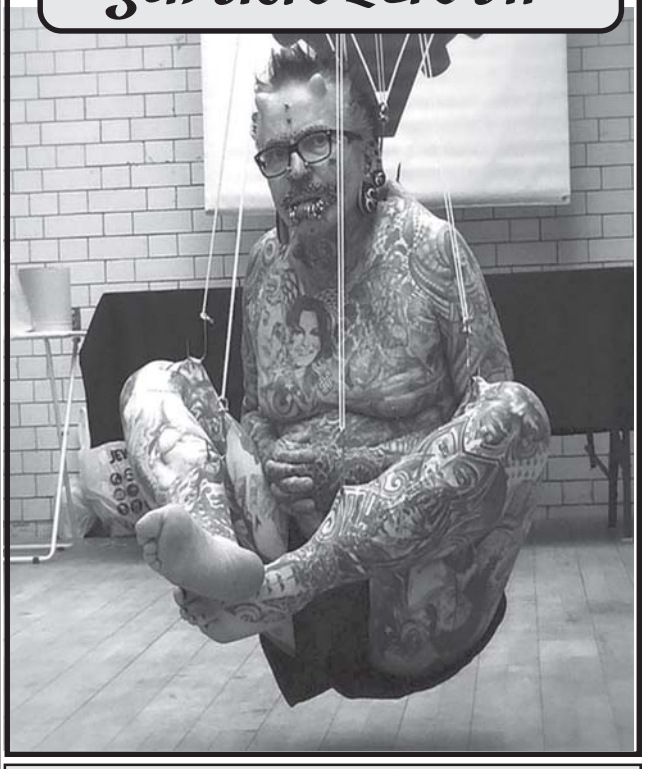

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308
- e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए-17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक-ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।
- A/C No. :- 0600050004768
  BANK :- United Bank Of India
  IFSC Code :- UTBI0KKB463
  PAN No. :- AAJFK0065A

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

झारखण्ड राज्य प्रमंडल ब्यूरो

संथाल परगना दुमका	आवश्यकता है	
दक्षिणी छोटानागपुर राँची	आवश्यकता है	
उत्तरी छोटानागपुर हजारीबाग	आवश्यकता है	
कोल्हान चाईबासा	आवश्यकता है	
पलामू डाल्टेनगंज	आवश्यकता है	

जुड़ने के लिए सम्पर्क करें:- 9431073769

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

www.kewalsach.com

पर पूरी पत्रिका 30 दिनों तक उपलब्ध

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी रालोसपा	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

विशेष प्रतिनिधि

राजेश कुमार मिश्र	8757834700, 7004296529
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
मनीष कुमार कमलिया	9934964551
कामोद कुमार कंचन	7492868363
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
प्रदीप कुमार सिन्हा	9472589853, 6204674225
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
प्रणव कुमार कश्यप	8809903185
सलाम साबरी	9835094832
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
अजय कुमार	9409103023,
रवि कुमार प्रजापति	9470708006
राजेश कुमार	7632936806, 7563816708
अवधेश कुमार शर्मा	9304827131, 8789324045

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

भारत रत्न
देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

Pranab Kumar Mukherjee

Chandikadas Amritrao (Nanaji) Deshmukh

Bhupen Hazarika

● **अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। पहले इसमें खेल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे सूची में शामिल किया गया है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बताते चले कि प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 1955 में बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया। इसके चलते यह सम्मान लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा है। अब तक 12 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया, पर सुभाषचन्द्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के उपरांत मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 11 मानी जा सकती है। एक वर्ष में अधिकत्तम तीन व्यक्तियों को ही 'भारत रत्न' दिया जा सकता है। अन्य प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों की श्रेणी में पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री का नाम लिया जा सकता है। पहले मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिमी गोलाकार स्वर्ण मैडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिन्दी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिह्न और मोटे अक्षरों में लिखा होता था। बाद में इस पदक के डिजाइन को बदल कर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया। इसके नीचे चांदी में लिखा रहता है- 'भारत रत्न' और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। सरकार ने अब तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। सबसे पहले 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस सूची में समाज के हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं। खेल जगत से अब तक किसी को यह सम्मान हासिल नहीं हो पाया था, लेकिन सचिन तेंडुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें यह सम्मान दिया गया है।

गौरतलब है कि भारत रत्न पर कभी किसी भी तरह की कोई गहन चर्चा तब तक नहीं हुई थी, जब तक कि भारत रत्न के नियमो में बदलाव करके भारत सरकार या फिर यूँ कहें कि राहुल गांधी या फिर 10 जनपथ से चलने वाली सरकार ने भारत रत्न के चयन के बने बनाएं नियमो में बदलाव नहीं किया था। भारत रत्न पहले खेल के क्षेत्र में भारत का नाम रौशन करने वालों को नहीं दिया जाता था, पर जब तक एक प्राइवेट क्लब (जैसा कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपने हलफनामे में दिया है।) के लिए खेलने वाले महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का मन नहीं हुआ था। सचिन को भारत रत्न मिलते ही खेल जगत में, भारत के झंडे के लिए खेलने वाले और भारत का दुनिया भर में नाम रौशन करने वाले सभी महान खिलाड़ियों की अनदेखी से ही पहली बार भारत रत्न की चयन प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा और सोशल मीडिया से लेकर खबरिया चैनल तक, दैनिक अखबारों से लेकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक खबरिया दुनियां ने जमकर चर्चा की और इस फैसले की मजम्मत भी की, पर आखिर में जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत को सार्थक करते हुए सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, कपिल देव आदि महान खिलाड़ियों के योगदान को नजरंदाज करके खेल

जगत का पहला 'भारत रत्न' सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया।

सचिन को क्यों? सवाल यह नहीं बल्कि सवाल यह है कि क्या मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह आदि का योगदान कम महान था या फिर इनके पास किसी पोलिटिकल पार्टी के किसी बड़े आका का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था? ये कैसी विडंबना है कि जिस खिलाड़ी के जन्मदिन को भारत में 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के तौरपर मनाया जाता है, उसी को 'भारत रत्न' से नवाजने की कवायद में हम सभी न जाने कब से जुटे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद की बदौलत कई सालों तक हॉकी में भारत का दबदबा बना रहा। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, 1905 को इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। चौदह वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार हॉकी स्टिक अपने हाथ में थामी थी। सोलह साल की आयु में वह आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। चौथवी सदी तक विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर, 1979 को नई दिल्ली में देहांत हो गया था। इसे मेजर साहब की हॉकी के प्रति दीवानगी ही कही जाएगी कि मेजर ध्यानचंद का अंतिम संस्कार किसी घाट पर नहीं किया गया बल्कि उनका अंतिम संस्कार झांसी के उस मैदान पर किया गया, जहां वो हॉकी खेला करते थे। भारतीय फील्ड हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान रहे ध्यानचंद को भारत और दुनिया भर के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाडियों में शुमार किया जाता है। ध्यानचंद तीन बार उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे, जिसने ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीता था। उसमें 1928 का एम्सटर्डम ओलम्पिक, 1932 का लॉस एंलिजल्स ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलम्पिक शामिल है। जब ध्यानचंद ब्राह्मण रेजीमेंट में थे, उसी समय मेजर बले तिवारी से हॉकी सीखी थी। ध्यानचंद सेना की ही प्रतियोगिताओं में हॉकी खेला करते थे। दिल्ली में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जब इन्हें सराहा गया तो इनका हौसला बढ़ा और 13 मई 1926 को न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला था। मेजर ध्यानचंद ने अप्रैल 1949 को प्रथम श्रेणी की हॉकी से संन्यास ले लिया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए, उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है।

गौरतलब है कि ध्यानचंद को देश का शीर्ष नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किए जाने की सिफारिशें केंद्र सरकार को मिली हैं और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे मानवीय व्यवहार से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सेवा या उच्च क्षमता का प्रदर्शन करने वाले नागरिक को प्रदान किया जाता है। वैसे तो भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न प्रदान किए जाने के बारे में विभिन्न सिफारिशें मिली हैं और शायद इसी वजह से इन सिफारिशों को प्रधानमंत्री कार्यालय को विचार करने के लिए भेज दिया गया है। ये बात तो काबिले गौर है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलना 'भारत रत्न' के लिए खुद एक सम्मान की बात है, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी गैर भाजपाई सरकार और राजनीतिक पार्टी को वाजपेयी का भारतीय राजनीति में योगदान अभी तक क्यों नजर नहीं आया था? सवाल तो डॉ० मदन मोहन मालवीय के इतने महान योगदान के बाद इतनी देर से भारत रत्न मिलने पर भी उठता है। कब तक इस तरह की महान हस्तियों की महानता पर कोई किसी ऐसी समिति का सदस्य सवालिया निशान लगाता रहेगा? कब तक देश की महान हस्तियों के साथ यूँ ही खिलवाड़ होता रहेगा? आज देश के प्रधानमंत्री हर किसी कार्य या फिर योजना को लागू करने से पहले आम जनता की राय को सबसे पहले रखते हैं, मानते हैं साथ ही किसी भी योजना को लागू करने से पहले कई तरह के प्रचार करके आम जनता को ज्यादा से ज्यादा अपनी राय रखने को प्रेरित करके आम जनता को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो क्या भारत रत्न के साथ और दूसरे सभी महत्त्वपूर्ण सम्मानों को भी किसी चाटुकार सदस्य के हवाले न करके सीधा जनता के हवाले क्यों नहीं कर देते हैं? ताकि फिर किसी मदनमोहन मालवीय के इतने महान योगदान के बाद भी सम्मान मिलने में इतनी देर न हो साथ ही किसी पोलिटिकल आका की वजह से फिर किसी मेजर ध्यानचंद की अनदेखी न हो।

हालांकि इस दिशा में कुछ कड़े फैसले लेने में नरेन्द्र मोदी की सरकार सामने आ रही है तथा ध्यान रहे कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका एवं आरएसएस से जुड़े नेता एवं समाजसेवी नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किये जाने की घोषणा कर दी है। ज्ञात हो कि 2019 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। वह संप्रग प्रथम और द्वितीय सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। संघ से जुड़े नानाजी देशमुख पूर्व में भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया और जीवन पर्यन्त दीनदयाल शोध संस्थान के अन्तर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विस्तार हेतु कार्य करते रहे। सनद् रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नानाजी देशमुख को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। वाजपेयी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वालम्बन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिये पद्म विभूषण भी प्रदान किया।

बताते चले कि भूपेन हजारिका पूर्वोत्तर राज्य असम से ताल्लुक रखते थे। अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा भूपेन हजारिका हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाना गाते रहे थे। उन्होंने फिल्म 'गांधी टू हिटलर' में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन 'वैष्णव जन' गाया था। उन्हें पद्मभूषण और पद्मविभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। पारंपरिक असमी संगीत का जादू बिखेरने वाले और 'दिल हूम हूम करे' और 'ओ गंगा बहती हो' जैसे कई शानदार गीत गाने वाले भूपेन हजारिका ने अपनी मधुर आवाज के जरिए से कई पीढ़ियों के लाखों लोगों को प्रेरित किया। ब्रह्मपुत्र के कवि को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। कवि, संगीतकार, गायक, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्मकार भूपेन हजारिका ने असम की समृद्ध लोक विरासत को अपने गीतों के माध्यम से दुनिया को परिचित कराया। सादिया में एक शिक्षक परिवार में 1926 में जन्मे हजारिका ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुवाहाटी से 1942 में पूरी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1944 में स्नातक और 1946 में परास्नातक (राजनीति विज्ञान) किया।

उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से

अब तक भारतरत्न से सम्मानित हस्तियों की सूची :–

1.	1954	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	देश के दूसरे राष्ट्रपति
2.	1954	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878–1972)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अंतिम गवर्नर जनरल
3.	1954	डॉ. चन्द्रशेखर वेंकट रमन (1888–1970)	नोबेल पुरस्कार विजेता, भौतिकशास्त्री
4.	1955	डॉ. भगवान दास (1869–1958)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेखक
5.	1955	सर डॉ. मौक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या (1861–1962)	सिविल इंजीनियर, मैसूर के दीवान
6.	1955	पं. जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)	प्रथम प्रधानमंत्री, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी
7.	1957	गोविंद वल्लभ पंत (1887–1961)	स्वतंत्रता सेनानी, उप्र के पहले मुख्यमंत्री, देश के दूसरे गृहमंत्री
8.	1957	डॉ. धोंडो केशव कर्वे (1858–1962)	शिक्षक और समाज सुधारक
9.	1958	डॉ. बिधान चन्द्र राय(1882–1962)	चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
10.	1961	पुरुषोत्तम दास टंडन (1882–1962)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक
11.	1961	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (1884–1963)	प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी, विधिवेत्ता
12.	1963	डॉ. जाकिर हुसैन (1897–1969)	देश के तृतीय राष्ट्रपति
13.	1963	डॉ. पांडुरंग वामन काणे (1880–1972)	भारतविद और संस्कृत के विद्वान
14.	1966	लाल बहादुर शास्त्री –मरणोपरान्त (1904–1966)	देश के तीसरे प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी
15.	1971	इंदिरा गांधी (1917–1984)	देश की चौथी प्रधानमंत्री
16.	1975	वराहगिरी वेंकट गिरी (1894–1980)	देश के चौथे राष्ट्रपति, श्रमिक संघवादी
17.	1976	के. कामराज –मरणोपरान्त (1903–1975)	स्वतंत्रता सेनानी, मुख्यमंत्री, मद्रास
18.	1980	मदर टेरेसा (1910–1997)	नोबेल पुरस्कार विजेता, कैथोलिक नन, मिशनरीज संस्थापक
19.	1983	आचार्य विनोबा भावे –मरणोपरान्त (1895–1982)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक
20.	1987	खान अब्दुल गफ्फार खान (1890–1988)	स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम अभारतीय
21.	1988	मरुदुर गोपाला रामचन्दम –मरणोपरान्त (1917–1987)	अभिनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
22.	1990	डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर –मरणोपरान्त (1891–1956)	भारतीय संविधान के वास्तुकार, राजनीतिज्ञ,अर्थशास्त्री
23.	1990	नेल्सन मंडला (1918–2013)	नोबेल पुरस्कार विजेता, रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता
24.	1991	राजीव गांधी –मरणोपरान्त (1944–1991)	देश के सातवें प्रधानमंत्री
25.	1991	सरदार वल्लभ भाई पटेल –मरणोपरान्त (1875–1950)	देश के पहले गृहमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
26.	1991	मोरारजी रणछोड़जी देसाई (1896–1995)	देश के पांचवें प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी
27.	1992	मौलाना अबुल कलाम आजाद –मरणोपरान्त (1888–1958)	देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी
28.	1992	जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा श्जेआरडी टाटा(1904–1993)	देश के जाने माने उद्योगपति
29.	1992	सत्यजीत रे (1922–1992)	फिल्म निर्माता, निर्देशक
30.	1997	एपीजे अब्दुल कलाम (1931–2015)	देश के 11वें राष्ट्रपति, वैज्ञानिक
31.	1997	गुलजारीलाल नंदा –मरणोपरान्त (1898–1998)	दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी
32.	1997	अरुणा आसिफ अली –मरणोपरान्त (1909–1996)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
33.	1998	एमएस सुब्बालक्ष्मी (1916–2004)	शास्त्रीय संगीत गायिका
34.	1998	चिदम्बरम सुब्रमण्यम (1910–2000)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कृषि मंत्र
35.	1998	लोकनायक जयप्रकाश नारायण –मरणोपरान्त (1902–1979)	स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ
36.	1999	पंडित रविशंकर (1920–2012)	सितार वादक
37.	1999	अमर्त्य सेन (जन्म 1933)	नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री
38.	1999	गोपीनाथ बोरदोलोई –मरणोपरान्त (1890–1950)	स्वतंत्रता सेनानी, असम के मुख्यमंत्री
39.	2001	लता मंगेशकर (जन्म 1929)	पार्श्व गायिका
40.	2001	उस्ताद बिस्मिल्ला खां (1916–2006)	शहनाई वादक
41.	2008	पंडित भीमसेन जोशी (1922–2011)	शास्त्रीय गायक
42.	2014	सचिन तेंडुलकर (जन्म 1973)	भारतीय क्रिकेटर
43.	2014	प्रो. सीएनआर राव (जन्म 1934)	जाने–माने वैज्ञानिक व केमेस्ट्री के विशेषज्ञ
44.	2014	अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1924)	देश के 11वें प्रधानमंत्री, जाने–माने राजनेता
45.	2014	पं. मदनमोहन मालवीय –मरणोपरान्त (1861–1946)	शिक्षाविद, समाज सुधारक
46.	2019	प्रणब मुखर्जी – (जन्म 1935)	देश के 13वें राष्ट्रपति, जाने–माने राजनेता
47.	2019	नानाजी देशमुख –मरणोपरान्त (1916–2010)	समाजसेवी
48.	2019	भूपेन हजारिका –मरणोपरान्त (1926–2011)	संगीतकार–गायक

जनसंचार में पीएचडी की। शिकागो विश्वविद्यालय ने उन्हें सिनेमा के माध्यम से शैक्षिक परियोजना के विकास के उपयोग के अध्ययन के लिए लेस्ले फैलोशिप प्रदान की। अमेरिका में उनकी प्रख्यात अश्वेत गायक पाल राबिनसन से मुलाकात हुई। राबिनसन के प्रसिद्ध गीत ओल्ड मैन रिवर को परिवर्तित कर उन्होंने 'बिस्तर नो परोरे' (हिंदी में-ओ गंगा बहती हो) गाया जो बेहद लोकप्रिय हुआ। हजारिका ने एक बार बताया था कि, 'मैं जनजातीय संगीत सुनते हुए बड़ा हुआ, जिसकी लय ने मेरा गायन के प्रति रुझान विकसित किया। शायद, गायन का कौशल मुझे अपनी मां से विरासत में मिला जो मेरे लिये लोरिया गाती थी। वास्तव में मैने फिल्म रुदाली में अपनी मां की एक लोरी का प्रयोग किया है।' भूपेन ने 12 वर्ष की उम्र में 1939 में अपना पहला गीत बिस्व निजोय नोजवान गाया। यह असम की दूसरी फिल्म इंद्रमालती का एक गीत था। अपनी मातृभाषा असमी के अलावा हजारिका ने 1930 से 1990 के बीच कई दशकों तक हिंदी और बंगाली के लिए भी कई गीत लिखे और गाए। बताते चले कि हजारिका असम के अग्रणी लेखक और कवि में भी शुमार किये जाते हैं। उन्होंने एक हजार से ज्यादा गीत, लघु कहानियों पर कई किताबें, निबंध, यात्रा वृतांत, कविताएं और बच्चों के लिए कई कविताएं लिखीं। उन्होंने असमी में कई फिल्मों का निर्माण, निर्देशन करने और इनमें संगीत देने के साथ-साथ गीत भी गाए। इनमें इरा बातार सुर, शकुंतला, प्रतिधवनि, चिक मिक बिजली, सिराज आदि शामिल हैं। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में रुदाली, एक पल, दरम्यिान, दम और क्यों शामिल हैं।

सनद् रहे कि एक ओर सरकार का जहां इन तीन विभूतियों को भारत रत्न का फैसला हुआ तो वही इसे लेकर बबाल भी मचा हुआ है। बताते चले कि सिद्दागंगा मठ के महंत शिव कुमार स्वामी को भारत रत्न से सम्मानित न किए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दारमैया ने इस चूक के लिए राज्य के भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सिद्दारमैया ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद बातचीत के दौरान इस मामले में केन्द्र सरकार पर दबाव न बनाने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दियुरप्पा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिवंगत स्वामीजी भारत रत्न सम्मान के लिए सर्वथा उपयुक्त हस्ती थे। यदि स्वामी को यह सम्मान दिया जाता तो, इस सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ती। स्वामी का लंबी बीमारी के बाद हाल में निधन हो गया था। सिद्दारमैया ने हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के बाद से देश ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने समाज के कुछ वर्गों की ओर से संविधान की मूल भावना को आहत किए जाने का प्रयास किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों को विफल कर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि एक तरफ जहां सिद्दारमैया भारत रत्न के मुद्दे पर नाराज दिखे तो वही दूसरी ओर सपा नेता आजम खान ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। सपा नेता ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। प्रणब ने संघ की दावत कुबूल की थी और एक कार्यक्रम में उनके हेड क्वार्टर गए थे, यह भारत रत्न उसी का इनाम है। आजम खान ने आगे कहा कि जब भारत रत्न दिए जाने की जानकारी डॉ०. मुखर्जी को मिली तो खुद उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि क्या मैं इसके लायक हूं। शायद उन्हें भी समझ नहीं आया कि भाजपा सरकार ने उन्हें भारत रत्न क्यों दिया। खान ने भाजपा के पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिशों के सवाल पर कहा कि भाजपा पैर जरूर पसारे, लेकिन ख्याल रखे कि नीचे तेजाब न हो। वही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि भारत रत्न जितने लोगों को दिया गया, उनमें से कितने दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, सामान्य वर्ग और ब्राह्मणों को दिए गए? बताते चले की ठाणे में एक सभा में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, पर दिल से नहीं मजबूरी की हालत में दिया गया। औवेसी ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। ओवैसी ने कहा कि हम पर मुस्लिम राजनीति करने का इल्जाम लगाया जाता है पर जब राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस हिन्दुओं की पार्टी है तब कोई कुछ नहीं कहता। ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण दिए जाने का भी विरोध किया था।

बहरहाल, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सुशोभित जो भी गणमान्य हैं या रहे हैं, वह इसके हकदार हैं, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। इस बाबत भारत सरकार द्वारा गत् 26 जनवरी 2019 की संध्या जिन महान विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है वह सम्मान जनक है, जिसे हर एक नेता और नागरिक को स्वीकारना चाहिए। ●

यू.पी. की राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण

● अमिय कुमार पाण्डेय

सर्दियों के इस मौसम में चुनावी सरगर्मीयों के बीच फरवरी के इस अंक में केवल सच पत्रिका के संपादक ब्रजेश कुमार जी जो हमारे लिए एक वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में आते हैं, उनके विशेष आग्रह पे हमने केवल सच अंक में हम आपको यू.पी. की राजनीतिक उठा-पटक से रूबरू कराएगे। हम आपको समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच हुए गठबंधन का उल्लेख तो करेंगे ही इसके अलावे हम कांग्रेस और समाजवाद से जुड़ी व्यभिचारी अभिव्यक्तियों की आजादी के बारे में भी बताएंगे। यू तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमारी रूचि राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लेखों में ज्यादा रहती है। शायद इसलिए हम राजनीतिक लेखों को आपके बीच परोसते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष मजबूत होने लगा, कर्नाटक चुनाव में बढ़त मिली और अभी हाल ही सम्पन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में कांग्रेस की फतह ने उसे राजनीति के उभरते हुए धरातल पर ला खड़ा किया है, बेशक राहुल गाँधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार से जनता की नाराजगी भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। ठीक उसी तरह जैसे 2014 कांग्रेस के प्रति जनाक्रोश ने ही मोदी लहर का नाम ले लिया था, बहरहाल बात उत्तरप्रदेश की हो रही है, और सवाल ये है कि क्या प्रियंका का आगमन कांग्रेस के पुराने दिन वापस ला सकता है, तो इसका जवाब है, हाँ लेकिन ये हाँ उतना आसान नहीं है, जितना कांग्रेसी समझ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो वो घुमाएंगी और यूपी की लोकसभा की 80 सीटें उनके नाम हो जाएगी। कांग्रेस प्रियंका के बहाने यूपी में इंदिरा गाँधी की छवि को भुनाना चाहती है, साथ ही वो अपने परंपरागत वोटरों को एकबार फिर अपने पाले में लाना चाहती है, लखनऊ के नेहरू भवन जाते समय बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा का माल्यार्पण दलित वोटरों को लुभाने का ही संकेत था, वहीं अल्पसंख्यक वोटरों का रूझान भी इन दिनों सपा की तरफ से खिसककर वापस कांग्रेस की तरफ गया है, जो कांग्रेस प्रियंका के माध्यम से पूरी तरह भुनाने का प्रयास करेगा, यही दूसरी तरफ सवर्ण हिन्दुओं को मोदी सरकार ने जो 10% आरक्षण का लौलीपॉप दिया है, यो लोग भलीभांति जानते हैं कि चुनावी जुमले से बढ़कर कुछ और नहीं है, उसके अलावा गौरक्षा के नाम पर फसलों को बर्बाद करते गौवंशियों से जिस कदर उत्तर प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है वो फैक्टर भी लोकसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा, कुल मिलाकर यूपी में राजनीति के बनते-बिगड़ते समीकरणों के बीच एक बात साफ हो गई जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी कहीं ना सामने भी आया है कि यूपी में लोकसभा

चुनाव ने कांग्रेस को बढ़त और बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिख रहा है। जहाँ एक तरफ सपा-बसपा के गठबंधन के लिए प्रियंका की राजनैतिक दस्तक खतरे की घंटी बताई जा रही है, वहीं दूसरे तरफ यूपी में योगी का कुनवा भी प्रियंका की धमाकेदार एंट्री से परेशान, परेशानी की लकीरें राजनीति के धरातल पर दिखे ना दिखे पर राजनेताओं के चेहरे पर साफ दिख रही है। यूपी में योगी-मोदी की जोड़ी के तौर पर प्रियंका-राहुल की जोड़ी को देखा जा रहा है। अब बात करते हैं यूपी में कांग्रेस के परम्परागत मतदाताओं की, यूपी में तथा कथित दलित, अल्पसंख्यक और हिन्दू सवर्ण ये कभी कांग्रेस के परम्परागत वोटर्स हुआ करते थे, ये वो समय था जब यूपी और केन्द्र में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त के साथ यूपी में सियासत का ध्रुवीकरण हुआ, जिस कारण हिन्दू सवर्ण बीजेपी के खेमे में खिसकता चला गया, यहीं अल्पसंख्यक, मुलायम के साथ हो लिए और दलितों ने मायावती का दामन थाम लिया, जिसके कारण लम्बे समय तक कांग्रेस को यूपी में ना सिर्फ सत्ता से दूर रहना पड़ा बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस यूपी में अपने अस्तित्व तक को खोती नजर आई, लेकिन 2014 के आम चुनाव का परिदृश्य कुछ और था जबकि 2019 में आलम कुछ और है।

लोकसभा से पहले कांग्रेस की संजीवनी कितना काम करती है, ये तो भविष्य के गर्भ में समाया हुआ एक ऐसा सच है, जो निकट भविष्य में तय हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक मानी जाने वाली प्रियंका गाँधी बाड्रा ने लखनऊ में रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर प्रियंका के समर्थन में एक बड़ा जन सैलाव देखने को मिला। इस दौरान प्रियंका के साथ उनके भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी भी रहे। साथ ही कांग्रेस की युवा ब्रिगेड भी नजर आई, संभवतः कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसे में इस मेगा शो के जरिए पार्टी कार्यकर्त्ताओं में उत्साह भरने की तैयारी है। यह रोड शो एयरपोर्ट मोड़-शहीद पथ तिराहा - अवध चौराहा-आलमबाग चौराहा-नाथा होटल तिराहा-हुसैनगंज चौराहा-बर्लिंगटन चौराहा-लालबाग तिराहा-हजरतगंज चौराहा- विक्रमादित्य चौराहा होते हुए नेहरू भवन तक गया, लखनऊ में प्रियंका के स्वागत में पोस्टर लगाए गए थे, इन पोस्टरों में प्रियंका गाँधी बाड्रा को माँ दुर्गा बताया गया था, भले ही ये सियासत में महिमामंडन की पराकाष्ठा रही हो, लेकिन प्रियंका के रोड शो और सड़कों पर उमड़े जनसैलाव को देखकर एक बार जरूर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका के आगमन से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है, जो खासकर यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। बरहाल आने वाला चुनाव लोकसभा का बड़ा दिलचस्प मुकाबला लिए जा रहा है, खैर जनता ही है सर्वोपरि क्योंकि अंततः जनता ही है जनार्दन। ●

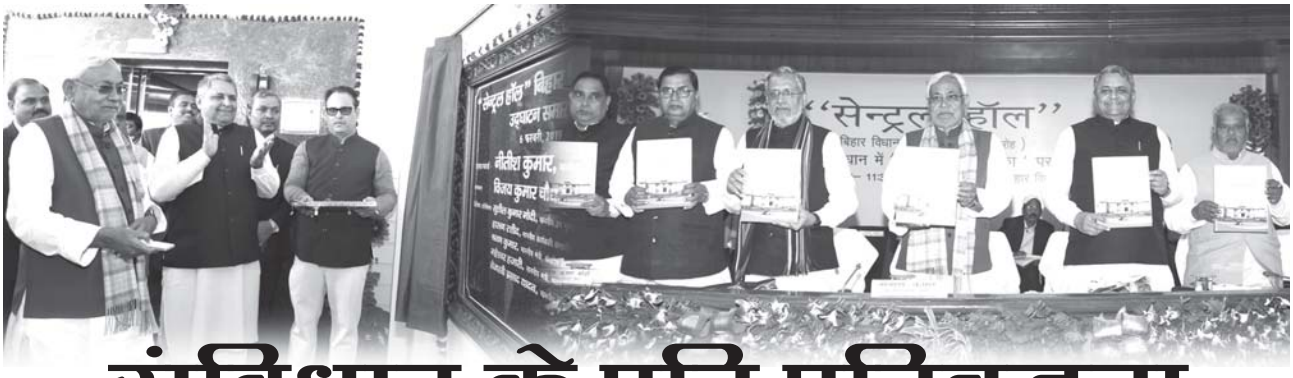

संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी : मुख्यमंत्री

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

पिछले 6 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल विस्तारित भवन के अंतर्गत बिहार विधानमंडल "सेंट्रल हॉल" का उद्घाटन किया तथा 'भारतीय संविधान में विधायिका की भूमिका' विषय पर विचारगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि आज सेंट्रल हॉल का विधिवत उद्घाटन हुआ है। वर्ष 2007–08 में बिहार विधानसभा, पुराना सचिवालय को बेहतर ढंग से बनाने की अवधारणा बनायी गई थी। उसके लिए अच्छे कन्सलटेंट से संपर्क किया गया, फिर डी0पी0आर0 तैयार कर विधानमंडल में इसकी रुप रेखा रखी गई। 26 जनवरी, 2010 को गणतंत्र दिवस की संध्या पर इसका शिलान्यास किया गया था। 19 नवंबर 2016 को इसका उद्घाटन किया गया लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे, जो आज पूरे तौर पर कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, मुख्यमंत्री का कक्ष एवं मंत्रियों का चैम्बर बनाया गया है। एक बेहतर लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। पढ़ने की जगह की उचित व्यवस्था की गई है, जो भी सदस्यगण अध्ययन करना चाहेंगे उन्हें काफी सहुलियत होगी। जब हम सांसद थे उस दौरान पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल की अवधारणा मेरे मन में थी उसी के अनुरुप इसे बनाया गया है। इसका फर्निचर भी बिल्कुल वैसा ही मजबूत और सुंदर बनाया गया है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में

सांसदगण, पूर्व सांसद आकर बैठते हैं और आपस में दलगत भावना से उठकर एक दूसरे से प्रेम पूर्वक विचार विमर्श करते हैं। संसद में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आपस में कितना भी तकरार कर लें लेकिन सेंट्रल हॉल की खासियत है कि यहां का माहौल सौहार्द्रपूर्ण बना रहता है। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में भी ऐसा ही वातावरण देखने को मिले। यहां खाने–पीने की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 फरवरी, 2019 को बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को सेन्ट्रल हॉल में ही राज्यपाल संबोधित करेंगे। 7 फरवरी 1921 को बिहार विधानमंडल की स्थापना की गई थी उसके 98 वर्ष के बाद आज यह सेंट्रल हॉल बनकर तैयार हो गया है, यह हमलोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसमें जरुरत की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और भी यहां जो कुछ करने की जरुरत होगी उसको किया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ही सबकुछ है उसके अनुपालन से ही देश में सारी चीजें हो रही हैं। संविधान में मौलिक अधिकार, संप्रभुता, नीति निर्देशक तत्व, धर्म निरपेक्षता, फेडरलिज्म जैसी मौलिक चीजों की विस्तृत चर्चा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के

प्रावधानों का पालन करने के अंतर्गत ही बिहार में वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू की गई। उन्होंने कहा कि संविधान का ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि देश का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर बना रहे। केंद्र को भी अधिकार दिए गए हैं और राज्य को भी अधिकार दिए गए हैं। फेडरलिज्म जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। राज्यों की स्वायतता का ख्याल रखा गया है और केंद्र की भी अपनी जिम्मेवारियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन तीनों के संविधान के अंतर्गत अपने–अपने अधिकार एवं कर्तव्य हैं उन्हें अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना होता है। विधायिका को नियम बनाने हैं तो, कार्यपालिका को उसका अनुपालन करना है और न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करनी है। अपने–अपने विचार एवं कार्यक्रम के अनुसार राजनीतिक पार्टियां भी देश के लिए काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हम सबकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

बताते चले कि वर्ष 1917 में शुक्ल जी के अनुरोध पर बापू यहां आए और चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से एक व्यापक जन आन्दोलन हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी हुई। देश में ऐसा वातावरण बना कि 30 वर्ष के अंदर ही वर्ष 1947 में देश आजाद हो गया। बापू ने पर्यावरण के प्रति भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी हमारी जरुरतों को पूरा करने में सक्षम है, लालच को नहीं। हम सबों को इसके प्रति सोचने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में 12 सौ से 15 सौ मिली मीटर तक वर्षापात होती थी। पिछले 13 वर्षों में सिर्फ एक वर्ष रेनफॉल 1000 मिली मीटर था, जबकि औसत रेनफॉल 800 मिली मीटर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू ने सात सामाजिक पापों की चर्चा की है जिसमें सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमने सभी सरकारी बिल्डिंगो में बापू के पर्यावरण संबंधी संदेश और सात सामाजिक पापों को अंकित करवा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस परिसर में भी इसे अंकित करवा दें, तो बेहतर होगा। 10 प्रतिशत लोग भी अगर इसका अनुपालन करेंगे तो समाज बदल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेंट्रल हॉल अच्छा बना है और मेरा ऐसा विश्वास है कि सेंट्रल हॉल में सभी सदस्यगण एवं पूर्व सदस्यगण सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर आपस में विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंटकर किया। कार्यक्रम के दौरान कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। कार्यक्रम को बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री हारुण रशीद, भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी, संसदीय कार्यमंत्री श्री श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, विधायकगण, विधान पार्षदगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षदगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित, अन्य पदाधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ●

शिव को क्यों प्रिय है भस्म?

शिवजी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व है। बारह ज्योर्तिलिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। यह प्राचीन परंपरा है। आइए जानते है शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित की जाती है? भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं, उतने ही रहस्यमयी भी हैं। भोलेनाथ का रहन–सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग हैं। शास्त्रों में एक ओर जहां सभी देवी–देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिवजी सदैव मृगचर्म (हिरण की खाल) धारण किए रहते हैं और शरीर पर भस्म (राख) लगाए रहते हैं।

शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढंका रहता है। शिवपुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है, एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग (त्रेता युग, सत युग, द्वापर युग और कलियुग) के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्माजी द्वारा की जाती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिवजी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है।

शिवपुराण के लिए अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है, उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिवजी को अर्पित की जाती है।

ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वह सभी सुख–सुविधाएं प्राप्त करता है। शिवपुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान–सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म, त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम भी करती है। शिवजी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहां का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहां जैसे हालात बनते हैं, हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां हो रहे यज्ञ के हवनकुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचौन हो गये। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्माण्ड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचौनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। पिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती

के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। जहां जहां उनके अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं। कथाओं के माध्यम से उनका रहन–सहन एक आम सन्यासी सा लगता है। एक ऐसे ऋषि सा जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंत काल सब कुछ राख हो जाना है। एक रहस्य यह भी हो सकता है चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है। ब्रह्मा जहां सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन–पोषण लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानि की समाप्ति और भस्म इसी अंत इसी विध्वंस की प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दें अन्यथा अंत में सब राख ही होगा।●

महाकाल की भस्मार्ती

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्मार्ती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले श्मशान भस्म से भूतभावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती–श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधियुक्त उपलों में शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ीबूटी और कपूर–गुगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म ना सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे तीन प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कण्डे को जलाकर भस्म तैयार की हो वह लौकिक भस्म है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए ना जाने क्या–क्या करते हैं। एक दिन इसी इस भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करता ही है तथा सब रोम कूपों को ढंककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोम कूपों के ढंक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं।

मुहावरों का मजलिस

● **आनन्द प्रकाश पाण्डेय**

एक आस्तिक का बयान :– हे प्रभे! तुम तो ''उड़ती चिड़िया पहचानने वाले'' ''अंधे की लकड़ी'' हो। तुमसे क्या छुपाऊँ – हमारा वह सामने वाला पड़ोसी जिससे हमारी ''दाँत काटी रोटी'' थी, ''आस्तीन का साँप'' निकला। उसके फेर में मेरी ''इज्जत मिट्टी में मिल गई।'' मैं ''अपना उल्लू सीधा'' करने के लिए ''गिरगिट की तरह रंग बदलता'' रहा, ''सफेद झूठ बोलता रहा'' फिर भी उसकी ''आँखों में धूल न झोंक'' सका। हम ''खून पसीना एक कर'' उसके लिए हमेशा ''कुआँ खोदते रहे'' किन्तु मुझे क्या पता कि हमारे ''पट्टी पढ़ाने'' के बावजूद उल्टे मुझे ही ''लेने के देने पड़ जायेंगे''। ''पाँचों उंगलियाँ घी में'' होने के बावजूद मेरी ''अक्ल पर पत्थर पड़ गया'' था जो मैं हर हमेशा उसके सामने ''भींगी बिल्ली बना'' रहा। जब ''मेरे पौ बारह''– ये तो मैं ''बाँसों उछलता'' रहा, मैं अपने को ''गुदरी का लाल'' समझकर ''घोड़ा बेचकर सोता रहा।'' ''तिल का तार करना'', ''गड़े मुर्दे उखाड़ना'' मुझे ''बांये हाथ का खेल'' प्रतीत होने लगा किन्तु ''निन्यानवे के फेर'' में हमारी ''अक्ल मारी गई'' और मैं ''दो कौड़ी का आदमी बनकर रह गया। जब उसने मुझे ''सिर आँखों पर बैठाया'' तो मुझे ''अपना सितारा चमकता'' दिखाई देने लगा। उसे ''भूल–भूलैया में पड़ता देख'' ''बगुला भगत बना'' बहार लूटता रहा। किन्तु हमारी मेहनत पर तब ''घड़ों पानी पड़ गया'' जब मुझे हर बात में ''टाँग अड़ाते देख'' वह मुझसे ''पल्ला छुड़ाने'' का यत्न करने लगा। फिर तो ''ठाकुर सुहाती करने'' के एवज में ''खरी–खोटी सुनने'' पर ही बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार मेरी ''एक न चली'' और सारी योजना ''टाँय–टाँय–फिस्स'' होकर रह गई। मुझे क्या पता था कि इस तरह ''सात–पाँच करते'' किसी षट्राग में पड़कर सब ''गुड़–गोबर'' हो जायेगा। हे भगवान, अब तुम ही उसको ''ईंट का जवाब पत्थर से देना।'' वह ''किस खेत की मूली है'' जो तेरे भक्तों को ''मूली गाजर समझे'', ''टेढ़ी नजरों से देखे।'' बोला भगवान क्या इस तरह वह तेरी ''आँखों में धूल झोंक सकेगा?'' ना प्रभो ना, ऐसा नहीं हो सकता, तू उसको ''ऐसी की तैसी कर'' उसकी ''नाक में दम कर देना।'' ''कान खोलकर सुन'' लो प्रभो। अगर मुझे अपना भक्त स्वीकार करते हो तो उस ''भाड़े का ट्टटू'' पर ऐसा ''सितम ढाना'' कि ''लाख का घर खाक'' हो जाय। फिर जीवन भर वह ''आठ–आठ आँसू रोता'' रहे और कोई ''आँसू पोछने वाला'' तक न मिले। मैं अपने लिए क्या मांगू भगवान? क्या ''चिराग तले अंधेरा'' तुम्हें अच्छा लगता है? तुम तो ''छप्पर फाड़कर देने वाले'' हो। अपने मुँ से कुछ मांग कर अपने ''मूँह मियां मिट्ठू बनना'' नहीं चाहता। इस पर भी तुम अगर देना ही चाहते हो तो मेरे कथित पड़ोसी को ''पर्वत से राई कर दे'' और मुझे ''पत्थर से पारस'' कर दे। बस! भगवान बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ●

आर्थिक आधार पर आरक्षण

आर्थिक आधार पर आरक्षण संसद में पास हो चुका है। अब सामान्य वर्ग के लोग भी 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर उठा सकते हैं। यह एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है, जो देश को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेगी। आरक्षण इससे पहले भी दिए गए लेकिन इससे कहीं–न–कहीं समाज ने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, मगर मोदी सरकार की इस पहल ने सबका दिल जीत लिया। लोकसभा में 5 घंटे से अधिक समय तक इस पर बहस हुई और सिर्फ 3 सांसदों ने इसका विरोध किया और अपार बहुमत से यह विधेयक पास हुआ। राज्यसभा में सफर थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन वहां भी आसानी से ये बिल पास हो गया है और अब वह दिन दूर नहीं, जब सरकारी संस्थानों और शैक्षिक संगठनों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ यह है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह लाभ केवल हिन्दू धर्मावलंबी व अनारक्षित जातियों के लिए ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों को भी मिलेगा।

★ संसद में कैसा रहा सफर? :– लोकसभा में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने संविधान (124वां संशोधन), 2019 विधेयक का समर्थन किया, साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा, क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है। आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ धोखा है। सवर्ण आरक्षण बिल को आईएनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला ने लॉलीपॉप बताया, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बहस में शिरकत करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब को पहली बार फायदा मिलेगा। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है, लेकिन सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा नहीं है। सत्र के आखिरी दिन बिल लाए जाने का औचित्य समझ के बाहर है। आरएलएसपी के उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ें हों तथा बिल में इस प्रावधान को जोड़ा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को सभी पदों पर असमानता दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से समाज के सभी वर्गों को आरक्षण की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अगड़ी जातियों के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने से वे खुश हैं। उन्होंने सरकार के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि ये सभी के लिए समान अवसर वाली बात है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी दलों ने अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। सवर्ण आरक्षण पर अब तक सही प्रयास नहीं हुए थे। पिछली सरकारों ने सही कोशिशें नहीं की थीं। लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरीबों की सरकार होने की बात कही थी और इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया। उनके जवाब के बाद सदन ने 3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 124वां संविधान संशोधन बिल, 2019 का लोकसभा से पारित होना देश के इतिहास में मील का पत्थर है। इसे मंजूरी मिलने से समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। आगरा में हुई जनसभा में उन्होंने इस बिल को नए युग का सूत्रपात बताया। राज्यसभा में भी इस बिल पर लंबी चर्चा हुई। सभी दल पहले ही इस बिल पर समर्थन जता चुके थे इसलिए इसका पास होना लाजमी था।

★ आरक्षण का इतिहास :– आरक्षण की आग में देश कई बार झुलस चुका है। पहली बार मंडल कमीशन की सिफारिशों को 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया तो देश में सवर्ण समुदाय के लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर आए। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव

गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया था। इसके अलावा कई जगह आगजनी व तोड़फोड़ तक हुई। एक तरफ जहां आरक्षण विरोधी लोग उनके कट्टर दुश्मन बन गए तो दूसरी ओर आरक्षण समर्थकों ने वीपी सिंह को नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो उनके बीच से नहीं थे। इतना ही नहीं, जो वीपी सिंह 1987–89 के बोफोर्स अभियान के जमाने में मीडिया के अधिकतर हिस्से के हीरो थे, वे मंडल आरक्षण के बाद खलनायक बन गए। मीडिया के एक बड़े हिस्से के उनके प्रति बदले रुख से वीपी इतने दुरूखी हुए थे कि उन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। लेकिन आरक्षण की आग यहीं नहीं थमी और शुरुआत हुई एक नई राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग की जिसने देश के विकास के स्वरूप को ही बदल दिया।

★ अनेक आरक्षण आंदोलनों की शुरुआतः–

☞ **गुर्जर आंदोलन :–** इस कड़ी में राजस्थान में गुर्जर समुदाय को शामिल किया जा सकता है जिसने अनेक बार राजस्थान को आरक्षण के मुद्दे पर सुलगाए रखा। ये समुदाय अलग से आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरा और कई दिनों तक रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। साल 2008 में गुर्जर आंदोलनकारियों ने जमकर बवाल काटा था। उन्होंने तोड़फोड़ की व रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की गोलीबारी की वजह से हिंसा भड़क गई थी। कई लोगों की मौत भी हुई। साल 2015 में एक बार फिर गुर्जर समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया, पटरियां उखाड़ीं व आगजनी की जिससे 200 करोड़ का नुकसान हुआ।

☞ **पटेल आंदोलन :–** साल 2015 में हार्दिक पटेल एक ऐसे ही आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे जिनके नेतृत्व में पटेल आंदोलन से पूरा गुजरात हिल गया था। हार्दिक को पुलिस ने हिरासत में लिया तो सूबे का माहौल ही बिगड़ गया। देखते ही देखते पटेल समाज के लोग शहरों में सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए करीब 125 गाड़ियों में आग लगा दी, हालांकि कुछ समय बाद ये आंदोलन खुद ही ठंडा पड़ता नजर आया।

☞ **जाट आंदोलन :–** साल 2014 के आम चुनावों से पहले यूपीए सरकार ने जाट समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया था जिसे न्यायालय ने रद्द कर दिया था। हरियाणा सहित कई राज्यों में जाट समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और उनके आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। आंदोलन के दौरान करीब 30 लोगों की जान गई और राज्य को 34,000 करोड़ रुपए की धनहानि हुई और दिल्ली को कई दिनों तक प्यासा रहना पड़ा था।

☞ **आंध्रप्रदेश में आंदोलन :–** आंध्रप्रदेश के कापू समुदाय ने 2016 में ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन किए। प्रदर्शनकारियों ने रत्नाचल एक्सप्रेस के 4 डिब्बों सहित 2 पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान कई लोग व पुलिसकर्मी घायल हुए।

☞ **मराठा आरक्षण :–** महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से प्रयासरत है। इसके लिए मराठा लोग कई बार सड़क पर उतरे चुके हैं। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और महाराष्ट्र के विधानसभा में 16 फीसदी मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया गया।

☞ **50 फीसदी आरक्षण की सीमा :–** पहले भी आरक्षण की तय सीमा को बढ़ाने को लेकर प्रयास होते रहे हैं, मगर संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। याद कीजिए साल 1991 में जब नरसिंहराव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और कहा था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक गैरबराबरी दूर करने के मकसद से रखा गया है, लिहाजा इसका इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर नहीं किया जा सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की रोशनी में राजस्थान, गुजरात व हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों के इसी तरह के फैसलों को उन राज्यों की हाईकोर्टों ने भी खारिज किया।

☞ **क्या सोचता है आम नागरिक? :–** आम नागरिक सरकार के इस फैसले से खुश है कि जो काम बहुत पहले किया जा सकता था वह ''देर आए, दुरुस्त आए'' की तर्ज पर अब किया गया है। कुछ लोग भले ही बिल की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन राजनीति से परे इसको समाज की बड़ी जरूरत भी बता रहे हैं, साथ ही ये भी कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरियों की ही कमी है, तो ऐसे में इस बिल से क्या लाभ होने वाला है?

☞ **निष्कर्ष :–** देश का बड़ा युवा वर्ग आरक्षण को खत्म करना चाहता था और उसके मन में कहीं–न–कहीं समान अवसर न पाने की टीस साफ झलक रही है और वो समान अवसर चाहता था, मगर इस बिल को लेकर उसके मन में ऐसा उत्साह नहीं है। याद कीजिए कि 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थीं तब भाजपा इसके खिलाफ थीं और उसे अपार जनसमुदाय का समर्थन हासिल हुआ था और उसकी राजनीति की जमीन तैयार हुई थी। मगर जब उसे 2014 में इतना बड़ा अवसर मिला भी तो उसने भी आरक्षण को खत्म करने की बजाय इसमें 10 प्रतिशत और जोड़ दिया, वजह चाहे जो भी हो। हाल ही में भारत के छोटे से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर एक नए युग में प्रवेश किया है, जहां सिर्फ मेहनत, हुनर और आपकी काबिलियत ही भविष्य है, न कि आरक्षण।●

दहाड़ से डगमगा रहा सिंहासन

प्रियंका की इंट्री से सहमी भाजपा

● अमित कुमार

लोकतंत्र के हित के लिए लोकशाषक बनाने हेतु आम चुनाव का विगुल बज चुका है, यह सर्वविदित है और इसके तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पूरे दम-खम के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की विजय पताखा लहराने के लिए आतुल हैं। किन्तु, यह तभी संभव है जब संसद के दोनो सदनों यानि राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के साथ वाली खड़ी भाजपा सह एनडीए की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंगेंगे और इसके मद्देनजर फिलवक्त देश के महत्वपूर्ण दो राज्य, पश्चिम बंगाल और बिहार में सियासी ठिकरा शुरू हो चुका है तथा चुनावी अखाड़े में खुद को मजबूत करने के जद्दोजहद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा रैली आयोजित किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई दिग्गज नेताओं को एक मंच पर देख गया। चूकि चुनाव नजदीक है तो जनता के बीच जाने के एक सशक्त माध्यम है रैली। इसके तहत अन्य राज्यों में विपक्षियों द्वारा इसकी रैलियों की शुरूआत कर दी गई है। वही केन्द्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीते 3 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस ने जन अकांक्षा रैली को आयोजित किया। सनद् रहे कि इस रैली में भी महागठबंधन एक मंच पर दिखी।

गौरतलब है कि कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

बनर्जी की पहल पर हुई विराट रैली ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान पहली बार देशव्यापी विपक्षी एकता की संभावना का स्पष्ट संकेत दिया है। इस रैली में कांग्रेस समेत 22 राजनीतिक पार्टियों के 25 वरिष्ठ नेता शामिल थे, लेकिन वामपंथी पार्टियों की इसमें शिरकत नहीं थी। यूं भी सीपीएम अभी तक अपनी राजनीतिक लाइन तय नहीं कर पाई है और अन्य वामपंथी पार्टियां भी अंधेरे में ही रास्ता टटोल रही हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसी विभिन्न क्षेत्रों, जनाधारों और विचारधाराओं वाली इन सभी पार्टियों का एक साझा उद्देश्य आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की छत्रछाया में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की दुर्गति हुई है, देश में हर प्रकार की असहिष्णुता बढ़ी है, अर्थव्यवस्था तहस-नहस हुई है और रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद में घोटाले के आरोप भी सामने आए हैं, उसके कारण सरकार की लोकप्रियता में काफी गिरावट

आई है। यदि विपक्ष इसका चुनावी लाभ उठाना चाहता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पहले कुछ समय तक एक फेडरल फ्रंट यानी संघीय मोर्चे की बात भी चली थी, जिसे तेलांगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने प्रस्तावित किया था और ममता बनर्जी उसके प्रति आकर्षित भी हुई थीं, लेकिन उन्हें और अन्य पार्टियों के नेताओं को भी जल्दी ही समझ में आ गया कि भाजपा और कांग्रेस को एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं होगा और कोई तीसरा मोर्चा मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ही होगा। यही कारण है कि हमेशा कांग्रेस का विरोध करने वाले चंद्रबाबू नायडू भी रैली में मौजूद थे। बीजेपी ने इसे राजनीतिक अवसरवाद कहा है, लेकिन वह गठबंधन बनाने का अपना इतिहास भूल गई। उसने इन पार्टियों के आपसी अंतर्विरोधों और तनावों की ओर भी इशारा किया है, जबकि रैली में शामिल पार्टियों और उनके नेताओं को भी इनका पूरा-पूरा अहसास है और वे इसके बावजूद एकजुट हुए हैं। इस रैली में यह संकल्प भी लिया गया कि देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की रैलियां की जाएंगी ताकि विपक्षी एकता न केवल मजबूत हो बल्कि देशवासियों को भी वह मजबूत होती हुई दिखे और उन्हें उसकी ताकत में यकीन हो जाए। यह सही है कि विपक्षी एकता का निर्माण केवल सदिच्छा के आधार पर नहीं किया जा सकता। सभी नेताओं की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। पार्टियों के जनाधार अलग-अलग हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उनके बीच कैसा और कितना तालमेल हो पाएगा, उसी से पता चलेगा कि एकता कितनी कारगर होगी। उधर सबसे अधिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अभी तक विपक्षी एकता अधूरी है,

क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी समझौता और सीटों का बँटवारा हो चुका है। कांग्रेस इस गठबंधन के बाहर है और अजित सिंह के राष्ट्रीय लोक दल के साथ अभी बातचीत चल रही है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। यह महागठबंधन किसी को भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने से बच रहा है, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती के सिपहसालार अभी से उनका नाम उछालने लगे हैं और यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। सभी को पता है कि गठबंधन की अपनी समस्याएं होती हैं लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब इन समस्याओं के साथ सफलतापूर्वक निबटा गया। स्वयं मोदी सरकार औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतंत्रिक गठबंधन की सरकार है। बीजेपी को भी अपने सहयोगी दलों की ओर से लगातार परेशानी रही है। शिवसेना तो उस पर लगातार प्रहार करती ही रहती है, अब नीतीश कुमार के जनता दल युनाईटेड ने असम में नागरिकता कानून को लेकर असहमति जता दी है। लोकसभा में उसके सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और अब राज्यसभा में वे इसका विरोध करेंगे। इसलिए बीजेपी विपक्षी गठबंधन की इस मुद्दे पर कोई प्रभावी आलोचना नहीं कर पाएगी कि इसमें शामिल दलों के बीच अंतर्विरोध हैं। कांग्रेस भी अब गठबंधन की राजनीति का अनुभव हासिल करती जा रही है और कर्नाटक में उसने कम विधायकों वाले एचडी कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दिया है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए वह कुर्बानी भी दे सकती है। उत्तर प्रदेश में भी एसपी और बीएसपी के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है क्योंकि अभी चुनाव होने में दो-तीन माह का समय है। जो भी हो, पहली बार मोदी सरकार को प्रभावी चुनावी चुनौती मिलती नजर आ रही है।

बहरहाल चुनाव की तैयारियों को लेकर महागठबंधन एक मंच पर मिलकर जिस प्रकार की रैलियां कर रही है और एकजुटता से सप्रग सरकार को हटाने की मुहिम छेड़ी है, उसे बीते 3 फरवरी को पटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में देखा गया। बताते चले की बिहार की राजधानी पटना की सड़कें पोस्टरों से पटी हुई थी किन्तु एक एक पोस्टर जो बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिंह की ओर से बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम के मेन गेट पर लगाया गया था, जिसमें राहुल गांधी को राम के रूप में दिखाते हुए लिखा गया है, 'वे राम नाम जपते रहे! तुम बनकर राम जियो रे!!' इसी तरह के एक और पोस्टर में 'त्रिदेव' लिखकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भगवान के रूप में दिखाया गया था। ज्ञात हो कि ये सभी पोस्टर 3 फरवरी को गांधी मैदान में संपन्न हुई जन आकांक्षा रैली को लेकर लगाए गए थे। इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बिहार में यूपीए

महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को हिन्दू देवी-देवताओं के रूप में पेश कर रैली में शामिल होने की अपील की जा रही थी। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आगामी चुनावों में बिहार कांग्रेस इस बार सवर्ण हिन्दू वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहती है। किन्तु कांग्रेस की नीतियां उसके पतन का कारण हमेशा से बनी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस की नीतियां गलत रहीं। वही जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं के पास मुद्दे थे। जवाहरलाल की छवि फ्रीडम फाइटर की थी, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, राजीव गांधी की नीतियों की तारीफ आज भी लोग करते हैं। मगर आज की कांग्रेस के पास मुद्दों का नितांत अभाव हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार और मत प्रतिशत घटने का सिलसिला 1991 के बाद से शुरु हुआ था। 1991 में हुए दसवें लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करीब 24 फीसदी मत मिले थे लेकिन, उसके बाद वोट शेयर गिरता गया। 1998 में कांग्रेस को केवल 7.3 फीसदी वोट ही मिल सका, जबकि 2004 में मतों का प्रतिशत और गिरकर 5.4 फीसदी पर आ गया। हालांकि, 2009 में जब कांग्रेस ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा तो वोट शेयर का ग्राफ चढ़कर 10 फीसदी पर आ गया। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक 1991 के बाद से बिहार में कांग्रेस के घटते राजनीतिक कद का एक कारण लालू प्रसाद यादव का साथ भी रहा। जब से कांग्रेस ने लालू से हाथ मिलाया है तभी से उसका पतन भी शुरु हो गया। लालू की छवि जमनानस में कैसी है, ये किसी से छुपा नहीं है। रही सही कसर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति और नेतृत्व के अभाव ने पूरा कर दिया। नीतियों में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है हालांकि, जिस तरह हाल ही में हुए तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता

है कि 30 साल के बाद पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस ने रैली की है। बिहार में कांग्रेस द्वारा इतने बड़े स्तर पर रैली इसके पहले 1989 में हुई थी। हालांकि, 2015 की राजद की स्वाभिमान रैली में भी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना संबोधन यहां दे चुकी हैं। लेकिन इस रैली से कांग्रेस को क्या कुछ मिलेगा, इस बारे में बिहार कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह बताते हैं, कि जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, ये रैली उन्हें हमारा अहसास दिलाएगी। 'मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक जितनी भी पार्टियों की रैली गांधी मैदान में हुई है, उनसे अधिक भीड़ हमारी रैली में होगी। करीब सवा दो लाख कुर्सियां वहां सिर्फ बैठने के लिए लगवाई हैं'। हालांकि, सिंह भी इस बात से सहमत दिखते हैं कि हाल के दिनों में बिहार में जो कांग्रेस की जो स्थिति हुई वो गलत नीतियों का परिणाम थी। इसकी नीतियां ऐसी थीं कि बिहार जैसे प्रदेश में नए उद्योग नहीं आए। बिहार पिछड़ गया और जब राज्य पिछड़ गया तब यहां की सरकार भी जो काफी लंबे समय से कांग्रेस की ही थी, वो भी पिछड़ गई। बिहार कांग्रेस का कुनबा इन दिनों में बढ़ा है। टिकट की आस लिए नए-नए नेता शामिल हो रहे हैं। इस वक्त सबसे अधिक चर्चा लवली आनंद और अनंत सिंह की है, क्योंकि ये दोनों तब कांग्रेस से जुड़ने के लिए आगे आए जब दूसरी पार्टियों ने इनके नाम पर अपने हाथ पीछे कर लिए। यदि बात महागठबंधन की हो तो उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी 'हम', उपेन्द्र कुशवाहा की रालोसपा और मुकेश सहनी की वीआईपी जैसी पार्टियां शामिल हुई हैं। यहां सवाल अब सीट शेयरिंग का खड़ा होता है। क्योंकि अभी तक राजद-कांग्रेस महागठबंधन के बीच सीटों को

लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। महागठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने और कांग्रेस में नए नेताओं के आने से पुराने कांग्रेसियों में डर बन गया है। पिछली बार जब सीटों की बात आई थी तो शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह कहा गया था कि जो कम से कम तीन साल तक संगठन के लिए काम करेगा, उसी को उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जाएगा। ऐसे में वो लोग जो टिकट की आस में पिछले आठ-दस साल से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं, उनके लिए इन नए पैराशूट कैंडिडेटों के आने से नाइंसाफी होगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस में इसके पहले भी गुटबाजी की खबरें आती रही है। गुटबाजी में कई बार पार्टी टूट भी चुकी है और अखिलेश सिंह इन सारी बातों को समझते भी हैं। लेकिन, फिर भी कहते हैं, 'जो नेता हमारे साथ आ रहे हैं वो एक समय में हमारे विपक्षियों के लिए तुरुप के इक्के थे। फिर चाहे वह अनंत सिंह हों या लवली आनंद। अगर वैसे नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। इन नेताओं की छवि को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि जब उनकी पार्टी के खेवनहार बने थे, तब वो अच्छे कैसे थे? सीटों को लेकर संगठन के अंदर पनप रहे असंतोष पर अखिलेश कहते हैं, 'मुझसे अभी तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की है और असंतोष किस बात का! हमारी तो यही कोशिश है कि हम लोकसभा में अधिक से अधिक सांसद चुनकर भेजें। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता टिकट के लिए नहीं, संगठन और नेतृत्व के लिए काम करता है'। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना चाहती हैं लेकिन, वो तो तभी हो पाएगा जब उसे सीट शेयरिंग में अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी। सीट शेयरिंग के सवाल पर अखिलेश कहते हैं, 'पिछली बार हमें 12 सीटें मिली थीं लेकिन, इस बार हमें

उससे अधिक सीटें चाहिए। वजह साफ है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से हमें एक कुशल नेतृत्व तो मिला ही है साथ ही हमने जमीनी स्तर पर भी संगठन का विस्तार किया है। आपको यकीन नहीं होगा, इस रैली के लिए अकेले मैंने 250 करीब छोटी बड़ी सभाएं की हैं। हालांकि, मैं सीटों को लेकर अभी कुछ नहीं कहूंगा। रैली के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा'।

गौरतलब है कि एक तरफ बिहार में लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर खींचतान जारी है और कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी रैली में महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित कर रही है। आखिर वजह क्या है? जिस तरह से कांग्रेस ने इस रैली में अपना दमखम दिखलाया है, उससे यही लगता है कि पार्टी अपने सहयोगियों को अहसास कराना चाहती है, उनकी हैसियत दिखाना चाहती है और फिर उस आधार पर वह अपने लिए सीटों की मांग करेगी। जन आकांक्षा रैली के जरिए कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को संदेश दबी जुबां से यह संकेत भी दिया कि हमें कमतर ना आंके। क्या कांग्रेस की बिहार में सहयोगी राजद उसे सच में कमतर आंक रही है? जवाब में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव की माने तो उनका कहना है कि यहां सवाल कम और अधिक आंकने का नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है भाजपा को शासन से उखाड़ फेंकना। कांग्रेस हमारी सबसे विश्वस्त सहयोगी पार्टी रही है और हमेशा रहेगी। शीर्ष नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। बिना झंझट के सब क्लियर हो जाएगा। बहरहाल, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां पूरे दम खम के साथ जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने में लगी रही। सनद् रहे कि इस रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल की अगुवाई में मोदी सरकार को देश से उखाड़ फेंकेंगे। मोदी सरकार ने जनता को धोखा दिया है और एक भी वादा पूरा नहीं किया है।

बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते 3 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक

गांधी मैदान से सत्ता में वापसी के लिए शंखनाद किया। पटना की रैली में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आए थें। कांग्रेस की इस रैली को आगामी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार में पार्टी के जनाधार की वापसी का फैसला जहां इस रैली से हुआ, वहीं महागठबंधन के सहयोगियों संग सीटों की साझेदारी में भी कांग्रेस की हिस्सेदारी इस शक्ति प्रदर्शन से तय देखी गई। रैली में राजद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, लोजद संरक्षक शरद यादव, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी सहित वाम दलों के नेता मौजूद रहे। ध्यान रहे कि उक्त रैली में राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि लोकसभा के बाद विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। साथ ही किसानों के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 27 प्रतिशत चीनी बिहारी किसान देता था, आज 2 फीसदी दे रहा है। किसानों को अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। जेब से बीमा का पैसा लिया जा रहा है। वही नमो पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा की, नोट अच्छे नहीं लगे तो 500 और 1 हजार रुपये के नाट बंद कर दिए। महिलाओं के बचत के पैसे बैंक में जमा करवाए और जनता के पैसे निकाले। नोटबंदी दुनियां का सबसे बड़ा घोटाला है। 15 लाख नहीं दिए। किसान का अपमान किया। उद्योगपति के लिए सरकार ने हजारों करोड़ माफ किए, किसानों का नहीं किया। तीन राज्य में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया। बिहार में अब विपक्ष की सरकार आने वाली है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अपने भाषण में राहुल ने कहा कि बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेंगे। 'मैंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर नहीं खेलेगी बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेगी। तेजस्वी और लालू जी के साथ फ्रंट फुट पर खेलकर कांग्रेस छक्का मारेगी। तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी जी युवा नेता हैं, काम करके दिखाते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं और हम सब मिलकर इज्जत से, प्यार से, एक साथ लोकसभा में और उसके एकदम बाद विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं।

सनद् रहे कि बजट में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी किसानों को 17 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं।

किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपये मोदी जी ने दिए हैं। अनिल अंबानी को आप 30 हजार करोड़ रुपये देते हैं और किसान को 3.5 रुपये देते हैं और फिर ताली बजाते हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, आपने कहा था कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या किसी को नौकरी मिली? नहीं, लेकिन मैंने वादा किया था कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 10 दिनों के भीतर कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा। अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की तरह नीतीश कुमार भी वादे करने में माहिर है। नोटबंदी को दुनियां का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए राहुल ने कहा कि इसमें मोदी जी ने अमीर दोस्तों का काला धन सफेद किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश को भोजन और सूचना का अधिकार दिया। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, हम गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी राहुल गांधी ने चुटकी लिया और कहा कि मोदी की तरह नीतीश भी वादे करने में माहिर हैं, लेकिन पूरा नहीं करती। लेकिन आपसब से मेरा वादा है कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्विद्यालय का दर्जा दिया जायेगा। बिहार से हम जीत कर जाएंगे। जनता समझदार है।

बताते चले कि इस जन आकांक्षा रैली में शिरकत कर रहे मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने रैलीय भाषण में कहा कि बिहार देश का निर्माण करेगा और नौजवान अब ठेके नहीं काम चाहती है। बीजेपी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के नारे देकर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गंगा की सफाई नहीं हुई और देश के बैंक साफ हो गए। नियत साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बहुत सालों बाद बिहार आया और यहां आकर खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि पटना आकर अपनी जवानी याद आती है। मध्यप्रदेश में अत्याचार था, जनता त्राहिमाम कर रही थी। हमने एक महीने में 30 लाख किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। दूसरी तरफ इसी मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोजपुरी भाषा में रैली में 'का हाल बा'। 'बिहार, एकदम गर्दा उड़ा देल हो' से शुरू किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था खतरे में है। राहुल का मतलब, किसानों का सम्मान है, गरीबों की चिंता है। किसानों का 6 हजार करोड़ कर्ज माफ किया। 2500 रुपये क्विंटल धान खरीद रहे हैं। 80 लाख मीट्रिक टन खरीदी। किसानों की जमीन वापस कर दी। गठबंधन करके बीजेपी सरकार को भगाना है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत की मशीन को खराब कर दिया। बताते चले कि मंच पर से रैली में आयी जनता को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख खाते का नारा देकर धोखा किया गया। अगले चुनाव के लिए कांग्रेस ने किसान, नौजवान, न्यूनत्तम आमदनी का एजेंडा तय किया है। हम नरेंद्र मोदी वाली राजनीति नहीं करते। हम मन बना लेते हैं तो ऐतिहासिक कार्य करते हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले पांच साल में अरबपतियों को करोड़ों रुपये दिए। धन की कोई कमी नहीं है। जो यह चाहते हैं, हो जाता है। देश की गरीब जनता देखती रह जाती है। सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार देश के हर गरीब मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। हर गरीब के

बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डालकर दिखाएगी। सीपीआई के सचिव सत्यनारायण ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की ये रैली अहम है। फासीवाद का खतरा बढ़ गया है। विरोधियों को मारा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है बीजेपी की यही पहचान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है। वही कभी जदयू के शीर्ष नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शरद यादव आज मंच पर महागठबंधन के इस जुटान में अपनी नई पार्टी की पहचान पर उपस्थित होकर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। संविधान खतरे में है। बेकारी और बेरोजगारी हावी है। नौजवान बेवस है और हालात गंभीर है। जनता खतरे में है।

ध्यान रहे कि बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके राजद सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव लगातार केन्द्र की हर एक नीतियों पर लगातार कटाक्ष करने में पीछे नहीं दिखते और वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा आयोजित रैली के बाद कांग्रेस द्वारा राजधानी पटना में आयोजित जन आकांक्षा रैली में महागठबंधन के मजबूत युवा नेता के हैसियत से रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत किसी के बाप का देश नहीं है, जो पाकिस्तान भेज देंगे। तेजस्वी यादव बोले, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ और युवाओं को ठगा गया है। उन्होंने कहा कि काम पूछने पर सीबीआई और ईडी को पीछे लगाया जाता है। हम घबराएंगे या डरेंगे नहीं। लालू शेर हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस रिटेलर है। पीएम बनने की योग्यता राहुल गांधी में है और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए सहयोगियों को जोड़ना दायित्व है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी महागठबंधन की रैली में बाहर होने के कारण नहीं आ पाए थे। बिहार आकर राहुल गांधी ने नौजवानों को मोदी सरकार की कार गुजारी बताएंगे। हम तो पलटूराम पर ध्यान देते हैं। तेजस्वी ने कहा, भगवान राम और सीता माता स्वर्ग में बैठे हुए थे और भगवान राम को हिचकी आती है तो वह पूछती हैं कि क्या हुआ। तब राम जी बताते हैं कि लगता है चुनाव नजदीक आ गए हैं और बीजेपी उन्हें याद कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2014 में बीजेपी ने गंजों को भी कंघा बेच दिया था। उन्होंने कहा, हमारे पिता लालू प्रसाद यादव शेर है। मंच पर अगले वक्ता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी ने कहा कि दलित परिवार के साथ धोखाधड़ी हो रही है और मोदी सरकार आरक्षण पर हमला कर रही है। केंद्र सरकार दलितों के प्रति बेईमान है। अगला पीएम राहुल को बनाना है। 17 रुपये रोज किसानों को दिया जाना उनका अपमान है। विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को हटाना है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सिंह ने कहा कि राहुल जनता की आवाज हैं, देश पर राहुल झंडा फहराएंगे, पीएम बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि काला धन भी नही आया और न ही किसानों को फसल के दाम मिल रहे हैं। सनद् रहे कि मंच पर दिग्गजों के भाषण के साथ ही इस रैली का स्वागत भाषण बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा कर रहे थें। बहरहाल, 3 फरवरी, रविवार का दिन होने के कारण राजधानी पटना रैली में चार चांद लगाती दिखी, क्योंकि कांग्रेस समर्थक राज्य की जनता, जिन्हें अन्य दिन दफ्तरों में रहना होता था, वह इस दिन समय के साथ अपने नेता का भाषण सुनने ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे थे और पूरा पटना कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों से पटी हुई दिखी। हालांकि एक बात और जो कहना गलत नहीं होगा कि इस जन आकांक्षा रैली को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए मोकामा विधायक अनंत सिंह चुस्ती-फुर्ती के साथ दिखे। एक तरफ रैली के एक दिन पूर्व ही पटना के मिलर स्कूल में भोजन सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए थे, तो वही कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की रैली में विधायक अनंत सिंह के समर्थक अच्छे तादाद में गांधी मैदान पटना पहुंचे थे। साथ ही यह भी बता दें कि इस रैली को लेकर एक तरफ जहां पुलिस महकमा, खासकर वरीय पुलिस अधीक्षक पटना गरिमा मलिक मुस्तैद दिखी और सुरक्षा के मद्देनजर श्वान दस्ते की टीम को भी गांधी मैदान में उतारा गया था तथा दूसरी ओर जिला प्रशासन की कमान संभाले पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि हर एक हरकत पर नजर दौड़ाए हुए थे। रैली की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने करीब ढ़ाई हजार पुलिसकर्मी और 75 मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर रखी थी। कही भी कोई चूक न हो, इसके लिए गांधी मैदान के चारों ओर आठ एंबुलेंस और चार अग्निशमन दस्ता को भी तैनात किया गया था। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए शहर के अन्य हिस्सों में भी पुलिसबल की तैनाती कर रखी थी। इस रैली से किसी तरह की परेशानी लोगों को न हो, को लेकर डीएम कुमार रवि ने सुरक्षा

व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। भीड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश न कर जाएं, इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था किए गये थें। 41 डीएसएल मशीन भी लगाये गये थे ताकि अंदर आने वाले की पूरी तरह से जांच हो सके। इन तमाम व्यवस्था के साथ कांग्रेस और महागठबंधन ने जन आकांक्षा रैली में केन्द्र की सरकार और मोदी पर खूब दहाड़ा।

गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा सुनिश्चित पटना की गांधी मैदान में रैली होना पूर्व से तय था और इससे पूर्व कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत तब सामने आता दिखा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपनी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया। नेहरू गांधी परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा अब पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में उतर गईं है और उन्हें कांग्रेस का महासचिव नियुक्त कर पूर्वी उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है। सक्रिय राजनीति में सोनिया और राहुल गांधी ने पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए प्रियंका और सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महासचिव संगठन पद से हटाकर यह जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को सौंपी है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद प्रियंका गांधी की राजनीति में औपचारिक इंट्री हो गई है। हालांकि वे चुनावों में प्रचार में सक्रिय नजर शुरू से आती रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का तुरूप का इक्का माना जा रहा है। बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन को महासचिव बनाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बहन बहुत सक्षम और कर्मठ है। मुझे खुशी है कि मेरी बहन मेरे साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य भी युवा नेता हैं और उत्तर प्रदेश में जी जान से काम करेंगे। राहुल ने कहा कि हम युवा नेताओं से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा हमें सहयोग करने को तैयार हैं। मैं अखिलेश यादव का काफी सम्मान करता हूं। वही प्रियंका का राजनीति में सक्रिय होने से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है, कहना गलत न होगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि यह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। कांग्रेस को जब देश के कई राज्य नकार चुके हैं, ऐसे में परिवार की एक और सदस्या को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ राहुल ने प्रियंका के बारे में खुलकर कहते हुए बताया कि बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीति में आना अचानक से नहीं हुआ है क्योंकि अपने बच्चों के बड़े होने के बाद उन्होंने पार्टी में भूमिका निभाने का फैसला किया था। उन्होंने यह संवाद सत्र में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रियंका के राजनीति में उतरने के समय के बारे में फैसला कुछ वर्ष पहले किया गया था। वह बच्चों की वजह से इसमें देरी कर रही थीं। उन्होंने कहा, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। उनमें से एक विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया है। दूसरा भी बड़ा हो गया है। इसलिए, उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। प्रियंका की राजनीतिक भूमिका पर गांधी ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की है। उन्होंने कहा कि उनके और प्रियंका के बीच मजबूत रिश्ता है। हम दोनों ने काफी मुश्किल वक्त का सामना किया है। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद परिवार में राजनीतिक उतार-चढ़ाव को याद किया। राहुल ने आगे कहा कि इन घटनाओं ने हमें करीब लाया। सभी लोग सोचते हैं कि हमारे लिए सबकुछ आसान रहा है, लेकिन हमने कुछ बेहद मुश्किल हालात देखे हैं। उसने हमें एकसाथ ला दिया। उनके बीच के समीकरण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अगर हम अलग-अलग कमरों में बैठे हैं और आप हमसे एक ही सवाल पूछते हैं, तो 80 फीसदी समय आपको एक ही जवाब मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह और उनकी बहन दोनों एक-दूसरे को जगह देने में विश्वास करते हैं और जब उनके व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है तो दोनों के बीच निरंतर आदान प्रदान तथा पारस्परिकता की भावना रहती है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच काफी बातचीत होती है। सनद् रहे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बिहार सरकार के एक मंत्री के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा पर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी में बौखलाहट क्यों है?

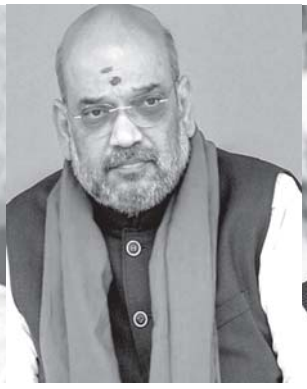
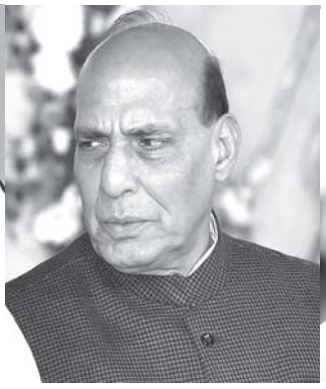

पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा, मैं किसी भी घटिया टिप्पणी को अपनी प्रतिक्रिया से सम्मान नहीं दे सकता। ऐसी बातें शायद प्रधानमंत्री को अच्छी लगें। इस पर प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को बोलना चाहिए कि क्या वे ऐसी घटिया टिप्पणियों का अनुमोदन करते हैं? देश ये जानना चाहता है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश में लाने से भाजपा वाले घबराए हुए हैं। राहुल ने कहा, मैंने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिशन दिया है कि वे राज्य में कांग्रेस की सच्ची विचारधारा, गरीबों और कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको आगे लेकर बढ़ने की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में नए तरीके की सोच आएगी और राजनीति में सकारात्मक बदलाव आएगा। कांग्रेस अधयक्ष ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वह कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है।

उल्लेखनीय है कि प्रियंका को कांग्रेस महासचिव नियुक्त करने के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा, हम कहीं भी बैकफुट पर नहीं खेलेंगे। हम राजनीति जनता के लिए, विकास के लिए करते हैं। जहां मौका मिलेगा, हम फ्रंटफुट पर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वे बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव का पूरा आदर करते हैं। कांग्रेस और सपा-बसपा की विचारधारा में काफी समानताएं हैं। हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि सपा और बसपा के साथ हमारा जहां भी सहयोग हो सकता है, हम करने को तैयार हैं। जहां भी हम भाजपा को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, करेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है। हमने यह जगह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन, जो बहुत कर्मठ है, अब मेरे साथ काम करेगी। ज्योतिरादित्य भी ऊर्जावान युवा नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को, युवाओं को, किसान को कहना चाहते हैं कि आपने बहुत समय जाया किया। आपने यहां भाजपा की सरकार बना रखी है। पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। राहुल ने जनता का आहवान करते हुए कहा, आप भाजपा को हटाइए। हम आपको नई दिशा देंगे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर-वन प्रदेश बने। म[illegible] किसी जाति-धर्म की बात नहीं करता। यहां के युवाओं ने अपने प्रदेश को देखा है कि किस प्रकार इसे नष्ट किया गया है। हम आपके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहते हैं। कांग्रेस अधयक्ष ने यह भी कहा कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश में लाने से भाजपा वाले घबराए हुए हैं। हालांकि अभी तक प्रियंका केवल सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में ही सक्रिय रही हैं लेकिन, माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का राजनीति में आना एकाएक नहीं हुआ है। कांग्रेस की खस्ताहाल हालत को सुधारने के लिए कांग्रेसी हमेशा से ही प्रियंका जैसे करिश्माई चेहरे को लाने की मांग करते रहे हैं। अपनी दादी से मिलती-जुलती प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस के लगभग हर नेता-कार्यकर्ता की रही है लेकिन पूर्वी यूपी की कमान मिलने के बाद एक बार फिर चर्चा गर्म है कि वे रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से उनके चुनाव लड़ने पर संशय है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी नेता लगातार कह रहे हैं कि अगर सोनिया चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा। उनके करिश्मे पर कांग्रेस अध्यक्ष और उनके भाई राहुल को भी पूरा विश्वास है। देखना अब यह है कि परदे के पीछे से राजनीति में दखल रखने वाली प्रियंका गांधी राजनीति के पर्दे पर कितनी सफल हो पाती हैं।

यकीनन उनमें इंदिरा गांधी क[illegible]

अक्स दिखता है, धीरे और नापतौल कर बोलना, पहनावा भी वैसा ही सादगी भरा। वक्ता के रूप में भी गजब का संवाद, बिना समय गंवाएं कुछ इस कदर घुलना-मिलना जैसे अपनों के ही बीच में हों, बरसों से जानती हों। हिन्दी में जितनी गब की महारत ठेठ उतना ही मजाकिया लहजा भी। अनजान महिला से भी गले मिल हाथ पकड़कर कुछ यूं पेश आना जैसे पुरानी पहचान हो। यही करिश्माई व्यक्तित्व प्रियंका गांधी को कभी गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी सा दिखने को मानने पर मजबूर करता है। प्रियंका की यही शख्सियत और लोकप्रियता सत्ता संघर्ष के लिए जूझ रहे दावेदारों के लिए कवच है। भाजपा तो परिवारवाद की आड़ में खुलकर वार कर रही है लेकिन सपा, बसपा ने मजबूरन ही सही चुप्पी ही साध रखी है। हालांकि प्रियंका को कांग्रेस महासचिव बनाकर राजनीति में एकाएक लाने का फैसला सबके लिए चौंकाने वाला रहा हो पर हकीकत यह है कि इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा चुकी थी और इंतजार सही वक्त का था। जैसे ही उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा का गठबंधन हुआ और कांग्रेस को दरकिनार रखा गया तो राहुल ने भी मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रियंका का नाम आगे कर छक्का जड़ दिया। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि या तो अध्यक्ष या प्रभारी बदला जाएगा। लेकिन उनके एक तीर ने कई निशाने साधे। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका को दी। इससे जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान फुंकी, वहीं पूरे देश में राहुल की राजनीतिक परिपक्वता पर शक करने वालों को भी बैकफुट पर ला खड़ा किया। यकीनन प्रियंका की यह सक्रियता उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर खास असरकारक होगी, जो कांग्रेस के लिए संजीवनी है। प्रियंका की क्षमता और कार्यशैली पर भी कोई संदेह नहीं है। सूत्रों की माने तो वे बताते हैं कि महज 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। जब भी मां या भाई के संसदीय क्षेत्र गईं, उनका दिन सुबह दिन सुबह छह बजे ही शुरू होता। थोड़ी सी कसरत, योग के बाद वह अपने मिशन पर निकल पड़तीं। रोटी या परांठे ही खातीं, वह भी सब्जी और नींबू या आम के अचार के साथ। चुनावी प्रचार की शुरुआत प्रियंका ने रायबरेली से 2004 में की थी और बतौर मेहमान रमेश बहादुर सिंह के घर पर पूरी सादगी से एक महीने ठहरीं। वो अपने पिता राजीव गांधी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र बचपन से आती रहीं। उनके छोटे-छोटे बालों के चलते उन्हें भइया कहा जाता था, जो बाद में भइयाजी हो गया। यादाश्त की तगड़ी प्रियंका कार्यकर्ताओं को खूब पहचानती और याद रखती हैं। यह भी उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है।

गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की मजबूती तय है पर कितनी यह देखने वाली बात होगी क्योंकि पार्टी का परंपरागत मतदाता इधर-उधर छिटक हुआ है। कई क्षेत्रीय दलों ने जबरदस्त पैठ बना ली है। संगठन खुद मजबूत नहीं है। प्रियंका को नजदीक से जानने वाले यह बताते हैं कि उनकी सहजता, प्रभावी व्यक्तित्व, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव की खूबी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने में मददगार होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार भी बहुत ही सोची, समझी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। आबादी के लिहाज से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनकर, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित-पिछड़ों की संख्या बहुत है, जो प्रियंका के निजी प्रभाव के चलते फिर से कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। इंदिरा जी ने भी हमेशा उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा भरोसा कर ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य बनाया। ऐसे में उत्तर प्रदेश को जानने वालों का मानना है कि वहां के लोगों का आज भी नेहरू-गांधी परिवार से खासा लगाव है। प्रियंका भी बहुत कुछ इंदिरा जी जैसी लगती हैं। इसका प्रभाव मतदाताओं पर न पड़े, यह नामुमकिन है। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चल पड़ी है कि काऊ बेल्ट के ब्राम्हण उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और दूसरे हिन्दी क्षेत्रों के क्षेत्रों में बहुतायत हैं जो नेहरूजी को असली ब्राम्हण मानते हैं। यदि इनका झुकाव प्रियंका की तरफ हुआ तो नुकसान भाजपा का ही होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने की बात के बावजूद साफ कर दिया है कि सपा-बसपा गठबंधन से कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति में कांग्रेस को अछूत मानना जल्दबाजी होगी। विडम्बना देखिए कि प्रियंका की सक्रियता और कुछ निजी चैनलों का सर्वे साथ-साथ आना भले ही संयोग रहा हो, लेकिन इसने 2019 के आम चुनाव का बड़ा संकेत जरूर दे दिया है। हो सकता है कि अब आने वाले सर्वे प्रियंका के चलते कांग्रेस की और मजबूती का दावा करें कुछ और आंकड़ें दें। किन्तु प्रियंका की राजनीति के मैदान में एंट्री ने एक बार फिर राजनीति को नया मोड़ जरूर दे दिया है और इस दबी हुई सुनामी अपना प्रभाव बिल्कुल डालेगी, पर कितना यह नहीं कहा जा सकता। हालांकि प्रियंका की इंट्री ने मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को खोखला जरूर कर दिया है। इतना तो तय है कि सत्ता के ताले की फिर कई चावी होंगी और देखना बस यही है कि अगले आम चुनाव में प्रियंका का जादू मोदी के मैजिक पर कितना असर डालेगा। बहरहाल, लोकसभा चुनाव होने के लगभग दो-तीन महीने बच गये हैं और कांग्रेस सहित महागठबंधन की सारी दलें एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन की विगुल फूंक चुकी है तथा पश्चिम बंगाल के बाद बिहार की राजधानी पटना के एतिहासिक गांधी मैदान में जन आकांक्षा रैली ने भाजपा को प्रभावित जरूर किया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता किन्तु रेस तो शुरू हुई है और रैलियों के दौर में अगले माह भाजपा सह एनडीए द्वारा आयोजित रैली अनुमानित है और जनता का रूझान इन दोनो दलों के बीच किस तरफ का होता है यह तो चुनावी परिणाम स्पष्ट करेगा, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस में अचानक प्रियंका के शक्ल में आयरन लेडी इंदिरा गांधी को लांच किया गया है, जिससे यह चुनावी घमासान 2014 के आम चुनाव से कही ज्यादा कांटे भरा टक्कर माना जा सकता है। ●

जंजीरों से बांध दी हांथों को फिर भी न तोड़ पाये हौसला समाजवाद का

● अमित कुमार

एक ऐसे नेता जो अपने जीवनकाल में लेखक और पत्रकार भी रहे और राजनीति में अमित छाप छोड़ने वाले समता पार्टी के संस्थापक के तौरपर एनडीए के संयोजक बने। उनकी कार्यकुशलता से वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई मंत्रालयों में मंत्री भी रहे, उस महान शख्स का बीते 29 जनवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया। वह शख्स कोई और नहीं पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हैं।

गौरतलब है कि जॉर्ज साहब का जाना हमारी मौजूदा राजनीति के एक दौर का अंत है। इस नेता, पत्रकार और लेखक के लिए चालीस साल से ज्यादा समय उनकी धारा की वैचारिक राजनीति में कभी प्रेम, कभी लड़ाई करने के बाद उनका जाना यह काफी कुछ निजी नुकसान भी लगता है। पर, जिस हालत में वे पिछले कई वर्षों से पड़े थे, वह उनकी शख्सियत के हिसाब से जमाना लग रहा है, वरना जॉर्ज जिंदा हों और इतने वर्ष कुछ बड़ा न हो यह असंभव था। कर्नाटक के एक पादरी परिवार के इस व्यक्ति ने परिवार से, समाज से बगावत करके ही समाजवादी राजनीति शुरू की, वह भी

मुंबई में और सीधे एस. के. पाटिल से भिड़े और धूल चटा दी। जॉर्ज तब क्या रहे होंगे, इसकी एक झलक तब भी दिखी जब इंदिरा गांधी रायबरेली से हारने के बाद कर्नाटक के बेल्लारी से उपचुनाव लड़ने गईं और जॉर्ज साहब ने विपक्ष का अभियान संगठित किया। मुंबई में जमने और राजनीति जमाने के तो अनगिनत किस्से हैं, पर यह सब उनकी दिलेरी, समझ, जबरदस्त भाषण कला और समाज के लिए कुछ करने की जबरदस्त इच्छाशक्ति से संभव हुआ। वे चुनाव लड़ने मुंबई नहीं गए थे, उनको ट्रेड यूनियन करना था और सारे स्थापित दलों–जिनमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस से जुड़े यूनियनों के बीच उन्होंने न सिर्फ अपना झंडा गाड़ा बल्कि टैक्सीमेंस यूनियन के लिए बैंकिंग, सरकारी दुकान और गाड़ियों के मेंटेनेंस की सरकारी व्यवस्था शुरू की। मुम्बई की टैक्सी सेवा और टैक्सीवालों का संगठन आज भी सबसे अलग है। जार्ज साहब के यूनियन पॉलिटिक्स का असली रंग रेलवे मजदूरों के बीच और 1974 की देशव्यापी हड़ताल में दिखा, जिसने सबसे ज्यादा असर डाला 'आयरन लेडी' इंदिरा गांधी पर। उसके बाद से आज तक 45 वर्षों में फिर वैसी

कोई हड़ताल नहीं हुई और जब जॉर्ज साहब की टोली ने उसी इंदिरा से लड़ाई में मुल्क को गरमाने के लिए बम की पॉलिटिक्स (जैसा समाजवादियों ने 1942 में किया था) करनी चाही तो उन्हें और उनके साथियों को बड़ौदा डायनामाइट केस में उलझाया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, सख्त जेल हुई, जंजीरों में जकड़े गए, पर जॉर्ज जेल से ही चुनाव जीते। जंजीरों में जकड़े जार्ज की तस्वीर ने कांग्रेस के एक और दिग्विजयी को तीन लाख से ज्यादा वोटों से परास्त कर दिया। वे अपने परिचित मुंबई, बैंगलुरु या दिल्ली से नहीं सुदूर बिहार के मुजफ्फरपुर से लड़े और जीते भी।

सनद् रहे कि घनघोर जातिवादी राजनीति (पहले राजपूत बनाम भूमिहार और बाद में अगड़ा बनाम पिछड़ा) का अखाड़ा जॉर्ज का अपना बन गया, जबकि वहां 10-20 क्रिश्चियन वोट भी नहीं होंगे। वह उनका नया ठिकाना बना जो आखिरी तक मन में बसा रहा और कमजोर होकर भी वे वहीं लड़े, जमानत जब्त कराई पर मुजफ्फरपुर का मोह नहीं छोड़ा। बताते चले कि जॉर्ज जब जनता पार्टी की राजनीति में विभाजन के समय मोरारजी सरकार के बचाव में जबरदस्त भाषण देने के बाद चरण सिंह के पक्ष में जा रहे थे, तब दिल्ली में उनके आवास के गेट पर 100 से ज्यादा समर्थकों ने धरना दिया। इनमें प्रो० रजनी कोठारी, धीरुभाई सेठ, सच्चिदानन्द सिन्हा, विजय प्रताप जैसे लोग थे। कोठारी साहब जनता पार्टी का घोषणा पत्र लिखने वालों के साथ एजेंडा फॉर इंडिया नाम से एक संवाद सिरीज चला रहे थे। सच्चिदा बाबू जार्ज के मुंबई के दिनों के दोस्त होने के साथ मुजफ्फरपुर से उनको चुनाव लड़ाने वाले शख्स थे और वही उनके चुनाव एजेंट थे। जॉर्ज कई बार उसी दरवाजे से आए-गए लेकिन

किसी से दुआ-सलाम नहीं, किसी को पानी के लिए भी नहीं पूछा। हालांकि जॉर्ज ऐसे न थे। उनके यहां तो गुरुजी जैसा साथी या पात्र रहता था, जो खाता-पीता रहता था। वहाँ और दिन भर मजे से जॉर्ज की आलोचना करता था। उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में विनोदानन्द प्रसाद सिंह, शरद राव, विजय नारायण और चंचल भी थे जिन्हें जॉर्ज की भक्ति से परहेज रहा। पर, साफ लगता है कि जॉर्ज यहीं से अपने लिए लोगों की राजनीति को नीचे करके सत्ता की राजनीति को ऊपर ले आए। कोई वंशवाद नहीं किया, कोई साम्राज्य नहीं बनाया, स्विस बैंक का खाता नहीं खोला, हत्या/दंगा नहीं कराया, बेटा-बीबी को आगे नहीं किया। लेकिन, सत्ता की चिंता ऊपर हो गई। यूनियन का काम, संसद के अंदर का काम, लोगों के बीच जाने का काम, मुल्क की राजनीति के जरूरी मुद्दे पहचानकर लड़ने-भिड़ने का काम अब पीछे चला गया। शायद सत्ता से ही सामाजिक बदलाव का भरोसा हो गया हो और इस खेल में भी जॉर्ज खूब खेले। वही ज्ञात हो कि चरण सिंह को आगे करके लोक दल की राजनीति की तो भाजपा से हाथ मिलाकर उसका अछूतपना दूर किया। भाजपा को दो सीटों से बढाकर सत्ता तक लाने में जॉर्ज का उनके बनाए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का कितना बड़ा हांथ है, यह इतिहासकार तो तय करेंगे ही साथ ही अभी की राजनीति के भी काफी लोग बता देंगे।

गौरतलब हो कि पूर्व रक्षामंत्री एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस सबसे पहले 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर और नालंदा लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व किया था। विदित हो की वे कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने संचार, उद्योग, रेलवे और रक्षामंत्री के तौरपर अपनी सेवाएं दी। अल्जाइमर यानी स्मृतिलोप की बीमारी से पीड़ित फर्नांडिस

को कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू हो गया था। कर्नाटक के मंगलोर के रहने वाले फर्नांडिस आपातकाल का विरोध करने वाले अग्रणी नेताओं में से एक थे। 3 जून 1930 को मैंगलोर के मैंग्लोरिन- कैथोलिक परिवार में जॉन जोसफे फर्नांडीस के घर जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मैंगलौर के स्कूल से पूरी की। इसके बाद मैंगलौर के सेंट अल्योसिस कॉलेज से अपनी 12वीं कक्षा पूरी की। सनद् रहे कि जॉर्ज अपने भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। परिवार के नजदीकी सदस्य इन्हें गैरी कहकर बुलाते थे। वही घर के पारंपरिक रिवाज के कारण जॉर्ज को 16 वर्ष की आयु में बैंगलोर के सेंट पीटर सेमिनरी में धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा गया। 1949 में जॉर्ज मैंगलोर छोड़ मुंबई काम की तलाश में आ गए। मुंबई में इनका जीवन काफी मुश्किलों में बीता। एक समाचार पत्र में प्रूफरीडर की नौकरी मिलने से पहले वे फुटपाथ पर रहा करते थे और चौपाटी स्टैंड की बेंच पर सोया करते थे लेकिन रात में ही एक पुलिसवाला आकर उन्हें उठा देता था, जिसके कारण उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। 1950 में जॉर्ज सामाजिक कार्यकर्ता राममनोहर लोहिया के करीब आए और उनके जीवन से काफी प्रभावित हुए। उसके बाद वे सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन के आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में उन्होंने मजदूरों, कम पैसे में कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों तथा होटलों और रेस्तरांओं में काम करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठाई। इसके बाद वे 1950 में मजदूरों की आवाज बन गए। बाद के दिनों में जॉर्ज 1961 तथा 1968 में मुंबई सिविक का चुनाव जीतकर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य बन गए। इसके साथ ही वे लगातार निचले स्तर के मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए आवाज उठाते रहे और राज्य में सही तरीकों से कार्य करते रहे। इस तरह के लगातार आंदोलनों के कारण जॉर्ज नेताओं की नजर में आ गए। 1967 के लोकसभा चुनाव में उन्हें संयुक्त सोशियल पार्टी की ओर से मुंबई साउथ की सीट से कांग्रेस के सदाशिव कानोजी पाटिल के खिलाफ टिकट दिया गया। जॉर्ज ने उस चुनाव में पाटिल को 48.5 फीसदी वोटों से हरा दिया, जिसके कारण उनका नाम 'जॉर्ज द जेंटकिलर' रख दिया गया। पाटिल को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने राजनीति छोड़ दी। 1960 के बाद जॉर्ज बॉम्बे में हड़ताल करने वाले लोकप्रिय नेता बने। इसके बाद राजनीति में बहुत बदलाव आया और 1969 में वे संयुक्त सोशियल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चुन लिए गए और 1973 में पार्टी के चेयरमैन बने। 1974 में जॉर्ज ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय रेलवे के खिलाफ हड़ताल शुरू की। वे 1947 से तीसरे वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे और आवासीय भत्ता बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। इस हड़ताल में देश के विभिन्न हिस्सों से आए रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, वहीं राज्य के टैक्सी चालकों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया। लगभग 30 हजार लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों का समर्थन रेलवे के लिए काफी मुसीबत बन गया। 27 मई 1974 को हड़ताल को खत्म कर दिया गया। इसके बाद जॉर्ज ने बताया की हड़ताल को खत्म करने का कारण यह रहा कि इसमें अलग-अलग आवाजें उठने लगी थीं। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और उसका विरोध करने वालों को जेल में भर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी दूसरों की तरह इसका विरोध किया तो इनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, जिससे बचने के लिए वे अंडरग्राउंड हो गए, मगर पुलिस ने उनके भाई को गिरफ्तार कर उन्हें आत्म-समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 10 जून 1976 को जॉर्ज कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिए गए। इनके गिरफ्तार होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल मेंबर ने सरकार से अनुरोध किया कि इन्हे तुरंत एक वकील दिया जाए और इनकी जान की गारंटी ली जाए। विश्व के तीन देशों जर्मनी, नॉर्वे तथा ऑस्ट्रेलिया के नेता मानते थे, कि इंदिरा गांधी जॉर्ज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके बाद जॉर्ज को बड़ोदरा जेल से तिहाड़ जेल लाया गया और इनके ऊपर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।

बताते चले कि 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ और इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने चुनाव जीता।

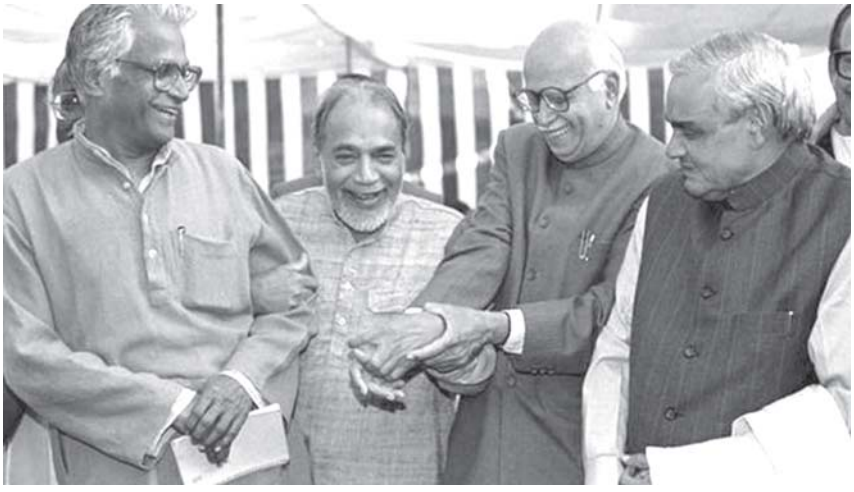

जॉर्ज फर्नांडीस भी जेल में रहते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत गए। इसके बाद वे जनता पार्टी की सरकार में इंडस्ट्री मंत्री बने। इसी दौरान दो अंतरर्राष्ट्रीय कंपनियों आईबीएम और कोका कोला द्वारा फेरा लागू करने को लेकर विवाद हो गया। फेरा के अंदर विदेशी कंपनियां 40 फीसदी से ज्यादा शेयर भारत को देने को तैयार नहीं थीं और दो कंपनियां तो अपनी सेवाएं भारत में बंद करने का निर्णय ले चुकी थीं, वहीं फर्नांडीस उनसे फेरा के शेयर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जॉर्ज 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से फिर से जीत गए और 1984 में बैंग्लौर नॉर्थ से कांग्रेस प्रत्याशी से हारने के बाद पुन: अपनी पुरानी लोकसभा सीट पर चले गए। 1989 में वे पुरानी सीट से जीत गए, जिसके बाद वे जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी दौरान वे वीपी सिंह की सरकार में कुछ सालों के लिए रेलमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने मैंगलोर और मुंबई को जोड़ने के लिए कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट भारतीय स्वतंत्रता के बाद से रेलवे के विकास के लिए पहला प्रोजेक्ट था। 1998 के चुनाव में वाजपेयी सरकार पूरी तरह सत्ता में आये और उसी दौरान एनडीए का गठन हुआ और जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक बने। 1999 में जनता पार्टी दो भागों में बंट गई जिसमें से जनता दल यूनाटेड तथा जनता दल सेक्युलर बनी। जॉर्ज जदयू के साथ हो गए और अपनी समता पार्टी को जदयू में मिला दिया। जॉर्ज एनडीए की सरकार में दोनों बार रक्षामंत्री बने। इनके रक्षामंत्री रहते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी हथियारों का प्रयोग किया गया। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' के दौरान पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष के साथ मीडिया ने सरकार पर इस युद्ध के पीछे खुफिया विभाग की नाकामी बताकर सरकार की खिंचाई की, मगर जॉर्ज ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया।

ज्ञात हो कि 2001 में तहलका रक्षा घोटाले के बाद जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में वे पुन: रक्षामंत्री बने। जॉर्ज फर्नांडिस पहले ऐसे रक्षामंत्री रहे, जिनके कार्यालय में हिरोशिमा बमबारी का चित्र था। वे 18 बार कश्मीर के सियाचिन गए हैं, जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई। कुछ समय बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि पार्टी में जॉर्ज का समता पार्टी के सह संस्थापक नीतीश कुमार के साथ मतभेद हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में वे जदयू के टिकट को छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुजफ्फरपुर से लड़े, मगर हार गए। 30 जुलाई 2009 को शरद यादव द्वारा सीट छोड़ने के बाद जॉर्ज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। जदयू ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। फर्नांडिस ने बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया। इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे, जिसमें आपातकाल के दौरान विदेशी संस्थाओं से पैसे लेकर इंदिरा गांधी का विरोध करना और अंडरग्राउंड होना, रक्षामंत्री रहने के दौरान तहलका कांड, 2000 में इसराइल से बैरक-1 की खरीद में 7 मिलियन डॉलर का घोटाला और पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद चीन को युद्ध के लिए भड़काने का आरोप लगाया गया। खैर! आज जॉर्ज साहब नहीं है किन्तु उनकी चर्चा हमेशा होते रहेगी। फिलवक्त पूरी राजनीति नम आँखों से उन्हें विदाई दे रही है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाजवादी नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि वे गरीबों एवं वंचितों के अधिकारों की सर्वाधिक प्रभावी आवाज थे। मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि जॉर्ज साहब भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक थे। बेबाक एवं निर्भीक, बेलागलपेट एवं दूरदर्शी फर्नांडिस ने हमारे देश के लिए अमूल्य योगदान दिया। वे गरीबों एवं वंचितों के अधिकारों की सर्वाधिक प्रभावी आवाजों में से एक थे। उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि जब हम जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में सोचते हैं, हम एक बहुत असरदार मजदूर नेता के रूप में उन्हें याद करते हैं, जो न्याय के लिए लड़ा, वे एक ऐसे नेता थे जो शक्तिशाली से शक्तिशाली राजनीतिज्ञों को झुका देते थे, वे एक विजनरी रेलमंत्री और एक महान रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने भारत को सुरक्षित एवं ताकतवर बनाया। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में फर्नांडिस अपनी राजनीतिक विचारधारा से तनिक भी नहीं विचलित हुए। उन्होंने आपातकाल का प्राणपण से विरोध किया। उनकी सादगी एवं विनम्रता अनुकरणीय है। मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं दिवंगत नेता के परिजनों, मित्रों एवं लाखों चाहने वालों के

साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो।

गौरतलब हो कि समता पार्टी के समय से लेकर जनता दल युनाइटेड के गठन में जॉर्ज फर्नांडिस के कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाले बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जॉर्ज साहब के निधन से काफी दुख पहुंचा है। भले ही विचारधारा में अंतर होने के बाद खुद को जदयू से जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग कर लिया हो और एक लंबे समय के लिए बिमारीवश राजनीति से दूर रहे हो किन्तु जिस जनता दल युनाइटेड की ईंट रखी गई थी, इसमें जॉर्ज और नीतीश का सहयोग सर्वविदित है और आज जॉर्ज साहब के निधन के बाद गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए रो पड़े। मुख्यमंत्री ने अपने जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कहा कि देश ने बड़े राजनीतिक शख्सियत के साथ ही प्रखर वक्ता, चिंतक, विचारक और करिश्माई व्यक्तित्व को खो दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता तथा पत्रकार थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने उच्च राजनीतिक मूल्यों एवं आदर्शों की बदौलत सार्वजनिक जीवन में उच्चस्थ शिखर को प्राप्त किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की बदौलत राजनीतिक सीमाओं के परे सभी विचारधारा के राजनीतिक दलों का आदर एवं सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने हमेशा साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुये कहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस के निधन से उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया है।

बहरहाल, एक लेखक, पत्रकार और समाजवादी नेता की याद लुप्त व्यक्ति की पहचान ने मृत्योपरांत दिला ही दी। किन्तु उनकी राजनीति ने देश पर जो प्रभाव डाला था, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। गौर फरमाये की अगर जॉर्ज न होते तो एनडीए न होता, अटल बिहारी की सरकार न बनती। भाजपा को कोई राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड से दूर न करता। हो सकता है भाजपा नेतृत्व भी यह चाहता हो और जार्ज ने बहाना उपलब्ध करा दिया हो, लेकिन यह हुआ है। इस दौर में जार्ज साहब ने अपनी पुरानी पत्रिका 'प्रतिपक्ष' को लगातार निकाला, बर्मा के आंदोलनकारियों, तिब्बत के आंदोलनकारियों, श्रीलंका में मानवाधिकार हनन के सवाल को, पूर्वोत्तर के बागी गुटों को उनका समर्थन जारी रहा। बंगले का एक कमरा भर उनका अपना होता था, बाकि सब ऐसे ही जमातों और साथियों का रहता था। पर, बदले जॉर्ज का असर साफ दिखने में वक्त नहीं लगा। किन्तु सवाल यह है कि आजाद भारत की राजनीति में ऐसा दूसरा कौन हुआ जो पादरी परिवार में जन्म लेकर समाजवादी हुआ, घर से निकलकर कई-कई बार पूरे देश को हिलाने या रोक देने वाला बना, सरकार बनाया-गिराया, पार्टी बनाई-तोड़ी? शायद दूसरा जॉर्ज मौजूदा राजनीति में मिल पाना असंभव है? ●

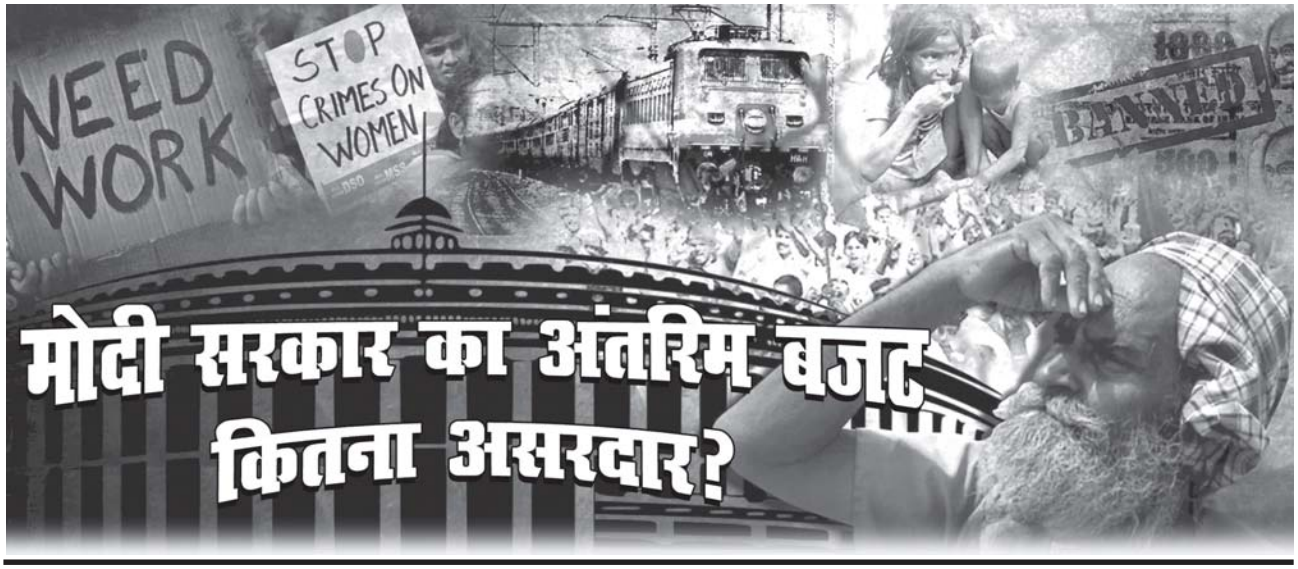

मोदी सरकार का अंतरिम बजट कितना असरदार?

● अमित कुमार

दुनियां में जितने भी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ही निर्धारित करती है कि वह विकास किस प्रकार करे और कैसे करें? इसके मद्देनजर बजट का बनना अति आवश्यक होता है। उल्लेखनीय है कि जहां लोकतंत्र है, वहां पर बजट बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें जनता उन अर्थशास्त्री नेताओं के आका होते हैं और वह उनके बजट से निर्णय लेते हैं कि वह कितने हितकर हैं जनता के लिए। इस कड़ी में लोकतंत्र की जननी कहा जाने वाला भारत देश भी जो प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के प्रारंभी में अपना आर्थिक बजट प्रस्तुत करता है। बताते चले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य-दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। 2016 से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य-दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरूआत, अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा इसे पारित करना आवश्यक होता है। सनद् रहे कि अंतरिम बजट होता क्या है को समझना आवश्यक है। आइए जानते हैं अंतरिम बजट से जुड़ी खास बातें और आम आदमी पर इसका किस तरह असर होगा.....।

ज्ञात हो कि जब केंद्र सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने के लिए समय नहीं होता है तो वह अंतरिम बजट पेश करती है। भारत में लोकसभा चुनाव के समय सरकार के पास परंपरा के मुताबिक चुनाव पूरा होने तक के समय के लिए बजट पेश करती है। यह पूरे साल की बजाय कुछ महीनों तक के लिए ही होता है और इसमें चुनाव तक देश चलाने के लिए खर्चे का इंतजाम किया जाता है। नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है। हालांकि, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार पूर्ण बजट भी पेश कर सकती

है। हालांकि अंतरिम बजट में भी आम बजट की तरह ही संसद से मंजूरी ली जाती है लेकिन यह आम बजट से अलग हो जाता है। इसमें सामान्यत: कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जाता। चुनाव के बाद गठित सरकार ही अपनी नीतियों के मुताबिक फैसले लेती है और योजनाओं की घोषणा करती है।

गौरतलब हो कि भारतीय गणराज्य का कार्यभार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हांथों में है और जैसा की सभी को पता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम वर्ष है। इसके मद्देनजर मोदी सरकार ने 1 फरवरी को संसद में अपने पहले कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। यह सर्वविदित है कि लोकसभा का चुनाव जल्द ही होना है, ऐसे में कहा जा रहा है कि यह अंतरिम बजट होगा। तकनीकी रूप से अंतरिम बजट चुनावी साल में कुछ वक्त तक देश को चलाने के लिए खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष का अंतरिम बजट वित्त मंत्री अरूण जेटली करते आये हैं किन्तु अस्वस्थ होने के कारण इस बजट को उनका कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया है। सनद् रहे कि बजट पेश करने के पूर्व कयास लगाये जा रहे थें कि इस साल आम चुनाव होने वाले हैं और यह बजट उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चर्चाएं यह भी रही कि सरकार वोटरों को लुभाने के लिए परंपरा के विपरीत पूर्ण बजट पेश कर सकती है। दरअसल हर चुनावी साल में केवल शुरुआती चार वित्तीय महीनों का बजट पेश किये जाने की परंपरा रही है, इसिलिए इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। नई सरकार के गठन के बाद बाकी वित्त वर्ष के लिए पूरक बजट पेश किया जाता है। हर बजट पेश करने के दौरान कुछ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जाने बगैर आप बजट को अच्छी तरह नहीं समझ पायेंगे।

गौरतलब हो कि सरकार की कुल सालाना आमदनी के मुकाबले जब खर्च अधिक होता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसमें कर्ज शामिल नहीं होता। साल 2017 में बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि साल 2017-18 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.2 फीसदी होगा। ये इसके पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 3.5 फीसदी से कम था। हालांकि विशेषज्ञों की चिंता थी कि ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा कम होने के बजाय बढ़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि बजट लोकलुभावन होगा, जिसमें आने वाले चुनावों के लिहाज से मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार अधिक खर्च की घोषणा करेगी और टैक्स की सीमा में भी बदलाव कर सकती है। दूसरी ओर पूर्व में ढ़ाई लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इस सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत निवेश पर दी जाने वाली करमुक्त आय की सीमा को भी 1।5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख किये जाने की संभावना जताई जा रही थी। सरकार इसका आधार यह बता सकती है कि आरक्षण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को माना जा रहा है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये हैं, ऐसे में इतनी ही कमाई करने वाले नौकरी-पेशा लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अंतरिम बजट के लिए प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर को समझना भी जरूरी है, जिसमें प्रत्यक्ष कर वो हैं जो देश के नागरिक सरकार को सीधे तौर पर देते हैं। ये टैक्स इनकम पर लगता है और किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स आते हैं। अप्रत्यक्ष कर वो हैं जो किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर किये जा सकते हैं, जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट या सेवा पर लगने वाला टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है जिसने वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे अलग-अलग टैक्स की जगह ले ली है। यहां एक बात और समझना होगा कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति यदि शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पैसे लगा कर लाभ कमाता है तो उसे अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) पूंजीगत लाभ कहते हैं। इस पर 15 फीसदी तक टैक्स लगता है। शेयरों में जो पैसा एक साल से अधिक समय के लिए होता है उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (लॉंग टर्म कैपिटल गेन) कहते हैं। पहले इस आय पर टैक्स नहीं देने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2018-19 के बजट में इस पर 10 फीसदी टैक्स का प्रावधान किया है। हालांकि, यह टैक्स सिर्फ 1 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर ही देना होगा। एक लाख से कम की कमाई पर किसी तरह का लॉंग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगाया गया है। इसके तहत ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि सरकार लॉंग टर्म कैपिटन गेन की समय-सीमा में बदलाव कर सकती है।

बहरहाल, विशेषज्ञों के अनुमानित संकेत जो पहले बताये गये थे, वह बजट पारित होने के बाद लगभग स्पष्ट ही दिखा। साथ ही यह भी बता दें कि हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस ने किसानों के हित में कर्जमाफी जैसे ट्रंप कार्ड को खेलकर अपनी जीत सुनिश्चित की है, उसके काट का जुगाड़ नरेन्द्र मोदी ने किसान कैश कार्ड से खेलने की शुरूआत की है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के अंतिम बजट में देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को हर महीने 500 रुपए नकद देने की योजना लाई गई है। किसानों के खाते में सीधे जाने वाली इस राशि में सरकार हर साल प्रत्येक किसान को 6000 रुपए कैश देगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के लोकलुभावन बजट में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि किसानों के खाते में छह हजार रुपए हर साल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से दिसंबर 2018 से शुरू होने जा रही इस योजना के तहत मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक किसान को पहली किश्त के रूप में दो हजार रुपए देने का प्लान तैयार किया है। सरकार के इस प्लान के तहत के 31 मार्च तक हर किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को साल में दो-दो हजार रुपए तिमाही के तौर पर दिए जाएंगे। देश के दो हेक्टेयर से कम जोत वाले करीब बारह करोड़ किसानों को प्रधान किसान सम्मान निधि का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को बड़ी सौगात देते हुए मोदी सरकार ने किसान केडिट स्कीम के तहत उन्हें दो प्रतिशत छूट देने का भी ऐलान किया है। मोदी सरकार की किसानों को दी जाने वाली इस बड़ी सौगात को कांग्रेस के कर्जमाफी की काट के रूप में देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसानों की कर्जमाफी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में देशभर के किसानों के लिए कर्जमाफी का दांव चला सकती है। 8 फरवरी को भोपाल में होने वाली किसान आभार सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वहीं अब मोदी सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस के सामने अपने कर्जमाफी के वादे को धरातल पर

लाना बड़ी चुनौती होगी।

बताते चले कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में दूसरी बार मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पहली बार बजट पेश किया है। जैसा की पहले हमने बताया कि यह नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। बजट पेश करते हुए गोयल ने 'प्रधानमंत्री किसान निधि' की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ही संसद में जय किसान के नारे लगने लगे। गोयल ने कहा कि अब हर किसान के खाते में सीधे 6 हजार रुपए जाएंगे। 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसका 2 हेक्टयर क्षेत्र वाले किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पहली किश्त के रूप में किसानों को 2 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए हैं। 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया है। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को आय सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलेंगे। ये राशि तीन किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ होगा। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। 25 करोड़ रुपए चालू वर्ष के लिए और 2019-20 के लिए 75000 करोड़ राशि के प्रावधान का प्रस्ताव किया दिया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का एमएसपी लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक तय किया है। हमारी सरकार की किसान समर्थन नीतियों की वजह से पैदावार बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत घटने और भारत में खाद्य महंगाई में कमी के चलते उनकी आय में कमी आई है। इसलिए गरीब किसानों को आय सपोर्ट की जरूरत है। बहरहाल माना जा रहा है कि पिछले दिनों हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा की हार किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी। इसलिए किसानों को पहली प्राथकिमता देना भाजपा के लिए अनिवार्य माना जा रहा था और तभी 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को 6000 रुपए सालाना की सहायता दी जाने की बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है।

यकीनन किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना लाभदायी तो है ही, साथ ही सरकार ने इस बजट में कामधेनु योजना का ऐलान करके किसानों का एक और लाभ से जोड़ दिया है। बताते चले कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड देगी, जिसमें गाय पालने वालों को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए कामधेनु योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार गौ माता के लिए पीछे नहीं हटेगी। कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें गाय की नस्ल की सुधार पर भी काम होगा। सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को पशुपालन और मछली पालने के लिए कर्ज में 2 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे सभी किसानों को 2 प्रतिशत और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी। वही गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण लागू होने से दूसरे आरक्षित वर्गों पर असर न पड़े, इसके लिए संस्थानों में करीब 2 लाख सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी तथा सभी को अनाज मिले और किसी को भी भूखे पेट नहीं सोना पड़े। इसके तहत मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने बजट को पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई घटाई है। इस दौरान पिछली सरकारों की तुलना में सबसे कम महंगाई दर रही है। हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। महंगाई गरीबी पर टैक्स की तरह है। हम महंगाई को दो अंकों से नीचे लाए। सरकार ने देश के आत्म-विश्वास को बढ़ाया। भारत अब ट्रैक पर है और विकास समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार दहाई

अंक वाली मुद्रास्फीति पर लगाम कसने में सफल रही है। हमने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी है और हमारे कार्यकाल में औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रही। बताते चले कि वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि संप्रग सरकार के 2009-2014 के शासन में मुद्रास्फीति औसतन 10.1 प्रतिशत पर रही थी। गोयल ने संसद में कहा, 2009-14 के दौरान मुख्य तौर पर खाद मुद्रास्फीति बढ़ी थी। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी। हम मुद्रास्फीति को 4.6 प्रतिशत के औसत पर लेकर आए, जो किसी भी अन्य सरकार के पूरे कार्यकाल के मुद्रास्फीति आंकड़े से कम है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति 2.19 प्रतिशत रही। यदि हम महंगाई को कम नहीं करते तो हमारे परिवारों को खाना, यात्रा और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों पर 35 से 40 प्रतिशत अधिक खर्च करना होता। देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। इसके बाद वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण, मनरेगा के लिए बजट और खाद्य सब्सिडी बढ़ाने का जिक्र किया और कहा कि हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। आर्थिक सुधार के बाद से औसत जीडीपी विकास सबसे बढ़िया रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिसके चलते 5 साल में एफडीआई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। हमने एनपीए को कम करने की कोशिश की। हमने एनपीए पर रिजर्व बैंक को स्थिति बताने को कहा। बड़े कारोबारियों को अब लोन चुकाने की चिंता होती है। किसानों की आमदमी दोगुना हुई है। हमारी सरकार ने बैंकिंग सुधार को आगे बढ़ाया। हमारी सरकार में ये दम था कि हम रिजर्व बैंक से कहा कि बैंकों के लोन को देखें और सही स्थिति को देश के सामने रखेंगे। पारदर्शी प्रक्रिया से हमने एनपीए की समस्या का समाना किया। पहले सिर्फ छोटे बिजनेसमैन पर कर्ज वापस करने का दबाव रहता था, अब बड़े बिजनेसमैन को भी चिंता रहती है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले पांच साल में देश को 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट भाषण पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि इसकी अहम वजह देश में नियामकीय व्यवस्था का स्थिर और उम्मीद के मुताबिक रहना है। साथ ही अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियाद ने भी इसमें मदद की। गोयल ने कहा कि इस अवधि में एफडीआई नियमों को बड़े पैमाने पर उदार किया गया। हमने अधिकतर एफडीआई निवेश को स्वत: मंजूरी मार्ग से करने की अनुमति दी। सरकार ने रक्षा, एकल ब्रांड खुदरा, एयरलाइंस और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई नियमों को सुगम बनाया है। अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम विदेशी निवेश हुआ है। सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, दूरसंचार शामिल हैं।

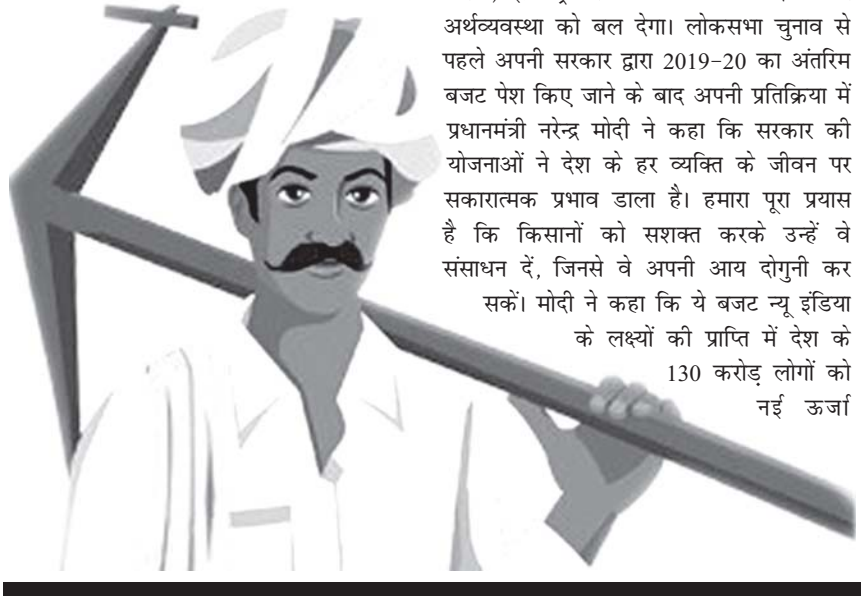

सनद् रहे कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसानों को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार आयकरदाताओं का गौरवगान करेगा, इंफ्रास्ट्रक्टर निर्माण को गति देगा और अर्थव्यवस्था को बल देगा। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार द्वारा 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को सशक्त करके उन्हें वे संसाधन दें, जिनसे वे अपनी आय दोगुनी कर सकें। मोदी ने कहा कि ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। उन्होंने कहा कि ये बजट

गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार आयकरदाताओं का गौरवगान करेगा, इंफ्रास्ट्रक्टर निर्माण को गति देगा और अर्थव्यवस्था को बल देगा। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि उन किसानों की मदद करेगी जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। यह योजना किसान कल्याण के मार्ग में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा को कुछ हौसला मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं मध्यम वर्ग को आयकर में मिली छूट के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और देश के विकास को गति देने में लगा हुआ है। उनके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मोदी ने कहा कि इस बजट से 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स देने वालों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। किसान उन्नति से लेकर, कारोबारियों की प्रगति तक, आयकर से लेकर आधारभूत संरचना तक, आवास से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सब पर ध्यान दिया गया है। मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले से चली आ रहीं

परंपराओं का पालन करते हुए अंतरिम बजट पेश किया। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में सत्तारूढ़ सदस्यों द्वारा मोदी, मोदी के नारों के बीच किसानों और करदाताओं को व्यापक राहत की घोषणा की।

ध्यान रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट में कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है कि बजट में टैक्स स्लैब की सीमा ढ़ाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। 5 लाख तक की आय पर पहले 13 हजार रुपए लगते थे। अब नहीं लगेगा कोई टैक्स। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब 5 लाख रुपए तक की आमदनी रखने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का पूरा टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया। टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग के 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। महिलाओं को बैक में 40 हजार तक के ब्याज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। टैक्स पेयर्स से 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। साढ़े चार साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसलिए कुछ फायदा मिडिल क्लास को भी दिया जाए।

दरअसल 2014 से अब तक किसी भी बजट में इनकम टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ाई गई थी। नतीजा लोगों को हर साल इनकम टैक्स में छूट मिलने का काफी इंतजार रहता था। इस बार भी कामकाजी लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीदे थी। चुनावी वर्ष होने के नाते उम्मीद भी थी कि सरकार इनकम टैक्स लिमिट में मामूली ही सही लेकिन राहत जरूर दे सकती है, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख की दी है। हालांकि सरकार ने आयकर में जो छूट दी है उससे सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी करमुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपए होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40000 रुपए तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है जो अभी छूट 10000 रुपए तक के ब्याज पर थी।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने अपने चुनावी बजट में 5 लाख तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी है। कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा आय वालों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इस छूट के अलावा भी आप अपनी आय को टैक्स से बचा सकते हैं। जैसे अगर आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट प्रोविडेंट फंड या एलआईसी जैसी जगहों पर करते हैं तो 6.5 लाख तक कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। इसी तरह यदि आपका कोई एजुकेशन लोन या होम लोन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको अतिरिक्त छूट दिला सकता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अब बढ़कर 50 हजार रुपए हो गया है। साथ ही आपका और आपके परिजनों के मेडिकल इंश्योरेंस को भी आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि फिर से मोदी सरकार बनती है और यह नया टैक्स स्लैब लागू होता है तो अनुमानत: 5 लाख कमाने वाला कोई व्यक्ति करीब 12,500 रुपए सालाना बचा सकेगा। सेस को जोड़-घटाकर यह बचत 13000 हो सकती है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां किसानों के लिए मोदी सरकार ने 6 हजार का सौगात दिया है तो वही छोटे व्यवसायियों व कामगरों को टैक्स में छूट देकर उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। वही बताते चले कि मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं, उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपए किया गया है। साथ ही ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में एक बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेश की। इसे मेगा पेंशन योजना भी कहा जा रहा है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपए का योगदान देना होगा। मोदी सरकार ने दावा किया कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 21 हजार रुपए तक के वेतन वाले लोगों को 7 हजार रुपए तक का बोनस का ऐलान भी किया गया। इसके अतिरिक्त श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की है।

बहरहाल, आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में मोदी सरकार की यह लोकलुभावन बजट आम जनता पर कितना असर डालेगा, यह तो वक्त बतायेगा। किन्तु जिस तरह से किसानों को एजेंडा बनाकर यूपीए और एनडीए में शीतयुद्ध कायम है, उससे किसानों के हित में सरकार चुनना मुश्किल है, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले जिस प्रकार से सरकार के विरोध में किसानों ने पदयात्रा किया और फिर उनके विरोध को रोकने के लिए पुलिस का बल प्रयोग किया गया, उसे शायद ही किसान भूली होगी और साथ ही आंकड़ों को पलटकर देख ले तो किसानों की आत्महत्या भी कही न कही चुनावी प्रभाव तो डालेगी ही। अब सवाल यह है कि किसानों के लिए एक तरफ एनडीए है तो दूसरे तरफ यूपीए, तो ऐसे में विकल्प चुनना बड़ा मुश्किल हो गया है और यह भी बता दें कि तीसरे विकल्प के रेस में महागठबंधन में शामिल कई पार्टियों के दिग्गज नेता अपने आप को प्रधामंत्री का पक्का दावेदार अभी से बताने लगे हैं। विडम्बना यह है कि बजट प्रत्येक वर्ष पेश किए जाते हैं किन्तु धरातल पर लाभ मिलने का जब समय आता है तब तक अगला बजट पेश कर दिया जाता है और इसी उपापोह में किसान पंगु बने हुए हैं। खैर! मोदी सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल के अंतिम बजट को कुछ मायनों में असरदार जरूर देखा जा सकता है। आगामी आम चुनाव में यह तुरूप का इक्का साबित हो। ●

● अमित कुमार

कहते हैं कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति बारहवें वर्ष और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच छह वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। वही खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारम्भ होता है, जब सूर्य और चन्द्रमा, वृश्चिक राशि में और वृहस्पति, मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को 'कुम्भ स्नान-योग' कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात् स्वर्ग दर्शन माना जाता है। गौरतलब है कि प्रत्येक तीन वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। इस तरह नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में तीन तीन वर्षों के चक्र के अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन मान्यता के अनुसार प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी के मद्देनजर प्रयागराज में मकर संक्रांति के पावन पर्व से कुंभ मेला का भी आगाज हो चुका है। इस मेले की एक खास बात इस बार यह है कि जो पहला स्नान पर्व होता है वह शाही स्नान से होता है। इतने बड़े और भव्य आयोजन को देखते हुए रेलवे और रोडवेज ने खास इंतजामात किए हैं। माना जा रहा है कि पहले कुंभ स्नान में लाखों लोग जुटेंगे। इसी तादाद को देखते हुए व्यापक प्रबंध प्रशासनिक स्तर पर किए गए हैं। खास बात ये भी है कि रेलवे ने इस मौके पर स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी किया है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है कुंभ मेला, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू एवं अन्य धर्म के लोग आते हैं एवं पवित्र नदी में स्नान करते हैं। यह मानवता की दुनिया की सबसे बड़ी सभा है, जो शुरू हो चुकी है। सनद् रहे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला के दौरान नागा साधु सहित करोड़ों तीर्थयात्री गंगा, यमुना और एक पौराणिक तीसरी नदी, सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। कुंभ से जुड़ी ऐतिहासिक कारणों को आइए हम जानते हैं....।

कूर्म पुराण के अनुसार अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में बारह दिन तक निरंतर युद्ध चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के बारह दिन अर्थात मनुष्यों के बारह वर्ष माने गए हैं इसीलिए कुम्भ का आयोजन भी प्रत्येक बारह वर्ष में ही होता है। मान्यता के अनुसार कुम्भ भी बारह होते हैं जिनमें से चार का आयोजन धरती पर होता है शेष आठ का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुम्भों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। प्रयागराज में कुम्भ मेला पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। प्रयागराज में कुम्भ मेला विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज कुम्भ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। सन् 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्योंकि उस

वर्ष पूरे 144 वर्ष पूर्ण हुए थे। संभवत: अब अगला महाकुंभ 138 वर्ष बाद आएगा। सनद् रहे कि हमारे धर्मशास्त्रों के मतानुसार कुंभ 12 कल्पित हैं, जिनमें से 4 भारतवर्ष में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यम्बकेश्वर (नासिक) में होते हैं तथा शेष 8 को देवलोक में माना जाता है। भारत के चारों स्थानों पर बृहस्पति के विभिन्न राशियों में संक्रमण और उसमें उपस्थिति की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे प्रयाग में बृहस्पति का वृषस्थ और सूर्य का मकरस्थ होना कुंभ पर्व का योग लाता है, तो उज्जैन में बृहस्पति का सिंहस्थ एवं चंद्र-सूर्य का मेषस्थ होना कुंभ पर्व का सुयोग बनाता है। हरिद्वार में कुंभ राशि के बृहस्पति में जब मेष का सूर्य आता है, तो कुंभ योग बनता है। नासिक में बृहस्पति तो सिंहस्थ ही रहते हैं, पर सूर्य और चंद्रमा भी सिंहस्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि उज्जैन और त्र्यम्बकेश्वर (नासिक) के कुंभ पर्वों को 'कुंभ' न कहकर 'सिंहस्थ' नाम से अधिक जाना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो सूर्य और चंद्र के साथ बृहस्पति को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। बृहस्पति का विभिन्न राशियों में संक्रमण का काल मांगलिक माना गया है और बृहस्पति की यही मांगलिकता 'कल्याणकारिता' ही कुंभ पर्वों का विशेष कारण है। अब सवाल यह उठता है कि बृहस्पति तो कुंभ, वृषभ और सिंह राशियों के अलावा भी अन्य राशियों में भी संक्रमित और उपस्थित होते हैं और हर राशि में करीब-करीब 12 वर्ष बाद ही आते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वे इन चारों स्थानों के अतिरिक्त और कौन से अन्य स्थान हैं, जहां बृहस्पति के अन्य राशियों में स्थिर होने पर मंगल पर्व (कुंभ पर्व) का सुयोग होता है। हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार 12 कुंभ पर्व कल्पित हैं, जिसमें से 4 प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यम्बकेश्वर (नासिक) में होते हैं, शेष अज्ञात हैं? अर्थात धर्मग्रंथों के अनुसार देवलोक में होते हैं। किंतु यह आज के वैज्ञानिक युग में एक महान खोज का विषय है, क्योंकि कुंभ पर्व या सिंहस्थ हेतु बृहस्पति का योग ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बृहस्पति तो कुंभ, मेष, वृषभ और सिंह राशियों के अतिरिक्त अन्य शेष राशियों में भी संक्रमित और उपस्थित होते हैं और करीब-करीब हर राशि में लगभग 12 वर्ष बाद ही आते हैं। अत: वैज्ञानिकों, ज्योतिर्विदों और खगोलशास्त्रियों को यह अवश्य खोज करनी चाहिए कि भारत के अतिरिक्त विश्व में वे कौन से अन्य स्थान हैं और कहां-कहां हैं, जहां बृहस्पति के अन्य राशियों में स्थित होने पर मंगल पर्व (कुंभ) का सुयोग उपस्थित होता है? विश्व के अन्य भागों में होने वाले मेलों, जो कि किसी-न-किसी नदी के तट पर भरते हों, उनकी खगोलीय (ग्रह स्थितियों) की विस्तृत खोजबीन तथा तुलनात्मक अध्ययन, शेष 8 अज्ञात कुंभ पर्वों की जानकारी में सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विश्व के मानचित्र में ऐसे अनेक विराट पर्व मनाएजाते हैं, जो कि किसी-न-किसी नदी, सागर आदि के तटों पर होते हैं। आवश्यकता है तो उन मेलों की गहन छानबीन के साथ अध्ययन और उपरोक्त बृहस्पति आदि ग्रहों के संयोग की तुलनात्मक अध्ययन की। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे भौगोलिक ज्ञान की श्रीवृद्धि भी।

दक्षिण भारत में पांचवां कुंभ महापर्व-

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि हमारे धर्मशास्त्रों में 12 कुंभ कल्पित हैं जिनमें से 4 कुंभ महापर्व प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यम्बकेश्वर (नासिक) में मनाए जाते हैं और यही चारों कुंभ ही जगविख्यात हैं, शेष अज्ञात हैं और उन पर शोध की आवश्यकता है। किंतु इन 4 कुंभ पर्वों के अतिरिक्त एक पांचवां कुंभ भी हमारे शोध से सामने आया है जिसे केवल दक्षिण भारत के साधु-संत और जनता-जनार्दन ही मनाते हैं। यह पांचवां कुंभ महापर्व तमिलनाडु में चिदम्बरम् के पास कुंभकोणम् नामक स्थान में 'महामाखम पर्व' के नाम से मनाया जाता है। 'कुंभकोणम्' का संस्कृत नाम 'कुंभघोषम्' है। यह कुंभ भी प्राय: 12 वर्षों में ही मनाया जाता है।

गौरतलब है कि कुंभकोणम् के महामाखम पर्व (कुंभ महापर्व) की कथा इस प्रकार है- ब्रह्माजी ने एक ऐसा कुंभ (कलश) बनाया जिसमें संचित कर रखा गया है। इस कुंभ की घोष अर्थात नासिका किसी कारण से खंडित हो गई, जिसके कारण 'अमृत' घड़े से बाहर फैल गया और वहां की भूमि अमृतमयी हो गई। यहां तक कि 5 कोस तक का भू-भाग अमृतमयी हो गया, यथा-

कुंभस्य कोणंतो यस्मिन सुधापूरं विनिस्सृतम्।
तस्मात् तत्पदं लोके कुंभकोणम् वदंतिहि॥

पुराणों के अनुसार अमृत और विश्व सृजन के बीजों से भरा कुंभ (कलश) जलमय प्रलय के समय कुंभकोणम् नामक स्थान में आकर ठहर गया। शिकारी के वेश में शिवजी ने तीर मारकर घड़े (कुंभ) को फोड़ दिया और इस प्रकार महामाखम सरोवर में अमृत भर गया। महामाखम के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोदावरी, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी व महानदी आदि नदियों के पावन सलिल स्रोत महामाखम सरोवर में प्रगट होते हैं तथा समस्त देवी-देवता वहां निवास करते

हैं। महामाखम पर्व के समय लाखों श्रद्धालुजन यहां आकर महामाखम सरोवर और कावेरी नदी में स्नान करके दान-धर्म आदि कर्म करते हैं। यहां विचारणीय बात यह है कि समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से इस महामाखम पर्व का क्या संबंध है? कुछ निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, किंतु इतना तो तय है कि भारत के चारों विख्यात कुंभ पर्वों का स्थल समुद्र तट पर नहीं है जबकि कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से बताया गया है और समुद्र से यदि कहीं अमृत की निकटता देखी जा सकती है तो वह निश्चित रूप से कुंभकोणम् है। जैसा कि कुंभकोणम् नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कुंभ कलश को समुद्र मंथन के बाद इसी स्थान पर रखा गया था और कुंभकोणम् नाम भी स्वयं कुंभ पर्व को चरितार्थ करता हुआ प्रतीत होता है तथा कुंभ संबंधी धारणाओं का जीवंत रूप भी साकार करता है। कुंभकोणम् में अनेक देवी-देवताओं के पावन मंदिर हैं जिसमें 'महामाखम सरोवर' सबसे महत्वपूर्ण है। इसी महामाखम में दक्षिण भारत के 'कुंभ का मेला' 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसी कुंभ मेले में माघी पूर्णिमा को प्रमुख स्नान होता है। नागेश्वर, शारंगपाणि और कुंभेश्वर सबसे प्रमुख मंदिर हैं। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान कुंभेश्वर मंदिर का है। कुंभेश्वर मंदिर में कुंभ (कलश) के आकार का गोलाकृत शिवलिंग स्थापित है। इस शिल्प का शिवलिंग भारत के अन्य किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि समुद्र मंथन के पश्चात निश्चित रूप से 'अमृत कलश' यहीं रखा गया होगा और यहीं से विष्णु का इशारा पाकर जयंत कलश लेकर भागे होंगे तथा उसे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यम्बकेश्वर (नासिक) में विश्राम के क्षणों में रखा होगा जिसकी स्मृति में कुंभ पर्व आयोजित होते हैं। उत्तर भारतीय नागरिकों एवं साधु-संतों को कुंभकोणम् के

कुंभ नाम की सार्थकता और शिव से कुंभ का घनिष्ठ संबंध तथा शताब्दियों से इस शैव क्षेत्र में कुंभ की मान्यता, असाधारण और अकल्पनीय लग सकती है, किंतु यह कटु सत्य है कि दक्षिण भारत में प्रति 12 वर्ष में 5वां कुंभ महापर्व मनाया जाता है। इस कुंभकोणम् के महामाखम सरोवर पर भरने वाले इस विशाल मेले को 'जो कि कुंभ मेलों (प्रचलित) की ही भांति प्रति 12 वर्ष में अमृत कलश की स्मृति में ही मनाया जाता है'। उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक मान्यताओं की एकात्मकता के साथ-साथ भारत के अन्य 4 कुंभ महापर्वों की परंपरा का प्रवेश द्वार तो माना ही जा सकता है। अभी संतों के अखाड़े एवं उत्तर भारतीय साधु-संत भले ही यहां कुंभ स्नान हेतु नहीं आते हैं अथवा इस महापर्व से अपरिचित हैं किंतु भविष्य में जब संतों के अखाड़ों और उत्तर भारतीय साधु-संतों का जमावड़ा कुंभकोणम् में भी होने लगेगा और यहां भी संतों का शाही स्नान होने लगेगा, तब इसे हमें 5वें महाकुंभ पर्व के रूप में स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि कुंभकोणम् के कुंभ महापर्व का भी अपना वैशिष्ट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार से धर्मग्रंथों में वर्णित 12 कुंभ महापर्वों में से 5 का तो पता चल ही चुका है किंतु 7 कुंभों (कुंभ महापर्वों) की व्यापक खोजबीन एवं मीमांसा अभी शेष है।

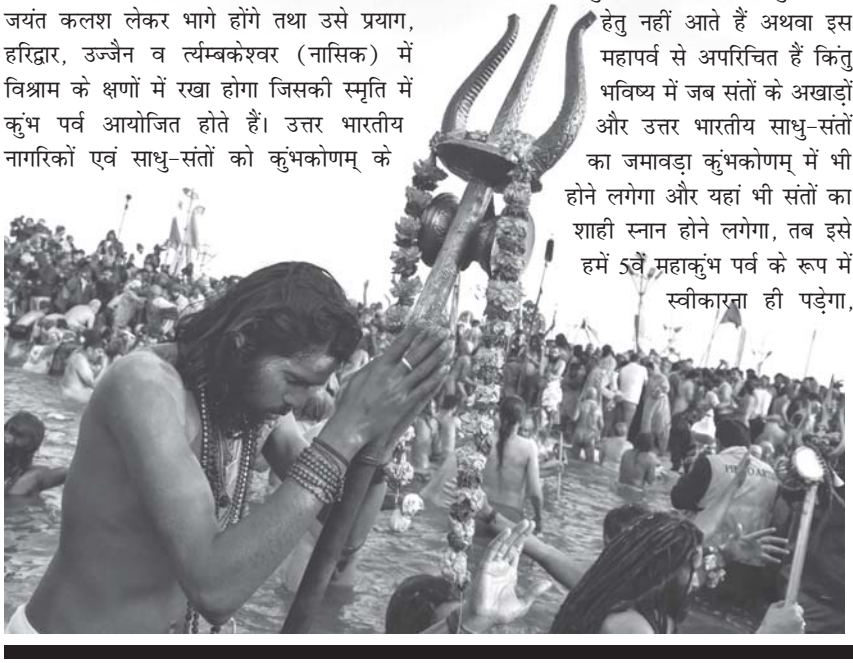

बताते चले कि कुंभ का इतिहास और उसकी महत्ता के बारे में स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्द्धन के राज्यकाल (664 ईसा पूर्व) में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है। साथ ही साथ उसने राजा हर्षवर्द्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया है। ह्वेनसांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्द्धन हर पांच साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दे देते थे। ग्रंथों के अनुसार इन संयोग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है। दूसरा जब बृहस्पति के मेष राशि में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ का आयोजन होता है। तीसरा कुंभ बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में आने पर नासिक में गोदावरी के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है और बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा तट पर कुंभ का आयोजन होता

है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भारद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा कि, हे राम गंगा-यमुना के संगम का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र है आप वहां भी रह सकते हैं-

श्रीरामचरितमानस में प्रयागराज के महत्व का वर्णन बहुत रोचक तरीके से और विस्तारपूर्वक किया गया है-

माघ मकरगत रवि जब होई।
तीरथ पतिहिं आव सब कोई।।
देव दनुज किन्न्र नर श्रेनी।
सादर मज्जहिं सकल त्रिवेणी।।
पूजहिं माधव पद जल जाता।
परसि अछैवट हरषहिं गाता।।
भरद्वाज आश्रम अति पावन।
परम रम्य मुनिवर मन भावन।।
तहां होइ मुनि रिसय समाजा।
जाहिं जे मज्जन तीरथ राजा।।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। साधु-संत प्रात:काल संगम पर स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों और तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है और इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात भी कही गई है। कुंभ का बौद्धिक पौराणिक ज्योतिषी के साथ-साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वर्णन भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषिवर ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया, जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी, उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर, फिर भी प्रयागराज का पलड़ा

भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर, वहां भी प्रयागराज वाला पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म, यज्ञ आदि के साथ-साथ त्रिवेणी संगम का अति महत्व है। रामायण के अनुसार यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर तीन-तीन नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं, यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। इस भूमि पर स्वयं ब्रह्माजी ने यज्ञ आदि कार्य संपन्न कर ऋषि और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने आपको धन्य माना। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा, ऋषिवर यह बताएं कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और वहां संगम स्नान का क्या फल है? इस पर मार्कंडेय जी ने उन्हें बताया कि प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर से लेकर वासुकी के हृदयोपरिपर्यंत कंबल और अश्वतर दो भाग हैं और बहुमूलक नाग है। यही प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां पर स्नान करने वाले विभिन्न दिव्यलोक को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है, देवताओं द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा शेष होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। मध्यकाल इतिहास में अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आइने अकबरी में लिखा है कि हिन्दू लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। कुंभ का महत्व न केवल भारत में वरना विश्व के अनेक देशों में है। इस प्रकार कुंभ को वैश्विक संस्कृति का महापर्व कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान दुनिया के अनेक देशों से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति में रचने-बसने की कोशिश करते हैं, इसलिए कुंभ का महत्व और बढ़ जाता

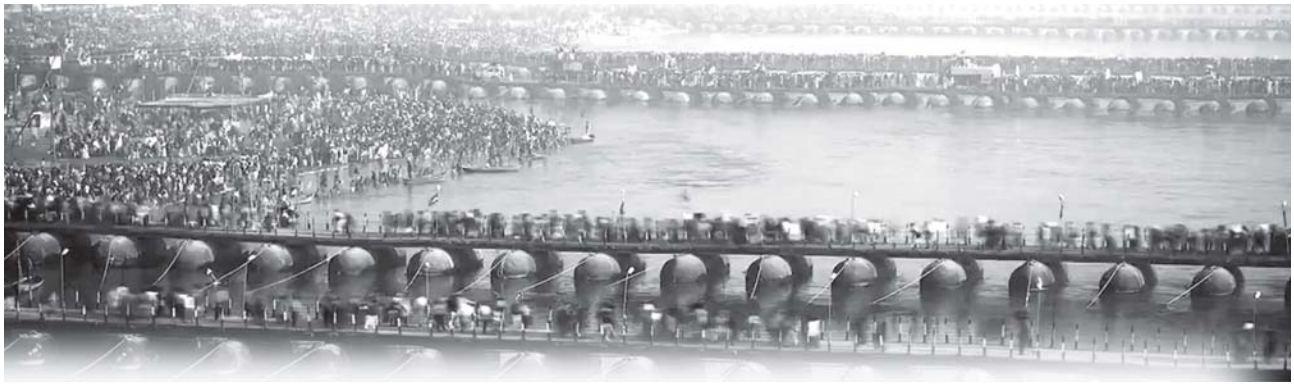

है। कुंभ पर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है, प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ पर्व को अब शासन स्तर से महाकुंभ और इसके बीच छह वर्ष पर आने वाले पर्व को कुंभ की संज्ञा दी जा रही है।

गौरतलब है कि पुराणों में कुंभ की अनेक कथाएं मिलती हैं, भारतीय जनमानस में तीन कथाओं का विशेष महत्व कुंभ पर्व के संदर्भ में पुराणों में तीन अलग-अलग कथाएं मिलती हैं। प्रथम कथा के अनुसार कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और अदिति के साथ हुआ था। अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई तथा दिति से दैत्य पैदा हुए। एक ही पिता की संतान होने के कारण दोनों ने एक बार संकल्प लिया कि वे समुद्र में छिपी हुई बहुत सी विभूतियों एवं संपत्तियों को प्राप्त कर उसका उपयोग करें। इस प्रकार समुद्र मंथन एकमात्र उपाय था। समुद्र मंथन उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक अमृत कलश भी था, इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उसे पीकर दोनों अमृत की प्राप्ति करना चाह रहे थे। स्थिति बिगड़ते देख देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को संकेत किया और जयंत अमृत कलश लेकर भाग चला। इस पर देवों ने उसका पीछा किया, पीछा करने पर देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर संघर्ष के दौरान अमृत कुंभ को सुरक्षित रखने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ने बड़ी सहायता की और उनके हाथों में जाने से कुंभ को बचाया। सूर्य भगवान ने कुंभ की फूटने से रक्षा की और चंद्रमा ने अमृत छलकने नहीं दिया, फिर भी संग्राम के दौरान मची उथल-पुथल से अमृत कुंभ से चार बूंदें छलक की गई, यह अलग-अलग चार स्थानों पर गिरीं, इनमें से एक गंगा तट हरिद्वार में, दूसरी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, तीसरी क्षिप्रा तट उज्जैन में और चौथी गोदावरी तट नासिक में। इस प्रकार इन चारों स्थानों पर अमृत प्राप्ति की कामना से कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। कुंभ की कथाओं के अनुसार देवता और व्यक्तियों में 12 दिनों तक जो संघर्ष चला था उस दौरान अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी थीं, वहां-वहां कुंभ मेला लगता है, क्योंकि देवों के इन 12 दिनों को 12 मानवी वर्षों के बराबर माना गया है। इसलिए कुंभ पर्व का आयोजन 12 वर्षों पर होता है। जिस दिन अमृत कुंभ गिरने वाली राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग हो, उस समय पृथ्वी पर कुंभ होता है। राशि विशेष में सूर्य और चंद्रमा के स्थित होने पर उक्त चारों स्थानों पर शुभ प्रभाव के रूप में अमृत वर्षा होती है और यही वर्षा श्रद्धालुओं के लिए पुण्यदायी मानी गई है। इस प्रकार से वृष के गुरु में प्रयागराज, कुंभ के गुरु में हरिद्वार, तुला के गुरु में उज्जैन और कर्क के गुरु में नासिक का कुंभ होता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार कुंभ पर्व की तिथियां निश्चित होती हैं। मगर शुरू में प्रयागराज, मेष के सूर्य में हरिद्वार, तुला के सूर्य में उज्जैन और कर्क के सूर्य में नासिक का कुंभ पर्व पड़ता है।

सनद् रहे कि कुंभ में स्नान पर्व का भी अपना महत्व होता है। संक्रांति के पूर्व और बाद की 16 घड़ियों में पुण्यकाल माना गया है। मुहूर्त तिथि आधी रात से पहले हो तो पहले दिन तीसरे पहर में पुण्यकाल बताया गया है और यदि मुहूर्त तिथि आधी रात के बाद हो तो पुण्यकाल प्रात:काल माना जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति का पुण्यकाल 40 घड़ी, कर्क संक्रांति का पुण्यकाल 30 घड़ी और तुला एवं मेष का संक्रांति का पुण्यकाल 20-20 घड़ी पहले और बाद में बताया गया है। प्रयाग में माघ के महीने में विशेष रूप से कुंभ के अवसर पर गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। अनेक पुराणों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। प्रयागराज में प्रमुख धार्मिक मंदिर है, जिसमें शंकर विमान मंडपम, बड़े हनुमान बंधवा रामानंदाचार्य मठ, सिद्धश्वर महादेव मंदिर, जगदंबा मठ, नाग वासुकी शक्तिपीठ, एलोप शंकरी मां, ललिता देवी मंदिर, कल्याणी मंदिर, भारद्वाज आश्रम मंदिर, शिव कोटि तीर्थ मंदिर, श्री हनुमान निकेतन मनकामेश्वर मंदिर, पातालपुरी मंदिर प्रमुख हैं। प्रयागराज में कुल छह कुंभ स्नान पर्व होते हैं। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इस बार यह प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां मकर संक्रांति शाही स्नान मंगलवार 15 जनवरी, पौष पूर्णिमा सोमवार 21 जनवरी, मौनी अमावस्या सोमवार 4 फरवरी, बसंत पंचमी रविवार 10 फरवरी, माघी पूर्णिमा मंगलवार 19 फरवरी, महाशिवरात्रि सोमवार 4 मार्च को पड़ेगा।

बताते चले कि प्रयागराज में आठ सप्ताह तक चलने वाली इस कुंभ में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इनमें अनुमानत: दस लाख विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। इस बार तीर्थयात्रियों को खिलाने और ठहरने का इंतजाम भी विशाल स्तर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ मेले के लिए खास इंतजाम किए हैं। संगम पर 10 किलोमीटर लंबे घाट और चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना के तहत 1.22 लाख शौचालय बनाए गए हैं और साफ-सफाई के लिए 20,000 कर्मचारियों को तैनात किए गये है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के लिए जगह-जगह सेल्फी प्वाइंट, फूड कोर्ट और कॉफी प्वाइंट बनाए गए हैं। साथ ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सनद् रहे कि कुंभ की मेजबानी करने के लिए प्रयागराज को इस तरह सजाया गया है जो देखकर ही श्रद्धा आस्था का भाव दर्शाता है। संगम का पूरा इलाका सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी अद्भुत रोशनी में नहाता नजर आ रहा है। ज्ञात हो कि प्रयागराज पहले कभी इतनी खूबसूरती से

नहीं सजाया गया था। संगम के घाट पर रंग-बिरंगी रौशनी तीर्थयात्रियों को भी खूब भा रही है। इसको लेकर प्रयागराज के निवासी फूले नहीं समा रहे हैं और योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रयागराज निवासी एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि उन्होंने कुंभ मेले खूब देखे, लेकिन कभी ऐसा बंदोबस्त नहीं देखा। कुंभ मेला के लिए योगी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए विशेष मेलाधिकारी विजय किरन आनंद खुद रात-रात तक संगम पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बार कुंभ के महापर्व पर तीर्थयात्रियों और सैलानियों को नया लुक देखने को मिलेगा। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद बताते हैं कि इस बार कुंभ एक नया अनुभव देगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को यादगार अनुभव दिया जाए, इसलिए दिव्य कुंभ की परिकल्पना की गई है।

ध्यान रहे कि प्रयागराज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रेलवे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यमुना के ऊपर बने पुराने लोहे के पुल को भी रोशनी से सजाया गया है। यमुना पर इसकी किरणें दृश्य को मनमोहक बना रही हैं। जाहिर है कि योगी सरकार मेले को दिव्य बनाना चाहती है, लेकिन चुनौती तब तक रहेगी जबतक कुंभ का समापन नहीं हो जाता। वही इस बार कुंभ में आयोजकों की तरफ से 600 बड़ी रसोई, 100,000 पोर्टेबल टॉयलेट, विशाल तंबू उपलब्ध कराए गये हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कई कंपनियां यहां लग्जरी टेंट भी लगा रही हैं। साथ ही साथ पर्यटन विभाग की ओर से विकसित किए जा रहे 'संस्कृति ग्राम' में सभ्यता और संस्कृति नजर आ रही है। जिसे बंगाल के कलाकार आकार देने में जुटे हैं। संस्कृति ग्राम में हजारों साल पुरानी सिन्धु सभ्यता की झलक तो मिलेगी ही आधुनिक भारत की तस्वीर भी यहां देखी जा सकेगी। सात करोड़ चालीस लाख की लागत से यह करीब आठ एकड़ क्षेत्र में 31 दिसंबर तक बनकर तैयार हो चुकी थी। कुंभ क्षेत्र में बसाए जा रहे संस्कृति ग्राम में बौद्ध और जैन धर्म के साथ मुगल सल्तनत के देश में विस्तार, वैदिक युग के साथ ब्रिटिश शासन, मराठा साम्राज्य, स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों की ऐतिहासिक और साहसिक कहानियों को भी चित्रों और चलचित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसमें स्वतंत्र भारत और आधुनिक भारत पर लघु फिल्में भी दिखाई जा रही है। कुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए पहली बार हो रहे इस आयोजन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को डिजिटल फॉर्म में ओपन थियेटर के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। आगे तैयारियों के मद्देनजर व्यवस्था की बात करे तसे उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ने अलग-अलग 51 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसके लिए टाइम टेबल भी जारी किया गया है। इनमें से 26 ट्रेन टाइम टेबल यानी शेड्यूल के हिसाब से तो 25 जरूरत पड़ने पर यानी ऑन डिमांड चलाई जाएंगी। इलाहाबाद जंक्शन से ये स्पेशन ट्रेनें कानपुर, डीडीयू, सतना और झांसी रूट पर चलेंगी। छपरा, वाराणसी और गोरखपुर रूट के लिए भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं रेलवे ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद जंक्शन, प्रयाग, नैनी और इलाहाबाद सिटी स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म पर स्पेशल मेडिकल बूथ भी बनाए हैं, ताकि अगर कोई यात्री बीमार हो जाए तो उसका फौरन इलाज किया जा सके। और तो और कुंभ मेला प्रांगण जाने के लिए चिन्हित जगहों पर फ्री पार्किंग प्लेस दिया गया है। इन स्थलों से 1 जनवरी से ही करीब 217 शटल बसें संचालित की जा रही हैं। स्नान पर्व 14 से 16 जनवरी तक प्रयाग में कुल 500 शटल बसें चलाई गयी। इस बीच अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि पहले स्नान के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक रोडवेज की बसों के शहर में आने पर रोक रहेगी। इसके लिए राज्य परिवहन निगम ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

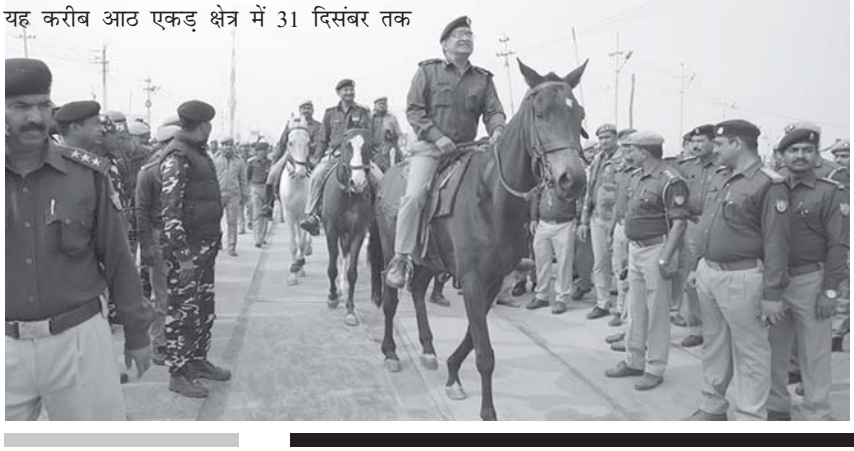

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज के संगम में हाईटेक अस्थायी अस्पताल बनाया हैं। यहां पर कुंभ मेला शुरू होने से पहले ही 10 हजार से ज्यादा लोग इलाज करा चुके हैं। इसमें महिलाओं की बीमारियों से लेकर अल्ट्रासाउंड, दंत चिकित्सालय और चर्म रोग से लेकर हर बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए योगी सरकार ने प्रयागराज में जो बंदोबस्त किए हैं, उसमें संगम तट पर बना अस्थायी अस्पताल आकर्षण का केंद्र है। बेहद कम खर्च और कम जगह में बने इस अस्पताल में 100 बेड लगाए गए हैं, जो बेहद आधुनिक हैं। दिगर बात है कि कुंभ मेला शुरू होने के पहले ही अस्पताल में 10,000 लोगों का ओपीडी के जरिए इलाज किया जा चुका है। इस अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज भी ऐसी सुविधा पाकर बेहद खुश हैं। प्रयागवासियों का कहना है कि अगर ऐसा अस्पताल परमानेंट उन्हें मिल जाए, तो बेहद खुशी होगी। कुंभ मेले में सरकार के साथ काम कर रहे कई मजदूरों ने एक प्रतिष्ठित चैनल से कहा कि इस अस्पताल के चलते उन्हें बेहद फायदा हो रहा है। कुंभ मेले के लिए योगी सरकार द्वारा बनाए गए इस खास अस्पताल में पर्चा भरने से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मफ्त है। अस्पताल में महिलाओं की बीमारियों से लेकर अल्ट्रासाउंड, दंत चिकित्सालय और चर्म रोग से लेकर हर बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। अस्पताल में एक चार बेड का आईसीयू भी बनाया गया है। दवाइयों का एक पूरा गोदाम बनाया गया है। इसके अलावा दो एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो बेहद आधुनिक हैं, जिनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी व्यवस्था है।

बहरहाल, कुंभ को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है और एक शाही स्नान भी हो चुका है तथा शेष तीन बाकी है। सनद् रहे कि कुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय दिख रही है और व्यवस्था को लेकर पूरे किए जा रहे इंतेजाम से लवरेज है। अगर आपने कुंभ स्नान अभी तक नहीं किया है तो, प्रयाग में चल रहे इस महाकुंभ में स्नान करके मनुष्य जीवन का बड़ा फल पाने का मौका नहीं गंवाये, क्योंकि यह कोई मामूली कुंभ नहीं बल्कि 144 वर्षों में एक बार प्रयाग में होने वाला महाकुंभ है जिसकी कहानी और महत्त्व को ऊपर बताया जा चुका है। ●

दिन के उजाले में मौन, चाँदनी रात में चहल-पहल

कभी-कभी ही क्यों जगते हैं साहब!

● सुमित राज यादव

ठाकुरगंज सर्किल के सुखानी थाना में मामला दर्ज होने के बाद इंट्री माफियाओ में हड़कंप मच गई है। एक तरफ पुलिसिया कार्रवाई से माफियाओं में हड़कम्प मची हुई है तो दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई से कई धंधेबाज व रसूखदारों के भूमिगत होने की खबर है। भारत–बंगाल की सीमा पर ट्रकों को पास कराने को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाने वाले गुर्गे पर भी इनदिनों निगाहें बनी हुई है। ठाकुरगंज सर्किल के बॉर्डर से सटे गलगलिया, कुर्लीकोर्ट, ठाकुरगंज, सुखानी, पाठामारी, जियापोखर, पोवाखाली थानाक्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रकों पर पुलिस की आंखों के नीचे से ट्रक पास कराया जाता है। देर रात से लेकर सूर्योदय के पहले तक इंट्री माफिया गाड़ी पास कराने का प्रयास करते है। ओवरलोड बेडमिसाली की गाड़ी, बालू की ट्रकों और डंफरो से ढुलाई की जाती है। यहां तक कि पुलिस को भी सरकारी योजनाओं में कार्य करने के सामग्री के नाम लर गुमराह किया जाता है। पुलिस को भी चकमा देने में आगे निकल चुके माफियाओं के गुर्गे की निगरानी नेशनल हाइवे पर बराबर की रहती है। दिनभर उजाले में चक्करमारी बॉर्डर पर ट्रक खड़ी रहती है। पुलिस को भी चकमा देने से नही चूकते है। कुर्लीकोर्ट थाना के सामने एसपी के आदेशानुसार लगाए गए चेक पोस्ट के ड्राम को भी तेज रफ्तार की ट्रक ने रौंद डाला गया था। इन माफिया के हौसले इतने बुलन्द है कि सबको मैनेज करने की बात करते फिरते है। किसी भी विभाग के निचले अधिकारी को मैनेज करने की बात कर ऊपर के अधिकारियों से बात तक करने से नहीं चूकते हैं। पत्रकार तक को मैनेज की झूठी और भ्रामक खबर फैलाकर अपना कारोबार का विस्तार करते है। खबर लिखने पर वास्तविकता उजागर हो जाने पर रहस्य से पर्दा उठता है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अब कई लोगों के बड़बोलेपन से दरपरत चेहरे सामने स्वयं आएँगे।

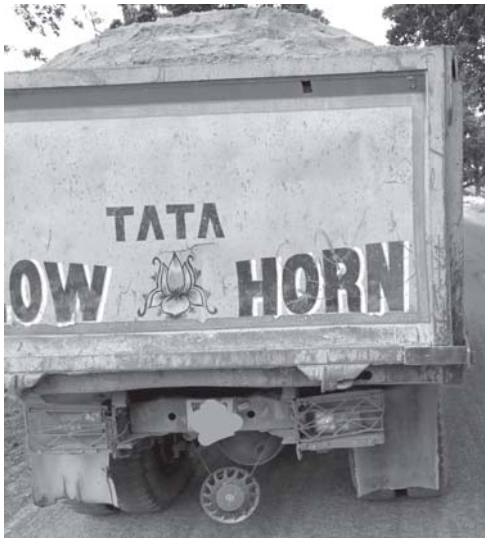

★ **नए नए चेहरों का हुआ है उदय :–** कई सरकारी योजनाओं का कार्य इनदिनों तेजी से चल रहा है। जिससे माल सप्लाई करने वाले कारोबारियों की संख्या निश्चिन्त तौर पर बढ़ी हैं। लेकिन, क्षमता से अधिक ओवरलोड वाहनों का परिचालन कर सप्लायर आजकल अपना उल्लू सीधा करने में जुटे है। कोडवर्ड के सहारे दर्जनो वाहनों को बंगाल की सीमा से पासिंग मिलता है। कई सफेदपोशों के भी इस धंधे में शामिल होने की जानकारी है। अफसोस पुलिस के हाथ अबतक ऐसे दर्जनों माफियाओं तक नहीं पहुंच पाई है। स्थलीय स्टिंग ऑप्रेशन दूध–का–दूध और पानी का पानी कर देगा। वास्तविकता तो यह भी है कि सीमा पार के कम उम्र लोग भी इस धंधे में महारत हासिल कर रहे है। जिससे पुराने माफिया भी पिछड़ते जा रहे है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी खास रसूखदार के भी होने का मामला प्रकाश में आ रहा है। जो पूर्व में जनप्रतिनिधि के पद पर भी रहे है।

★ **जुर्माना वसूली के बाद भी ओवरलोड परिचालन :–** कई थानाध्यक्ष के निर्देश पर ट्रकों के पकड़े जाने पर जुर्माना ठोका गया। जिसमें कुर्लीकोर्ट सबसे अग्रणीय रही है। इन धंधेबाजों से कई वर्ग के लोग सीधे तौर पर लाभांवित हो रहे है तो कई वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे है। खबर न लिखने पर पत्रकारों को भी इसका हिस्सा बनाया जाता हैं। किंतु, नाम बेचकर खुद मालामाल होना और दूसरे से वसूली कर अन्य के नाम पर खुद डकार जाना तो इनका पेशा रहा है। ऐसे नाम अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों के भी लेकर अपने मालामाल होने में माफिया जुटे है। जबकि, खुद को सबसे आगे और दबंगता साबित करने में सरकार के राजस्व को चुना लगाया जा रहा है।

★ **ओवरलोड वाहनों के परिचालन से सड़क होती है क्षतिग्रस्त :–** क्षमता से अधिक वाहनों के परिचालन पर सड़को को भारी क्षति पहुँच रही है। जिससे सरकार के राशि का बहाव हो रहा है। एक तरफ निर्माण कार्य जारी है। तो दूसरी ओर मालामाल होने के चक्कर मे इन माफियाओं द्वारा बिहार सरकार के परिवहन विभाग के साथ पथ निर्माण विभाग को भी ठेंगा दिखाया जा रहा हैं। प्रशासनिक महकमा के हरकत में आने के बाद इंट्री माफियाओं में कुछ दिनों के लिए हड़कम्प तो मचती है। लेकिन, कुछ दिनों बाद धंधेबाज अपने धंधे को पुनः चालू कर देते है।

★ **कई जगह ऑफिस चलाते हैं माफिया :–** बॉर्डर क्षेत्र के चक्करमारी, जलेबियमोर चौक, पानीटँकी, नक्सलबाड़ी सहित दर्जनो ऐसे अड्डे इन माफियाओ ने बना रखें है। जहां आसानी से गुर्गे और ट्रको के चालक एकत्र होते है। पुलिस के हड़कम्प में आने से माफियाओं के भीतर सेंटीग्रेड में तनाव बढ़ता जा रहा है।

★ **पहुँच का धौंस दिखाकर पास करते हैं ट्रक :–** कई करोबारी अपने धंधे को चमकाने और अपना वर्चस्व इस धंधे में आगे रखने को लेकर कई रसूखदार का नाम का भी इस्तेमाल करते है। जबकि, स्वयं मालामाल होने के चक्कर उक्त व्यक्ति पत्रकार, अधिकारी, पुलिस, जनप्रतिनिधियों तक को एक दूसरे से उलझाकर और एक दूसरे के खिलाफ कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। जिससे आपस के तनाव में इंट्री माफिया आसानी से लाभान्वित होते हैं। ●

शिक्षा ही बिहार को विकसित करेगा- पाण्डेय

बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य केदार पाण्डेय का साक्षात्कार करते पत्रिका प्रतिनिधि पियूष कुमार दुबे

★ आप शिक्षा के क्षेत्र में कब से है और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?

मैं 1965 से ही जब शिक्षक नियुक्त हुआ बिहार में मैं उसी समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। इसकी पृष्ठभूमि मेरे गुरूदेव आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी जी वो देश के जाने-माने शिक्षाविद् थे उस समय और शिक्षा शास्त्र पर उन्होंने कई किताबें लिखी थी। वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में प्राध्यापक भी रहे थे। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को भी पढ़ाया था और हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पुस्तक ''क्या भूलू क्या याद करूं मैं'' आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी जी की चर्चा की है तो मैं आचार्य जी को देखकर उनके पढ़ाने, बोलने और ब्यान देने की कला से काफी प्रभावित हुआ और मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिली। जब मैं बिहार में आया और शिक्षक संग से जुड़ा तो उस समय शिक्षकों के क्षेत्रीय सम्मेलन, एक दो सम्मेलनों में मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे लगा यहीं, से शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षकों के जीवन स्तर के सुधार की योजनायें लागू हो सकती है तो मैं लगातार काम करता चला गया और 1970-71 के बीच में मैं शिक्षक शिक्षण कॉलेज अंशकालिक व्याख्याता हुआ और फिर 1973 में सिवान जिला बना, छपरा जिला से कटकर तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संग का सचिव चुना गया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संग उन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गोष्ठियाँ आयोजित करता था, पाठ्यक्रम पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। उस समय हमारे महासचिव श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह राजगीर के थे। मेरे कुछ लेख हमारे संग की मासिक पत्रिका प्रच्यस्पधा उसमें प्रकाशित हुए और मुझे शिक्षा गोष्ठियाँ के मंचों पे काम कराना और बोलना शुरू किया तो मेरी रूची धीरे-धीरे और गहरी हो गई। हम बिहार की राज्य कार्यकारिणी में आए फिर हमारी पत्रिका के संपादक बने, फिर महासचिव बने फिर बिहार विधान पार्षद में आए शिक्षकों के आंदोलनों में हिस्सा लिया, शिक्षा के सवालों पे लिखा कई किताबें मेरी छपी और मेरे जीवन का संकल्प कि मैं जबतक जीवित रहूँगा शिक्षा का आंदोलन बनाने के लिए मैं सतत संघर्ष करूँगा और शिक्षकों की दशा है, उसको सुधारने के लिए अंतिम सांस तक काम करता रहूँगा।

★ आज शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, क्या तमाम शिक्षाविद्ों का ध्यान में नहीं है?

उत्तर: शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि शिक्षा की नींव गलत है। वे शिक्षा किसी भी देश की अर्थनीति और राजनीति के पीछे-पीछे चलती है। इस देश में आजादी मिलने के बाद नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनायें बनायी। ढेर सारे विकास के काम किये पर शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिये और इसलिए उस समय शिक्षाविद् कृष्णमृत ने उनको आलोचना की थी।

1964 में देश में एक आयोग बना, कोठारी आयोग बनाया गया, डॉ. दौलत सिंह कोठारी यू.जी.सी. के चेयरमैन थे। उसकी अध्यक्षता में एक सर्वांग आयोग रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इन देशों के शिक्षाविद्ों को शामिल किया गया। एक सर्वांग आयोग के रिपोर्ट सामने आयी 1966 में। 1966 में सरकार को इसकी रिपोर्ट करायी गयी और 1968 में संसद में स्वीकृत की गयी। उसमें दो बातें प्रमुख थी। एक राष्ट्रीय बजट में इन जी.डी.पी. का 6% शिक्षा पर व्यय करना और दूसरा देश भर में सामान स्कूल प्रणाली की शिक्षा जोर-शेर से की जाए। इसका मतलब सरल शब्दों में है कि एक क्षेत्र भूगोल में एक विद्यालय को केन्द्र बनाया जाएं जिसमें हर वर्ग का बच्चे पढ़ें। जैसे कि कलक्टर और भंगी का बच्चे या उसके 'चपरासी का बेटा हो सब उसी विद्यालय में पढ़े। एक समान शिक्षा की व्यव्सथा होगी तो सरकार का ध्यान उसपर रहेगा। देश के प्रभू वर्ग ने इस प्रणाली को लागू होने नहीं दिया। इस लिए दो तरह की शिक्षा हो गयी। एक अमीरों के लिए है और दूसरे गरीबों के लिए है। अमीरों के लिए नीजी स्कूल और गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है। विडम्बना यह है कि सरकारी स्कूल और नीजी स्कूल भेदभाव किया जाता है और सरकारी स्कूलों को सरकार उतना सपोर्ट नहीं देती है, जितनी आवश्यकता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में प्रभू वर्ग (अमीर वर्ग) के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए सरकार का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन शिक्षाविद्ों के ध्यान देने से शिक्षा में अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता है। आजकल राजनीतिक दल भी शिक्षा में सुधार के लिए सवाल नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ जीतन राम माँझी और उपेन्द्र कुशवाहा इस सवाल को उठा रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग मुजकुन द्विवेदी (दूबे) की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किये और उसके लिए एक पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया गया था। लेकिन रूपये के अभाव में लागू नहीं किया जा सका या यू कहिए कि प्रभु वर्ग के दबाव के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। और यथास्थिति बरकरार रह गयी। शिक्षाविद्ो में एक वर्ग है जो पूँजीवाद का समर्थक है और यथास्थितिवाद का वो भी नहीं चाहता है कि शिक्षा की स्थिति में तब्दीली हो और आम जानता की शिक्षा की नींव बने। जैसी कानाडा, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ तक कि मॉरिशस में भी समान शिक्षा प्रणाली है। और दुनिया के ग्यारह देशों में है।

★ शिक्षा में राजनीति आये दिन होती रहती है और ये 100% (सत प्रतिशत) सत्य है, मगर राजनीति में शिक्षा कितना प्रतिशत है या है भी नहीं?

राजनीति में शिक्षा नहीं है पर शिक्षा में ही राजनीति है। शिक्षा में

राजनीति इस लिए है कि शीर्ष आसन पर जो बैठा है, राज्यों से लेकर केन्द्र तक वे नहीं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में तेजी से सुधार हो, क्योंकि ऐसा होने से देश में बुद्धिजीवी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनका राजनीति पर खतरा पड़ सकता है। लोकतंत्र को भीड़तंत्र में परिपाटी बन गयी है, क्योंकि आम आदमी शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाता है वो जात, धर्म, सम्प्रदाय की राजनीति को समझता है। और ये सारे सृजीत सवाल उसको उलझाये रखने में काम आता है। इसलिए शिक्षा के सवाल को हासिये पर रख दिया जाता है। उसको आगे नहीं निकलने दिया जाता है। जिन देशों में शिक्षा आगे है, जैसे वियतनाम या दूसरे समाजवादी देश जहाँ सामान्य शिक्षा प्रणाली है, हलांकि वहाँ भी पूँजीवाद है, फिर भी लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था आम जनता के लिए पूरी ईमानदारी से लागू किया है। कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि आई.आई.टी., आई.आई.एम., और कई विश्वविद्यालय खोल लिया पर कई पारम्परिक विश्वविद्यालयों में विभाग दर विभाग खाली है। पटना विश्वविद्यालय जिसको (ईस्ट का कैम्ब्रीज) कहा जाता है वहाँ भी शिक्षकों की संख्या कम है और विश्वविद्यालयों में लड़कों का नामांकन होता है, परीक्षा होती है पर पढ़ाई नहीं होती है। ये सारी चीजें अपने आप नहीं है, बल्कि बनायी गयी है। आम जनता ज्यादा बेचैन न हो इसलिए रोटी के टुकड़े के तरह फेंक दिया जाता है। जैसे 1966 में कोठारी आयोग की सिफारिश पर सेकण्ड पॉलिशी जो राजीव गाँधी बनाई थी। इसका लाभ वंचितों और पीछड़ों के मेधावी बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों की संकल्पना सामने आयी। उस समय नवोदय विद्यालयों पर 3.79 करोड़ रूपया खर्च होता था, जबकि सरकारी विद्यालयों पर 50 लाख रूपया खर्च होता था। आज भी नवोदय विद्यालयों में बच्चे ही ज्यादातर पढ़ते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में भी ऐसी उनकी शैली गठित की गयी है कि उसमें भी प्रभू वर्ग के बच्चे ही ज्यादातर पढ़ते हैं, जिसके लिए वो खुला वो लोग फिर से हासिए पर रह गये।

★ बिहार की पहचान पूरे देश में शिक्षा के वजह से है। और आये दिन इस छवि का हनन होता जा रहा है क्या ये बातें तमाम शिक्षाविदों के ध्यान में नहीं है?

है, नहीं थी नालंदा विश्वविद्यालय था, बिक्रमशीला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था।

★ इसके सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? और वो कार्य कहाँ तक पहुँचा है, क्या वो कार्य सफल हुए हैं?

सरकार ने कुछ काम जरूर किया है। बिल्कुल नकारात्मक नहीं है सरकार। खास कर 2006 के बाद एन.डी.ए. की सरकार आई है। माननीय नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। नालंदा विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबन्धन संस्थान, आई.आई.टी., राष्ट्रीय चाणक्य विधि विश्वविद्यालय या फिर और भी विश्वविद्यालयों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने ये सभी काम किया है, लेकिन जिस सामान्य शिक्षा की अवश्यकता बिहार में है, उसपे अभी कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन, हाँ 2006 के पहले जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे उसकी फिसदी 27% थी, लेकिन अब घटकर वह 1% हो गई है। ये बच्चे नामांकन जरूर ले लेते हैं, लेकिन क्लास, कोचिंग, ट्यूशन करते हैं। इसका मुख्य कारण विद्यालयों में संसाधनों की कमी है, जैसे-शौचालय, प्रयोगशाला, उपयुक्त अध्यापक की कमी है।

★ क्या कह सकते हैं इन्हीं वजहों से निजी शिक्षा हावी होती जा रही है, सरकारी शिक्षा पे? क्या सरकार इसपे कोई कदम नहीं उठा रही है?

सरकार चाहती हैं शिक्षा का निजीकरण बहुत तेजी से हो जाये क्योंकि सरकार पर जो जवाबदेही है, शिक्षा की वह जवाबदेही से वो मुक्त हो जाये बिल्कुल। पहले शिक्षा, संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। बाद में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संविधान में संशोधन अनुच्छेद 21 'क' के अनुसार अनिवार्य शिक्षा को लागु किया गया है, जिसमें सिर्फ 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा का जिक्र है। लेकिन 5 वर्ष से नीचे और 14-18 वर्ष के बच्चों का जिक्र संविधान के अनिवार्य शिक्षा में शामिल नहीं किया गया है और ना ही सरकार का इस पर कोई ध्यान है। जिसकी संख्या हमारे देश में 39-40 करोड़ बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आए दिन कहते हरते हैं कि बारहवीं तक की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। कम से कम बच्चियों को बारहवीं तक की शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे अपने विषय में भली-भांति समझ सके। क्योंकि उसके बाद से क्षेत्र बदल जाते हैं। कुछ बच्चे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, मेडिकल की ओर जाते हैं। बारहवीं तक की शिक्षा को Quantity Education कह सकते हैं। Quality education नहीं वो सरकार भी मानती है। 70-71 साल के बाद भी देश का 3.6% जी. डी.पी. का दे रहा है शिक्षा के ऊपर जो कि 6% देना था और राज्य सरकार उसका भी बस 16%-17% ही खर्च कर पा रही शिक्षा पर। जबकि दूसरे राज्यों में ज्यादा खर्च हो रहा है। और उस बजट में भी शिक्षा से ज्यादा योजनाओं में ज्यादा खर्च किया जा रहा है। जैसे साईकिल, पोशाहार, छात्रवृति पर। सरकार समझती है जिसका हम साईकिल देगें वो वोट देगा। लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाने की कोई योजना मैं नहीं देखता अभी तक की Quality Education के लिए सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम उठा रही हो जिसकी तारीफ की जा सके।

★ बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम गुणवतापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी हम भवन निर्माण कार्यों में व्यस्त है तो क्या तमाम शिक्षाविद् इसपर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं? और क्या तब तक उन सारे बच्चों को इसे इंतजार करना पड़ेगा?

उनसे पूछा जाना चाहिए कि वह कब तक भवन निर्माण करेंगे और कब गुणवता पूर्ण शिक्षा के लिए काम करेंगे। और क्या वह मान कर चल रहे हैं कि अगले 25 वर्षों तक सरकार उनकी ही रहेगी और क्या वहीं शिक्षा मंत्री रहेंगे और क्या तब तक हमलोग इंतजार करेंगे। दूसरी बात देश के जो शिक्षाविद् है असली शिक्षाविद् नकली नहीं वो लोग शिक्षा में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। Right Form और Right to Education नाम कि जो संस्था है, वो लगातार काम कर रही है। इसका काम बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा और सामान्य शिक्षा प्रणाली है। दूसरी एक और संस्था है, दिल्ली की श्री अमरीश राय जी और मुचकुन दुबे जी की वो भी लगातार काम कर रहे हैं तो देश के शिक्षाविद् बैठे नहीं है। शिक्षा में सुधार राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि पैसा उसी के पास है हरवा हथियार उसी के पास है काम करना उसी को है, तो वो जब तक काम नहीं करेंगे या राजनीतिक दल जब तक इसको आन्दोलन नहीं बनेंगे तब तक ये बात उतनी तेजी से हमलोग अपेक्षा करते हैं। उतनी तेजी से नहीं बना। इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं इस राज्य और देश के शिक्षा को ये लोग बहुत महत्व नहीं देते हैं। छिट-पुट ढंग से बातें करते हैं, लेकिन चुनावों में शिक्षा एजेन्डा नहीं बन पाता है जो एक प्रमुख कारण भी हे। अगर शिक्षा को चुनावों के एजेन्डा में शामिल किया जाय तब जाकर बदलाव होगा। हमारी एक किताब है, शिक्षा को आन्दोलन बनाना होगा, और जब तक शिक्षा आन्दोलन नहीं बनेगी तब तक हमलोग जिस प्रकार की परिकल्पना करते हैं वैसी शिक्षा बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। वैसे तो पारम्परिक, कुछ न कुछ चलता ही रहेगा जो भी सरकार आए।

★ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का कहना है और जितने भी सरकारी शिक्षा कर्मी तरह-तरह के आये दिन प्रयास कर रहे है बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ लुभावने योजनाये भी देते हैं, जैसे साइकिल, किताब, छात्रवृति, खिचड़ी इत्यादि। तो क्या ये तमाम योजनाएं बच्चों तक पहुँचाई जाती है?

उत्तर: बच्चों तक पहुँचती तो है, ही लेकिन ये चीजें शिक्षा के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन मूल रूप से शिक्षा में बदलाव का कारण नहीं हो सकती है। वैसे अगर गरीब बच्चे खिचड़ी खाकर घर चले जाते हैं या खिचड़ी के बारे में लुट होती है तो नीचे से ऊपर तक बंटवारा होता है। बच्चे तो प्रलोभन

से स्कूल में आ ही जाते हैं, लेकिन शिक्षक पढ़ाने वाले कहा है। अभी 3 लाख 75 हजार ही शिक्षक है, जिसमें 70 से 50 हजार पुराने शिक्षक ही है। अभी कम से कम 2 लाख शिक्षकों की जरूरत है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार इंतजार कर रही है। तो सरकार की नीति का सारा बजट या ज्यादातर बजट इन योजनायों में ही खर्च हो रहा है। आपकी तो सोच ही गलत है कि शिक्षक पैदा ही होता है। Quality Education देने के लिए। बेहतर शिक्षक उपयुक्त कराने के लिए क्या कोई टिचर ट्रेनिंग संस्था है, जैसे कि दरोगा की ट्रेनिग के लिए है। चीन अपने बेहतर शिक्षकों को उपयुक्त करने के लिए बड़ी-बड़ी कार्यशाला आयोजित करता है, देश-विदेश से शिक्षाविद्ों को बुलाता है, और उन्हें प्रशिक्षण देता है। सुविधायें प्रदान करता है, अच्छे शिक्षक स्कूलों में भेजता है। हमारे यहाँ शिक्षक नियुक्त करता है, जिला परिषद् या नगर परिषद् का अध्यक्ष जो राज्य या देश एक सही शिक्षक उपयुक्त नहीं कर पाता है और उसका प्रधान कहता है कि हम शिक्षा में सुधार के लिए जीजान से काम कर रहे हें तो मुझे समझ नहीं आता कि वो उपयुक्त है। लोकलाज के दृष्टि से करता है मैं तो उसके लिए ही आवाज उठा रहा हूँ, गुणवतापूर्ण शिक्षा सुलभ करने के लिए बेहतर शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों जैसी व्यवस्था हो। तो ऐसी व्यवस्था हो जहाँ शिक्षकों में और बच्चों का मन पढ़ने में लगा रहे। बायोमेट्री लगाने या अधिकारियों से जाँच करने से गुणवतापूर्ण शिक्षा नहीं होगी। शिक्षकों से 21 तौर शिक्षण काम ले रहे हैं, तो उनको पढ़ाने का समय कहाँ मिलता है। आप विद्यालयों में और कई यूनिवर्सिटी में नामांकन लेते है और परीक्षा लेते हैं तो आप पढ़ाते कब हैं। पढ़ाने के लिये तो कोई योजना नहीं है, आपके पास मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आधारभूत संरचनाओं को ठीक कर रहे हैं, और जब ये सब कुछ बन जायेगा तब जाके सब ठीक-ठाक होगा।

☆ किसी भी देश या राज्य की रीढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। तो क्या ये रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है या टूट ही गई है ये कह सकते हैं बिहार में और इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? दूसरे राज्यों का विकास का शिक्षा में बिहार से कई ज्यादा है तो क्या सरकार को उनसे प्रेरणा की जरूरत है?

मेरी समझ से सरकारों की प्राथमिकताएं होती है कि वो किस-किस सेक्टर में काम करेगें। बिहार की सरकार में या माननीय मुख्यमंत्री में पोटेनशियल है, लेकिन सरकार की प्राथमिकतायें है मैं जैसा देखता हूं सड़के है, बिजली है, पुल-पुलिया है, ये भी आवश्यक व्यवस्था में है, और इसमें सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन शिक्षा से समाज बदलता है। सामाजिक बदलावों का कारगर भी शिक्षा है। आम आदमी की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत जरूरी है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में इतनी संकल्प शक्ति नहीं है। सामान्य स्कूल शिक्षा प्रणाली की जाये और अस्पतालों को इस तरीके से बना दिया जाये कि आम आदमी का भी अच्छे से इलाज हो सके। केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान इस पर नहीं गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। जब प्राथमिकताओं में ये बातें नहीं होगी तो जनता आन्दोलन कर सकती है। या राजनीतिक दल अपने एजेंडा में ले लेते हैं या मेनीफेस्टों में शामिल करते हैं, तो एक जवाबदेही झलकती है। तो जैसे-तैसे हो रहा है। बिजली आज घर-घर पहुँच रही है, देहातों में भी तो शिक्षा में बदलाव नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर नीतिश कुमार, चाहे तो उनमें शक्ति है। हमलोग तो काम कर ही रहे हैं, शिक्षा संग, विधान परिषद् के मंच से या कई अन्य संस्थाओं के द्वारा। लेकिन वगैर सरकार के सहयोग से अपेक्षायें पूरी नहीं हो सकती।

☆ केवल सच पत्रिका के द्वारा आप माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तमाम शिक्षाविद्ो को, एवम् शिक्षकों को और स्टेडेन्ट्स को क्या संदेश या राय देना चाहेंगे कि बिहार में कैसे गुणवता पूर्ण शिक्षा की स्थापना हो सके?

मैं तो आगाह कर सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ऐसा मानता हूँ कि नीतिश कुमार जी सक्षम हैं और शिक्षा का प्रभार उन्हें खुद लेना चाहिए। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बंद करवाना चाहिए। निजी विद्यालयों में नियम और कानून बनाना चाहिए सकरारी विद्यालयों के समय में और निजी विद्यालयों में नियम और कानून बनाना चाहिए और लागू भी होना चाहिए? सरकारी विद्यालयों को बेहतर शिक्षकों के साथ उपयुक्त करना चाहिए। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नामांकन को लागू करवा दिया, इमतहान, कदाचार रहित लागू करवा दिया आनन्द किशोर जी ने तो ये भी चलाया जा सकता है। अगर सरकार चाह ले तो संभव है। केवल सच पत्रिका से आग्रह करूँगा कि राजनीतिक दलों के जमीर को भी जगाये वो लोग भी इस मुद्दा को उठाये कि सामान्य स्कूली शिक्षा गरीबों के बच्चों को मिलना चाहिए और सामान्य शिक्षा मिलेगी, जो भेद-भाव नहीं होगा और राज्य और देश का अपने आप ही आगे विकास होगा।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

मसौढ़ी थाना में पत्रकार के साथ हुआ अभद्र व्यवहार

● श्रीकांत श्रीवास्तव

खबर संकलन के दौरान मसौढ़ी के पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर मसौढ़ी अनुमंडल के सभी पत्रकार बन्धुओं में रोष व्याप्त है। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ कहलाने वाले मीडिया बन्धु के साथ दुर्व्यवहार की घटना वास्तव में शर्मसार करने वाली है। पत्रकार बन्धु देश और दुनिया को अपने खबरों से रूबरू करवाते हैं। ऐसे पत्रकारों को खबर संकलन करने पर रोक और पत्रकार के साथ पुलिसिया रवैया निछाजनक है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर सीधा प्रहार है। क्या बिहार में यही सुशासन है, जहाँ पत्रकारों को खबर संकलन की आजादी है, वहाँ पत्रकारों को खबर संकलन की आजादी नहीं है। कानून के रक्षक पुलिस ही भक्षक बने हुए हैं, ऐसे में हम बेहतर कानून व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मसौढ़ी अनुमंडल बीते कुछ दिन पहले मसौढ़ी थाना में खबर संकलन करने के दौरान दैनिक अखबार हिन्दुस्तान के पत्रकार मनोज पाण्डेय के साथ पुलिस के जवान के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। जिसको लेकर मसौढ़ी के कई सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं राजनीतिक दल के लोग पत्रकार मनोज पाण्डेय के साथ हुए इस दुर्व्यवहार का न्यायिक स्तर पर मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जब लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकार लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा। अपना परिचय देने के बाद भी पत्रकार को समाचार संकलन से रोका गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। अब यह जगजाहिर हो चुका है कि अगर पत्रकरों के साथ पुलिस अगर ऐसा व्यवहार करती है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। ऐसे पुलिस जवान को अधिकारियों द्वारा शीघ्र जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकारों के ऊपर अपनी वर्दी का धौंस दिया जाय पुलिस जवान ने अपने चेहरे को बेनकाव कर दिया है। पुलिस जवान ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज पाण्डेय (हिन्दुस्तान दैनिक अखबार) जी का हाथ पकड़कर थाना ले जाना चाहा। वही मौके पर अन्य पत्रकार के द्वारा तीव्र विरोधा करने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी अपनी मंसूबे को अंजाम देने में विफल रहा और पत्रकार मनोज पाण्डेय जी को छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हालांकि घटना की जानकारी थाने के अन्दर बैठे अन्य पुलिसकर्मी को दी गई एवं थानाध्यक्ष को भी मोबाइल से सूचना दिया गया, परन्तु उस पुलिसकर्मी को बुलाकर कार्रवाई करने की बात तो दूर उसे बुलाकर डांटा-डपटा भी नहीं गया। इस घटना को लेकर एवं पुलिस के रवैए को देखकर मसौढ़ी अनुमंडल के सभी पत्रकार आहत एवं आक्रोशित हैं। पत्रकार के साथ हुए इस अभद्रता को लेकर मसौढ़ी के कई सामाजिक एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं ने सामूहिक रूप से मिलकर पत्रकारों के साथ की गयी पुलिसिया रवैया के विरूद्ध मोर्चा निकाला था, जिसमें इन्होंने दोषी जवान और संरक्षण में जुटे पुलिसकर्मी को अविलंब निलंबन का मांग किया था। लेकिन जनांदोलन और ज्ञापन सौपने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन स्तर पर सहायता प्राप्त न होते देख मसौढ़ी अनुमंडल के सभी पत्रकार बन्धु दैनिक हिन्दुस्तान मसौढ़ी से मनोज पाण्डेय, राष्ट्रीय सहारा से पंकज सिंह, दैनिक जागरण से नागेन्द्र नाथ शर्मा, दैनिक भास्कर से अरविन्द कुमार, सहारा समय से अरूण कुमार, प्रभात खबर से बबलू, धनरूआ दैनिक हिन्दुस्तान से सोनू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शशि तुलष्यान्न, सुजीत कुमार, मीडिया दर्शन से नीजर कुमार ने पटना एस.एस.पी. गरीमा मलिक से मिलकर दोषी पुलिसकर्मी के विरूद्ध ज्ञापन दिया और इस घटनाक्रम में लिप्त सभी पुलिसकर्मियों पर तुरन्त कार्रवाई की मांग की है। जिससे भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी ऐसे अभद्र व्यवहार का दुःसाहस न कर सके। यह हमारे स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। ●

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। बेरोजगारी के अभिशाप को मिटायें। देश के सभी प्रदेश की राजधानी और देश के सभी प्रदेश के शहरों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें।

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308